₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

मार्च 2026

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PS.-35

निशांत के राजनीतिक अध्याय का प्रारंभ...

बिहार की राजनीति में विरासत बचाने की जंग

सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में रोजगार का सुनहरा अवसर

केवल सच सामाजिक संस्थान और **श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट** अपने भविष्य के आगामी योजनाओं में सामाजिक एवं बौद्धिक सुधार के क्षेत्र में पुर्नजागरण के शंखनाद हेतु बिहार और झारखण्ड राज्य के मेधावी/सक्षम/योग्य/दक्ष एवं कर्मठ नवयुवकों को अपने टीम में वैतनिक/अवैतनिक रूप से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करना चाहती है। उक्त स्वयंसेवी संस्थान मुख्य रूप से 'अपना घर' (वृद्धाश्रम आवास योजना), परिवार परामर्श केन्द्र, शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम (मूल रूप से निर्धन/बेसहारा लड़कियों हेतु) और विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रीत करना चाहती है। इन कार्यक्रमों से जुड़कर नवयुवक सामाजिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। उक्त संगठन इसके लिए टीम वर्क के तहत कार्य करना चाहती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय समन्वयक के अधीन वार्ड/ पंचायत/ प्रखण्ड/ अनुमण्डल/जिला समन्वयकों की नियुक्ति भी करना चाहती है। इस संस्थान से जुड़कर इच्छुक नवयुवक उक्त पदों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

संस्थान

shruti कम्युनिकेशन ट्रस्ट

श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत संचालित

निबंधन संख्या : 22333/2008, आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2549-52 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1073

केवल सच सामाजिक संस्थान

भारतीय सोसायटी एक्ट 21, 1860 के तहत निबंधित

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

निबंधन संख्या : 1141 (2009-10), आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

www.shruticommunicationtrust.org

www.ks3.org.in

Regd. Office:- East Ashok Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar)

Jharkhand State Office:- **Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi**

Mob.- 9431073769

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

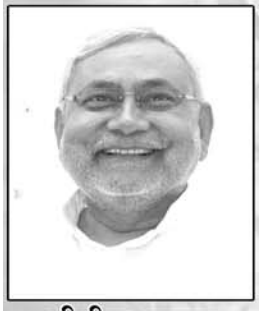

नीतीश कुमार
01 मार्च 1951

मेरी कॉम
01 मार्च 1983

शंकर महादेवन
03 मार्च 1967

शिवराज सिंह चौहान
05 मार्च 1959

अनुपम खेर
07 मार्च 1955

नवीन जिंदल
09 मार्च 1970

उमर अब्दुल्लाह
10 मार्च 1970

श्रेया घोषाल
12 मार्च 1984

वरूण गांधी
13 मार्च 1980

अमीर खान
14 मार्च 1965

हनी सिंह
15 मार्च 1984

राजपाल यादव
16 मार्च 1971

सानिया नेहवाल
17 मार्च 1990

रानी मुखर्जी
21 मार्च 1978

स्मृति जुबैद ईरानी
23 मार्च 1976

इमरान हाशमी
24 मार्च 1979

मधु
26 मार्च 1972

प्रकाश राज
26 मार्च 1965

शीला दीक्षित
31 मार्च 1938

मीरा कुमार
31 मार्च 1945

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880 09339740757

Advertisement Rates Per Issue

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

भरोसा

कल-आज और कल

हर - हर मोदी, घर - घर मोदी यानि नरेन्द्र दामोदर दास मोदी (भारत के प्रधानमंत्री) जिसके मन की बात को काम की बात मानकर लोग एकत्रित हो जाते थे और उनपर भरोसा इस कदर हावि था कि एक घोषणा के बाद लोग 05 दीपक जलाना, थाली बजाना, लाईट ऑफ करना, नोट बदलने के लिए लाईन में लगना वगैरह-वगैरह। मोदी ने भारत में सनातन (हिन्दू धर्म) को धारदार बनाने और बंटने-कटने से बचाने वाले अचानक अपने सलाहकारों के एक के बाद कानून से अपनी साख पर प्रश्न लगा रहे हैं की चर्चा हर एक मोबाइल पर चल रही है। राघव चड्डा ने सदन के भीतर जनहित के मुद्दे को पूरी गंभीरता से उठाकर मोदी की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मोदी जितना भरोसा कायम करना आसान नहीं है। केन्द्र की मोदी सरकार ने भारत की जनता को कई मामलो में जागरूक किया और हिन्दूओं को संगठित करके उनकी पुरानी समस्या का निदान किया एवं स्वाभिमान को भी जिवंत किया है। एक भारत - श्रेष्ठ भारत में आरक्षण एवं यूजीसी कानून ने आपसी भेदभाव को जन्म दिया है जिसकी वजह से भरोसा शब्द की राजनीति हो रही है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आज वर्त्तमान समय में जातिवाद का खेल राजनीतिक दृष्टिकोण से सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है और कुर्सी पर कब्जा कायम रखने के लिए भरोसा के साथ खेला जा रहा है।

— — — — — — —

ब्रजेश मिश्र, संपादक
8340360961, 9431073769

राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता इसलिए पक्ष एवं विपक्ष कई मुद्दे पर मौन होते हैं ताकि कब किसकी जरूरत पड़ जाये और उसके साथ होने से उसे सफलता मिल जाये। डच, पुर्तगाल, मुगल और ब्रिटिश हुकुमत से मुक्ति पाने के बाद 1947 में देश को आजादी मिली और भारत की जनता ने कांग्रेस पर आंख मूंदकर भरोसा किया लेकिन सत्ता के सिंहासन पर बने रहने के लिए धर्म एवं जाति की राजनीति को जन्म देकर सत्ता पर विराजमान रही। 1980 में कांग्रेस को राजनीति में पछड़ाने के लिए अटल बिहारी बाजपेयी + लाल कृष्ण आडवाणी + मुरली मनोहर जोशी की टीम ने अपने अन्य लोगों के साथ मिलकर देश की जनता का भरोसा अयोध्या-मथुरा-काशी+ अन्य मुद्दे पर अपने पक्ष में कर लिया और 2014-2029 तक देश का भरोसा गठबंधन के नाम पर अपनी ओर कर लिया है। कांग्रेस के शासन काल में किये गये कार्य की सराहना कोई नहीं करना चाहता जबकि भोजन+रोजगार+शिक्षा+सूचना एवं अन्य कई जनहित के कानून को बनाया पर जनता के बीच उसका श्रेय लेने में असफल हो गया है। 1990 में बिहार की जनता ने लालू यादव पर भरोसा किया और 15 साल शासन करने दिया लेकिन वक्त ने करवट ली और लालू की सरकार की नाकामी पर प्रश्न उठाते हुए 2005 में नीतीश कुमार पर भरोसा किया और 2025-2030 तक शासन करने का अवसर दिया। राजनीति में मुद्दे जन-बुनियादी समस्याओं की जगह पर जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, आरक्षण, एससी/एसटी सहित यूजीसी 2026 कानून की राजनीति करने वाले राजनेता पर जनता कैसे भरोसा करे। यूजीसी के मुद्दे ने भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह की कूटनीति ने सवर्ण को भाजपा एवं इन चंद नेताओं की राजनीति पर भरोसा उठ गया है। भाजपा एवं खासकर मोदी पर सवर्ण आंख मूंदकर भरोसा करते हैं तो पिछड़ा+अतिपिछड़ा+एससी/एसटी+मुस्लिम भरोसा नहीं करते ऐसे में सरकार की सभी जांच एजेंसी और देश की न्यायालय व्यवस्था पर से भी भरोसा उठने लगा है। जब कोर्ट के निर्णय पर भी राजनेता एवं उनके कार्यकर्त्ता और उनके समर्थक उंगली उठाने लगे तो लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में है कहना गलत नहीं होगा। पूरे विश्व में राजनीति और नेताओं पर से लोगों का भरोसा ऐतिहासिक रूप से उठता जा रहा है और यह काफी चिंताजनक विषय है। यही प्रमुख कारण है कि आम आदमी सरकार एवं राजनीतिक दल को स्वार्थी मानते हैं जिसकी वजह से निराशा एवं संशय बढ़ता है। आज के वर्त्तमान दौर में राजनीति में विश्वास कायम रखने के लिए ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ जनता के प्रति जवाबदेही अति आवश्यक है। आज चुनाव के वक्त चुनाव आयोग के पास नामांकन के वक्त घोषणा कुछ और किया जाता है और विजय प्राप्त करते हीं घोषणा के विपरित कार्य को संपादित किया जा रहा है और सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी निचता के हद तक गिर कर दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। किसी के चरित्र पर भी प्रहार करने से बाज नहीं आते, वैसे में भरोसा शब्द कल की बात हो गयी है जैसा लगने लगता है। वैसे तो देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनेताओं एवं राजनीतिक दलों की भरोसा अलग-अलग विषयों पर है लेकिन 2014 में जब केन्द्र में भाजपा ने मोदी को प्रधानमंत्री का पद सौंपा तो लोकतंत्र के बीच राजनेताओं की गिरती साख को एक बार मजबूती मिली और लोग नेताओं पर भरोसा करने लगे। श्रीराम मंदिर, धारा-370, मथुरा-काशी सहित एनआरसी के साथ कई ऐसे हालत (सर्जिकल स्ट्राइक एवं कोरोना) हुए जहां पीएम मोदी पर लोगों ने आंख बंद करके भरोसा किया और नोटबंदी के साथ सभी गंभीर मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के तमाम लोक-लुभावन वादे को भी ठोकर मारकर चुना लेकिन भरोसे की साख तास के पत्ते की तरह यूजीसी 2026 के कारण ढ़ह चुकी है और कल कितना भरोसा करेगी चिंता का विषय बनता जा रहा है। किसी खास वर्ग के लिए विभिन्न प्रकार के कानून तो फिर सबका साथ-सबका विकास कैसे? क्या सवर्ण होना गुनाह है? क्या किसी के कहने मात्र से कोई अपराधी साबित हो जाता है? क्या 1947 से मिल रहे आरक्षण से किसी का भला नहीं हुआ? अल्पसंख्यक, आदिवासी एवं दलित वर्ग के लोग राष्ट्र के प्रधान पद पर विराजमान हुए फिर भी आरक्षण का लाभ पर लाभुक चुप क्यों हैं? देश का सबसे बड़े संगठन के प्रधान मोहन भागवत के विवादास्पद बयान क्या भाजपा को जनता के बीच भरोसे लायक छोड़ी है? क्या सिर्फ मोदी एवं मोहन ही सच बोलते हैं? राजनीति में भरोसा टूटने की वजह से ही विश्व तृतीय विश्वयुद्ध के चपेट में है। किसी मंच से सही बोलने पर भी जनता को ऐसा लगता है कि कहीं जुमला तो नहीं होगा? एक तरफ राष्ट्रवाद की बातें और दूसरी तरफ पहले धार्मिक अब जातिय भेदभाव से भरोसा कायम रह सकता है? पीएम मोदी की यूजीसी 2026 पर चुप्पी उनके अब तक के राजनैतिक यात्रा पर ग्रहण लगा सकता है। लगभग 50 लोगों का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जीतना और किसी का चुनाव हारने का मामला भी भरोसे का कत्ल साबित हो सकता है। अब भरोसा के लिए सिर्फ कानून पर निर्भर रहना होगा, यह जानते हुए की उसपर पर भी उंगली उठ सकती है।

फरवरी 2026

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

हमारा ई-मेल

हुंकार

ब्रजेश जी,

फरवरी 2026 अंक में पत्रकार अमित कुमार की खबर ''सवर्णों की हुंकार, कांप उठी मोदी सरकार'' में यूजीसी के नये कानून पर जनहित में हो रही समस्याओं पर लिखी गई है जो काबिले तारिफ है। पूरी खबर पढ़ने पर ऐसा लगता है की इस कानून के मद्देनजर पीएम मोदी को भी अंधेरे में रखा गया है। सवर्ण राजनेताओं की करतूत भी उनके अपने बिरादरी के सामने आ चुकी है की बात को भी प्राथमिकता के साथ लिखा गया है। ऐसी धारदार खबरों को पत्रिका के सभी अंकों में स्थान देना चाहिए।

✦ **आशीष पाठक, भोपाल,मध्यप्रदेश**

बेटियो की बोली

ब्रजेश जी,

वरिष्ठ पत्रकार निशिकांत ठाकुर ने फरवरी 2026 अंक में अपनी खबर ''बेटियों की 'बोली' लगाते नेता और मूकदर्शक समाज'' में आज की सामाजिक एवं राजनैतिक दुर्दशा के साथ प्रशासन की नाकामी पर सटीक प्रहार है। जिस प्रकार बिहार में बेटियों के उपर जुल्म हो रहे हैं और सरकार के साथ प्रशासन भी कहीं न कहीं गुमराह होकर मामले को देखती है। बिहार राज्य महिला आयोग के सामने बड़ी चुनौती है की पिछले महीने हुए कई घटनाएं बेटियों के उपर हुए जुल्म की कहानी कह रही है।

✦ **रमेश दयाल, माटूंग, मुम्बई, महाराष्ट्र**

एक से एक यूपी

मिश्रा जी,

मैं आपकी पत्रिका का नियमित पाठक हूं और केवल सच, में छपी खबर पर पूर्ण भरोसा करता हूं। फरवरी 2026 अंक में वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार की खबर ''बीस साल बाद फिर मायावती का दलित-ब्राह्मण-मुस्लिम गठजोड़ फॉमूला'' सार्थक साबित हो सकता है। वहीं दूसरी खबर ''शंकराचार्य के बहाने हिन्दू धर्म पर चोट'' में संजीव कुमार झा ने वर्त्तमान समय की कूटनीति पर प्रहार करते हुए खबर को पाठकों के समक्ष रखा है जो पठनीय एवं चिंतनीय है। जबकि तिसरी खबर में संजय सक्सेना ने ''सपा-कांग्रेस को ओवैसी के कारण मुस्लिम वोट में बंटवारा'' खबर में सारी सच्चाई वोटरों के बीच रख दी है।

✦ **दिवाकर वर्मा, लखनऊ, उत्तरप्रदेश**

झारखंड की खबरें

मिश्रा जी,

केवल सच पत्रिका के फरवरी 2006 अंक में झारखड प्रदेश कर राजनीतिक एवं प्रशासनिक खबरों को पढ़कर अच्छा लगा कि पिछले एक वर्ष से झारखंड की खबरों को भी स्थान मिलने लगा है। गुड्डी साव, ओम प्रकाश और भारती मिश्र की खबरों को प्रिंट मीडिया एवं पोर्टल और यूटयूब पर भी देखने को मिल रहा है। झारखंड प्रदेश की खोजी खबरों को स्थान मिले और विभाग एवं मंत्रालय में चले रहे भ्रष्टाचार की खबरों को बिहार की तरह प्रकाशित किया जाये तो यह झारखंड प्रदेश के लिए भी उपयोगी साबित होगी। इस अंक की सभी खबरें पठनीय एवं जानकारीप्रद है। तीनों पत्रकारों को बधाई।

✦ **कैलाश्स भगत, पिस्का मोड़, राँची, झारखंड**

सी.बी.आई.

संपादक जी,

आपका संपादकीय वास्तव में समाज का दर्पण बनता जा रहा है। किसी भी विषय पर बिना किसी लाग-लपेट के वास्तविक विषयों को पूरी गंभीरता के साथ लिखना ही केवल सच की और आपकी पहचान है। फरवरी 2026 अंक में ''सीबीआई बनाम बिहार'' में आपने सीबीआई के जांच एवं उसके अनुसंधान पर उंगली उठाते हुए इस संगठन के जांच पद्धति पर सवाल खड़े करके निर्भिकता का परिचय देते हुए चुनौती दिया है। बिल्कुल यह सच है की अब सीबीआई की विश्वसनियता लोगों के बीच समाप्त होती जा रही है। सटीक व सार्थक संपादकीय।

✦ **सूरज मिश्र, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना**

शिक्षा का मंदिर

संपादक जी,

केवल सच पत्रिका की खबर का असर बड़े स्तर पर होता है। फरवरी 2026 अंक में शशि रंजन सिंह एवं राजीव कुमार शुक्ला ने अपनी खबर ''**शिक्षा का मंदिर या भ्रष्टाचार का अड्डा?**'' में राजभवन एवं शिक्षा विभाग और मगध विश्वविद्यालय के मिलीभगत से कुलपति डॉक्टर शाही पर लिखा गया आलेख बिल्कुल सत्य एवं तथ्य के साथ है। मैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की काली करतूत की सटीक जानकारी एवं दस्तावेज पत्रिका का उपलब्ध करा रहा हूं ताकि यहां का भी भ्रष्टाचार से लोग परिचित हो। निर्भीक पत्रकारिता को धन्यवाद।

✦ **लोकेश आनंद, आरा, भोजपुर**

अन्दर के पन्नों में

बाहा पर्व में सम्मानित हुए मुख्यमंत्री...83

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 20 | अंक:- 238 | माह:- मार्च 2026 | मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

श्रद्धेय गोपाल मिश्र

श्रद्धेय सुषमा मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका (एडमिन) 7782053204

सुरजीत तिवारी 9431222619

निलेन्दु कुमार झा 9431810505, 8210878854

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

डॉ० शशि कुमार 9507773579

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उप-संपादक

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 7979909054, 9334813587

राजनीतिक संपादक

सुमित रंजन पाण्डेय 7992210078

संतोष कुमार यादव 8210487516

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

कुमार अनिकेत 9431914317

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

चीफ क्राइम ब्यूरो

सैयद मो० अकील 9905101976, 8521711976

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०)	:-	श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०)	:-		
(ग्रा०)	:-	मुकेश कुमार	9473038020
बाढ़	:-		
भोजपुर	:-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर	:-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर	:-		
रोहतास	:-		
	:-		
गया (श०)	:-		
(ग्रा०)	:-		
औरंगाबाद	:-		
जहानाबाद	:-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल	:-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा	:-		
	:-		
नवादा	:-	अमित कुमार	9162664468
	:-		
मुंगेर	:-		
लखीसराय	:-		
शेखपुरा	:-		
बेगूसराय	:-		
	:-		
खगड़िया	:-		
समस्तीपुर	:-		
जमुई	:-	अजय कुमार	09430030594
वैशाली	:-		
	:-		
छपरा	:-		
सिवान	:-		
	:-		
गोपालगंज	:-		
	:-		
मुजफ्फरपुर	:-	.	
	:-		
सीतामढ़ी	:-		
शिवहर	:-		
बेतिया	:-	रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा	:-		
मोतिहारी	:-	संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा	:-		
	:-		
मधुबनी	:-		
	:-	प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा	:-		
मधेपुरा	:-		
सुपौल	:-		
किशनगंज	:-		
	:-		
अररिया	:-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया	:-		
कटिहार	:-		
भागलपुर,	:-		
(ग्रा०)	:-	रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया	:-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर,
नई दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 7903856569, 6203723995

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या.- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ **सभी पद अवैतनिक हैं।**

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- State Bank of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक

.....

.....

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

.....

झारखण्ड सहायक संपादक

अभिजीत दीप 7004274675, 9430192929
ब्रजेश मिश्र 7654122344, 7979769647
अनंत मोहन यादव 9546624444, 7909076894

उप संपादक

अजय कुमार 6203723995, 8409103023

.....

संयुक्त संपादक

.....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343, 8863893672

.....

.....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची :- अभिषेक मिश्र 7903856569
:- ओम प्रकाश 9708005900
साहेबगंज :-
खूँटी :-
जमशेदपुर :- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता 9304824724
हजारीबाग :-
जामताड़ा :-
दुमका :-
देवघर :-
धनबाद :-
बोकारो :-
रामगढ़ :-
चाईबासा :-
कोडरमा :-
गिरीडीह :-
चतरा :- धीरज कुमार 9939149331
लातेहार :-
गोड्डा :-
गुमला :-
पलामू :-
गढ़वा :-
पाकुड़ :-
सरायकेला :-
सिमडेगा :-
लोहरदगा :-

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी

'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सूमन सौरभ	9471492480, 7004952447
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
रजनीश कांत झा	9430962922, 7488204140

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670

झारखंड राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
राँची	गुड्डी साव	6299470142
हजारीबाग		
पलामू		
दुमका		
चाइईबासा		

2025

नीतीश कुमार फिनिश

ब्रजेश मिश्र

राजनीति में कोई अपना - पराया नहीं होता क्योंकि किसके गठजोड़ से कुर्सी मिल जाये यह कहां नहीं जा सकता है, इसलिए कट्टर दुश्मन से भी दोस्ती की गुंजाईश हो सकती है। 1947 में मिली आजादी के बाद से लेकर 1990 की कांग्रेस की सरकार को धक्का देकर सत्ता में आई लालू की सरकार कुछ ही वर्षो में लालू - राबड़ी की सरकार बनकर 2005 तक बिहार की शासन व्यवस्था को संभाले रखा लेकिन इनकी सरकार की करतूतों से मुक्ति के लिए एनडीए गठबंधन को महत्व देते हुए नीतीश कुमार को सत्ता पर ऐसे बैठाया की चुनाव परिणाम में कोई भी दल बड़ा हो लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी 2005 से लेकर 2026 में राज्यसभा जाने से पहले तक, नीतीश कुमार की जब तक इच्छा थी तब तक कायम रहे, जबकि इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी छिनने के लिए मोदी - शाह ने भी जुगाड़ लगाया तो लालू - राहुल ने भी परिश्रम किया लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। नीतीश कुमार की गद्दी भाजपा हासिल करने के लिए लगातार जुगाड़ लगा रही है और उसमें उसको कामयाबी मिलती भी दिख रही है पर एक समीक्षात्मक रिपोर्ट:-

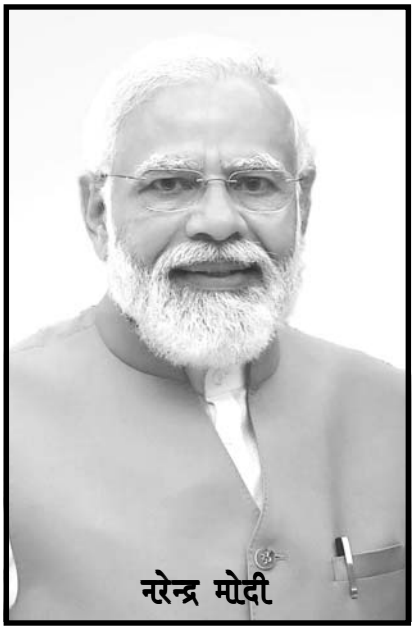
नरेन्द्र मोदी

नीतीश कुमार

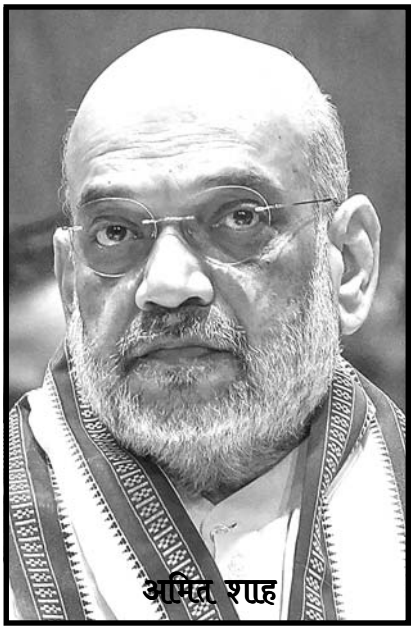
अमित शाह

बिहार में बहार है, फिर से नीतीशे कुमार हैं'' का स्लोगन को खुद नीतीश कुमार मिटाना चाहते हैं। लालू यादव के साथ राजनीति की शुरूआत करने वाले नीतीश कुमार को तब झटका लगा जब उनके रहते लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्समंत्री की कुर्सी सौंप दी और वहीं से सत्ता के सिंहासन को अपने कब्जे में लेने के लिए नीतीश कुमार ने समता पार्टी फिर जनता दल यूनाईटेड बनाकर बिहार की जनता का विश्वास जितने लगे और 2005 के नवंबर में लालू-राबड़ी की सरकार को उखाड़ फेंका और एनडीए की सरकार बनाकर मुख्समंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार काबिज हो गये। नीतीश कुमार की सरकार 2005 के फरवरी में

बनने से रामविलास पासवान ने रोक दिया और न तो एनडीए के साथ गये और न लालू राबड़ी सरकार बनने दिया। रामविलास पासवान राजनीति के ऐसे अवसरवादी नेता हुए कि जिसकी भी सरकार केन्द्र में रही वह उसके गठबंधन में शामिल होकर मंत्री बन जाते थे। बल्कि एक वोट से केन्द्र में अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार गिराने में भी इनकी भूमिका को लोग आज भी याद रखते हैं। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार में रहे और जब 2014 में मोदी की लहर को भांपते हुए फिर से एनडीए में शामिल होकर अपने पुत्र चिराग पासवान का भी भविष्य सुधार लिया। राजनीति के चाणक्य के बजाय राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में अपनी पहचान बनायी और अपने दोनों भाईयों को भी सांसद बनवाने में सफल रहे। नीतीश कुमार को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस, राजद, लोजपा, बसपा, सपा सहित कई अन्य राजनीतिक दल के प्रमुखों ने अपनी क्षमता लगाकर रोकना चाहा लेकिन लालू-राबड़ी सरकार के शासन काल में हुए कुछ काले कारनामे की वजह से जनता ने मन बना लिया था कि किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री (एनडीए) बनाना है और नवंबर 2005 के चुनाव के नतीजे ने जनता के विश्वास को साबित करने का मौका मिल गया और 2010 के विधानसभा चुनाव में बेहतरीन कार्य के लिए नीतीश कुमार को जनता ने इतना विधायक दिया की लालू-राबड़ी की पार्टी विपक्ष के लायक भी सीट नहीं जीत सकी। तेजस्वी यादव अपने ही परिवार के अंदरूनी राजनीति में बुरे फंस चुके हैं और उनका कोर टीम भी कभी भी राजद का लालटेन थामने से डरता है क्योंकि तेजस्वी के बीरबल राज्यसभा सांसद संजय यादव (हरियाणा) की वजह से बिहार के यादव भी खुद को ठगा महसूस करते हैं की चर्चा राजनीतिक गलियारे में सुर्खियों में है। चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने के लिए काफी मेहनत किया और मोदी के हनुमान बनकर कुमार की राजनीतिक औकात बताने में कामयाब भी रहे जबकि एनडीए में रहने के बाद भी मोदी ने चिराग को नहीं रोका अलबत्ता उसको अंदरूनी पावर देकर कुमार को फिनिशि करने की रणनीति को बल दिया जिसके परिणाम के रूप में जदयू 50 का भी आंकड़ा नहीं पार कर सकी। उपेन्द्र

कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने अपना पार्टी बनाकर मोदी के साथ मिलीभगत करके नीतीश कुमार का कद छोटा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, यह अलग बात है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के विकसित सोच एवं ईमानदार प्रयास का हमेशा साथ दिया।

2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नरेन्द्र दामोदर दास मोदी को खड़ा किया तो नीतीश कुमार भाजपा के बिहार के चर्चित नेता सुशील कुमार मोदी के साथ मिलकर राजनीतिक खेल (भोज रद्द) तो करना चाहा लेकिन आरएसएस ने स्पष्ट तौर पर मोदी को लेकर चुनावी मैदान में उतरे और 273 सीट पर विजय हासिल करते हुए प्रधानमंत्री के कुर्सी पर काबिज करा दिया जिसकी वजह से स्वाभिमान के रक्षा के नाम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का ताज सौंप कर मोदी को कैसे 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में परास्त किया जाये उसके अंकगणित के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के प्रचार के चाणक्य प्रशांत किशोर को 2015 के महागठबंधन के लिए चुना और बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 17 वर्ष पुराना गठबंधन से अलग हुए नीतीश कुमार ने भाजपा और मोदी पर कई तीखे वार किये और पलटवार में नीतीश कुमार की छवि को भाजपा ने भी धूमिल करने का प्रयास किया और दोनों के बीच का दरार इतना बढ़ गया और जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के बजाय मोदी को अपना नेता चुन लिया लेकिन प्रशांत किशोर ने 2015 में

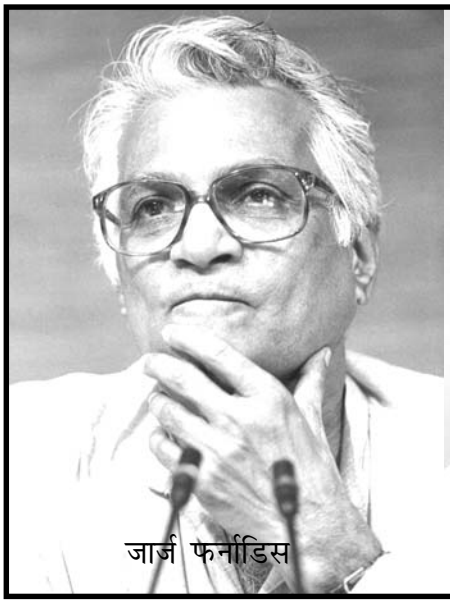
जार्ज फर्नांडिस

रामविलास पासवान

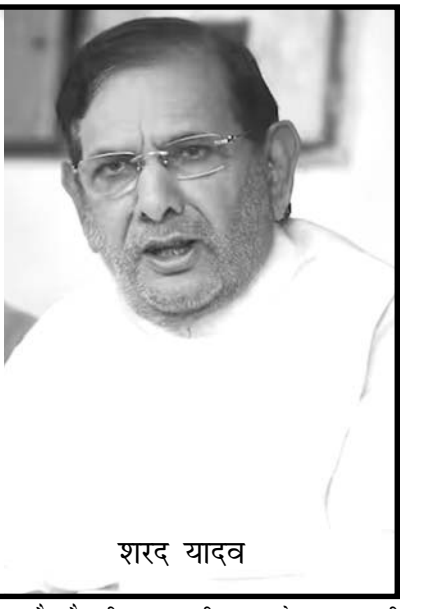
शरद यादव

''बिहार में बहार है, नीतीशे कुमार है'' का टैगलाईन से सरकार तो बनवा दी लेकिन सत्ता के सिंहासन पर कांटे न चुभे इसकी वजह से 2017 में ही फिर से एकबार नीतीश कुमार महागठबंध न से हटकर एनडीए में शामिल हो गये। प्रशांत किशोर अपनी कूटनीति की वजह से नीतीश कुमार के काफी करीबी हो गये लेकिन मोदी के साथ चले जाने की वजह से प्रशांत कहीं न कहीं ठगा हुआ महसूस करते थे। 2025 के चुनाव के पहले प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन सुराज बनाकर मैदान में तो उतरे लेकिन 0 (जीरो) पर आउट हो गये। 2015 मोदी के तमाम प्रयास के बावजूद बिहार में भाजपा सरकार बनाने में असफल हो गयी, उसी वक्त से मोदी ने यह ठान लिया कि बिहार में नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा एवं राजनीतिक कद को छोटा करना है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के साथ मिलकर ऐसा जाल बिछाया कि नीतीश कुमार 117 से घटकर 44 पर सिमट गये और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नीतीश कुमार ने खुद को एवं जदयू को फिनिश होता देख फिर से महागठबंधन के साथ चले गये लेकिन सुशासन और कुशासन के आरोप-प्रत्यारोप से बचने के लिए अब कभी नहीं भागूंगा की बात कहते हुए मोदी के शरण में आ गये। अदला-बदली से परेशान बिहार की राजनीति में 2013 के बाद से ही नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य कटघरे में आ गयी, भले ही वह सरकार के मुखिया बने रहे। अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता जार्ज फर्नांडीस एवं शरद यादव को भी हासिए पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसका आरोप भी श्री कुमार पर लगता रहा है। अपने मुंहबोले राजनीतिक भतीजे तेजस्वी यादव से मोह भंग हो गया और फिर प्यार आ गया वाली स्थिति की वजह से अपने बेटे निशांत को राजनीति में प्रवेश कैसे करायें की जुगत में लगे हुए हैं। राजनीति में परिवारवाद से अलग हटकर काम करने वाले नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव परिणाम आने के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही है की 2025 में नीतीश कुमार फिनिश वाली स्थिति बनती जा रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार के गठन में जब गृह मंत्रालय भाजपा के सम्राट चौधरी के पास चले जाने के बाद से ही यह साफ हो गया है कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से फिनिश करना है और 2026 के शुरूआत से ही इसका खेल शुरू हो गया है और नीट छात्रा की हत्या के बाद यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे की भूमिका भी संदिग्ध है और उसको बचाने के लिए वह अपनी ईच्छा अब केन्द्र की राजनीति में दिखा रहे हैं और राज्यसभा का चुनाव भी जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागने का मन बना चुके हैं। अब मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का? कौन-कौन दोनों डिप्टी सीएम जदयू के होंगे? कौन बनेगा बिहार विधानसभा का अध्यक्ष? चिराग पासवान एवं जीतन राम मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा की भूमिका क्या होगी? उपरोक्त सभी राजनेता बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार को बेदखल करने का कई बार असफल प्रयास कर चुके हैं लेकिन अब उनका

तेजस्वी यादव

सुशील कुमार मोदी

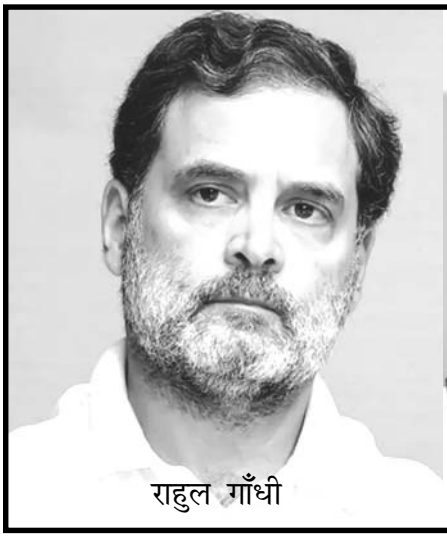
राहुल गाँधी

अखिलेश यादव

मायावती

प्रयास सफल होता दिख रहा है कि चाहे कारण कुछ भी हो बिहार की मुख्यमंत्री की गद्दी से वह हट जायेंगे और अब भाजपा के हांथ में यह कुर्सी आ सकती है। ''**2025 फिर से नीतीश**'' बिहार विधसनसभा चुनाव 2025 में यह नारा एनडीए का था लेकिन भाजपा ''**2025 नीतीश कुमार फिनिश**'' की राजनीति कर रही है। 2013 का भोज का बदला जुमला देने वाला कभी भी ले सकते हैं की सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता। गुजरात के मोदी को बिहार के मोदी से भी बदला लेना था जिसकी वजह से 2014 के बाद सुशील कुमार मोदी की राजनीतिक कद धीरे-धीरे धूमिल होती गई और उनको फ्रंट लाईन से हटा दिया गया। भाजपा में वहीं लोग प्रभावकारी हैं जो मोदी एवं शाह के इशारे पर चले और जिन्होंने अपना हुनर दिखाया, उनको उनकी जगह बता दी जाती है और कार्यकर्त्ता को युवाओं का विकास हो रहा है बताकर मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है। उप मुख्यमंत्री के रूप में सुशील कुमार मोदी की जोड़ी नीतीश कुमार के साथ सुपरहिट मानी जाती रही है लेकिन तेजस्वी के साथ भी श्री कुमार का संबंध बहुत बुरा नहीं रहा है।

कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गाँधी ने अपनी छवि बिहार में महागठबंधन के साथ मिलने की वजह से धूमिल कर ली है जबकि कांग्रेस लगातार अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरे तो वह सवर्ण+दलित+मुस्लिम गठजोड़ के दम पर फिर से अपनी हांथ को मजबूत कर सकती थी लेकिन इसी मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस ने राजद का दामन थामा और 2015 के चुनाव में कुछ करिश्मा भी दिखाया लेकिन यूपी में अखिलेश यादव के साथ हां और ना की राजनीति के कारण कुछ विशेष कर पाने में असफल हो चुकी है। दूसरी तरफ सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव की राजनीति बिहार में बिल्कुल ठप है और पहले भी मुलायम सिंह यादव के तमाम कोशिश के बाद भी सपा की सायकिल की सवारी कोई नहीं कर पाया और यूपी की बहन मायावती सभी बिहार विधानसभा चुनाव में सीट तो जीत जाती हैं लेकिन उनका विधायक किसी अन्य दल में शामिल होकर हांथी को पीछे छोड़ देता है। सपा और बसपा भी नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने के लिए कोई प्रयास नहीं छोड़ती पर विपक्ष की लाचारी एवं वोटरों का इनपर विश्वास नहीं होने की कारण हर बार नीतीश कुमार ही गद्दी पर कायम हो जाते हैं। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी और झारखंड के हेमंत सोरेन ने भी नीतीश कुमार की राजनीति के साथ चलना चाहा जिसकी वजह से मोदी के टारगेट पर दोनों रहे लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। कई राजनेताओं को 12 साल में जेल जाना पड़ा (मुख्यमंत्री तक जेल में लंबे समय तक रहे) और लोकतंत्र को कई बार खुद शर्मिंदा होना पड़ा। नीतीश कुमार को 2025 में ही सत्ता से बेदखल करने का खेल शुरू हो गया था लेकिन चुनाव के ठीक चंद दिन पहले 10 हजार महिलाओं की देने की योजना की वजह से फिर से एकबार नीतीश कुमार ने अपनी क्षमता का परिचय देते हुए सीएम की कुर्सी कब्जा करने में कामयाब हो गये लेकिन गृह विभाग छीन जाने की वजह से भाजपा की नीति ''**2025 नीतीश कुमार फिनिश**'' कामयाब हो गयी और 2026 में पूर्णरूपेण यह स्लोगल सच साबित हो जायेगा। कौन होगा नीतीश कुमार का विकल्प? यूजीसी 2026 की राजनीति के मामले में सवर्णों के बीच बुरी तरह से फंस चुकी मोदी-शाह के लिए मुख्यमंत्री को चुनने में मशक्कत करनी पड़ रही है लेकिन 2025, नीतीश फिनिश के गेम में वह सफल हो चुके हैं इससे इंकार नहीं किया जा सकता।●

ममता बनर्जी

हेमंत सोरेन

बिहार एक बार फिर राजनीतिक पटकथा लिख रहा है और इस पटकथा के मुख्य किरेदार लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इंजीनियर पुत्र निशांत कुमार हैं। 2022 के बाद से ही नीतीश कुमार की हरकतें उनके स्वास्थ्य संतुलन पर प्रश्न चिन्ह् लगाती आयी है, ऐसे में बिहार का नेतृत्व आगे कौन करेगा का मंथन जारी था। पहले निशांत का नीतीश से दूरियां और बाद की नजदीकियों ने निशांत को जदयू का उतराधिकारी मान लिया था, बस मुहर लगनी बाकी थी। वर्षों से निशांत को राजनीति में आने की गुहार पर नीतीश कुमार ने हामी भरी और स्वयं बिहार से दिल्ली की ओर रूख करने (राज्यसभा जाने) की मंशा बनाई। नीतीश कुमार भले ही दिमागी रूप से अस्वस्थ चल रहे हो किन्तु राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश ने अपने बेटे निशांत को जदयू संभालने की पूरी जिम्मेदारी दे डाली, यानि जदयू और बिहार की विरासत निशांत को मिल गई है। राजनीति में नौसीखिए निशांत के लिए लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि बीते कई वर्षों का राजनीतिक अनुभव तेजस्वी के पास है किन्तु इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि निशांत, नीतीश के बेटे हैं और उन्हें इनका लाभ जरूर मिलेगा। जदयू के वरिष्ठ नेता, निशांत को राजनीतिक पाठ का ज्ञान देने में जुट गये हैं और निशांत भी राजनीतिक दिलचस्पी लेते हुए बखूबी इस पर अमल भी करते दिखने लगे है। बहरहाल, निशांत-तेजस्वी को विरासत के इस जंग का फैसला 2029 के लोकसभा और 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा। निशांत की राजनीतिक एंट्री से तेजस्वी को नुकसान होगा या नहीं ये तो वक्त बतायेगा किन्तु दोनो के लिए विरासत बचाने की यह जंग है जो बिहार की राजनीति के बड़े धुरी लालू-नीतीश के बेटे हैं। निशांत-तेजस्वी के विरासत बचाने की जंग पर प्रस्तुत है संयुक्त संपादक **अमित कुमार** की राजनीतिक रिपोर्ट :-

'मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने की कोशिश करूंगा। मेरे पिता ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है और मैं उसका सम्मान करता हूं। जनता और पार्टी ने जो मुझपर विश्वास किया है मैं उसपर खरा उतरने की कोशिश करुंगा। पापा ने जो बीस साल में बिहार के लिए जो किया, उसें मैं जन-जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरा पिताजी ने जो किया है वो सभी को याद रहेगा।' ये बातें निशांत ने अपने राजनीतिक प्रवेश के दौरान कही, जब पिता नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया और निशांत को बिहार का बागडोर संभालने की जिम्मेदारी दी जा रही थी। निशांत जेडीयू के पार्टी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं तथा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा के साथ प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के सानिध्य में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। निशांत कुमार ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने की कोशिश करूंगा। मेरे पिता ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है और मैं उसका सम्मान करता हूं। जनता और पार्टी ने जो मुझपर विश्वास किया है मैं उसपर खरा उतरने की कोशिश

करुंगा। निशांत ने पार्टी कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे पापा पर आपलोग अपना विश्वास कायम रखिएगा। मैं पार्टी को और मजबूती प्रदान करने की कोशिश करूंगा। मैं लोगों के ह्रदय में जगह बनाने का प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में काम करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने की कोशिश करूंगा। निशांत कुमार ने कहा कि मेरे पापा ने जो कुछ किया है उसपर पूरे देश और बिहार को गर्व है। राजनीतिक पंडितों की मानें, तो निशांत कुमार का ये कहना कि मेरे पापा के ऊपर विश्वास बनाए रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। निशांत कुमार राजनीति में अपनी हैसियत को समझते हैं। उन्हें मालूम है कि उनके पास जो भी विरासत है, उनके पिता की दी हुई है। उनके पिता का एक्टिव रहना उनके स्थापित होने तक जरूरी है। निशांत कुमार ने लोगों से भावुक अपील की। उन्होंने ये बता दिया कि नीतीश कुमार के गाइडलाइन्स पर ही वे चलेंगे। उसके साथ ही उन्होंने जेडीयू नेताओं को संदेश दे दिया कि जो व्यक्ति नीतीश कुमार के करीब है, वहीं उनके करीब होगा।

बहरहाल, अब बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। कुछ हफ्तों पहले तक निशांत प्रदेश के राजनीतिक मंच से पूरी तरह से दूर थे। पूरा रंगमंच उनके पिता नीतीश कुमार ने ही संभाला हुआ था। होली पर अचानक से बड़ा बदलाव आया और पता चला कि नीतीश राज्यसभा जाने का मन बना रहे हैं। नीतीश राज्यसभा सदस्य चुन भी लिए गए और निशांत ने औपचारिक तौर पर जदयू की सदस्यता भी ले ली और पिता के नक्शेकदम पर चलने को तैयार हो गए। बिहार की नई संभावित सरकार को लेकर चर्चा चली कि निशांत को फिलहाल उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ताकि कुर्सी के नजदीक रहें और सत्ता की बागडोर संभालने की ट्रेनिंग लें। पिछले कुछ समय से सबकुछ इसी स्क्रिप्ट पर चल रहा था। लेकिन अब अचानक से कहानी में नया ट्विस्ट आता दिख रहा है। निशांत कुमार को अचानक से मुख्यमंत्री बनाने के सुर जोर पकड़ने लगे हैं। मतलब बिहार की सत्ता किसी फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह हो सकता है! करीब 2 महीने पहले जदयू ऑफिस के बाहर ***'चाचा जी के सपनों का निशान है ये तीर.., भाई निशांत जी हैं तीर का अगला तकदीर।'*** पोस्टर लगा तो शायद बहुत ही कम लोगों ने इसे गंभीरता से लिया था, लेकिन तारीख बढ़ती गई और पोस्टर पर लिखी लाइनें अपना मजबूत आधार ढूंढती रहीं। वही नीतीश के दिल्ली प्रवास (राज्यसभा) के बाद बिहार के सियासत में सीएम की कुर्सी के उतराधिकारी बनने की चाह रखने वालों की नींद जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के बयान ने उड़ा दी। उन्होंने निशांत को लेकर कहा है कि वह सभी पद डिजर्व करते हैं। उन्हें जो भी पद मिलेगा, वो उसे संभाल लेंगे। उन्होंने कहा कि वह सीएम या डिप्टी सीएम जो भी पद मिलेगा, उसे संभाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो पढ़े-लिखे हैं, काबिलियत है उनमें। सीएम का पद भी अच्छी तरह संभाल सकते हैं। शीर्ष नेतृत्व जो उन्हें जिम्मेदारी देगा, वो उसे संभाल लेंगे। इसके साथ ही हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आए बाहुबली व मोकामा से विधायक

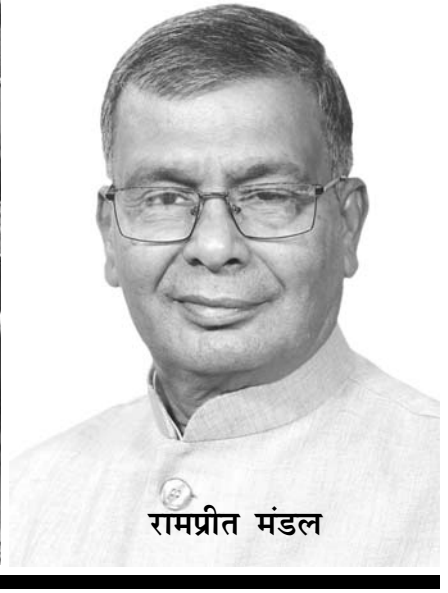

रामप्रीत मंडल

अनंत सिंह ने कहा कि निशांत में वो सारे गुण हैं, जो उनके पिता नीतीश कुमार में हैं। निशांत के पास काम करने की कला है। इसके अलावा नालंदा में समृद्धि यात्रा थी। इस दौरान नीतीश के सामने मंच से ही निशांत को कमान देने की मांग उठने लगी। रैली में 'जय निशांत तय निशांत' के नारे लगने शुरू हो गए।

गौरतलब है कि बिहार की राजनीति में अक्सर 'परिवारवाद' के जरिए नेताओं के बेटों को सत्ता के शिखर पर बैठाने की परंपरा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत इस बार एक अलग राह पर चलते दिख रहे हैं। निशांत केवल नाम के सहारे राजनीति में आने के बजाय जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक संदेह बना हुआ था कि आध्यात्म की दुनिया में रमे हुए निशांत का व्यक्तित्व पर राजनीति का रंग चढ़ पाएगा। हालांकि एक पुरानी कहावत है, *'बापे पूत परापत घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़म थोड़ा।'* ऐसे में निशांत तो राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार के पुत्र हैं। उनके कुछ गुण तो होंगे ही होंगे। बता दें कि इन दिनों निशांत कुमार खुद को साबित करने में लगे हुए हैं। निशांत कुमार ने सामाजिक और राजनीतिक भूमिका निभानी शुरू कर दी है। ज्ञात हो कि साम्यवाद से समाजवादी राजनीति की ओर बढ़े नेता सतीश कुमार की शव यात्रा में शामिल होकर निशांत कुमार ने न केवल पिता नीतीश कुमार की जिम्मेदारी निभाई बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ सतीश कुमार के प्रति अपनी श्रद्धा भी दिखाई। निशांत ने सतीश कुमार का अंतिम दर्शन किया और साथ ही परिजनों से मिलकर उनको ढांढस भी बंधाया। सतीश कुमार और नीतीश कुमार दोनों ही एक दौर में बेहद करीबी रहे थे। दोनों के बीच सियासी तौर पर काफी नजदीकियां रही थी। लालू यादव के सत्ता के खिलाफ बिगुल फूंकने में दोनों साथ-साथ थे। ऐसे में नीतीश कुमार के परिवार से सतीश कुमार की नजदीकियां रही है।

खैर, बात निशांत की है और निशांत का राजनीति के प्रति रुचि का प्रदर्शन तो उसी दिन हो गया, जब जनता दल (यू) की सदस्यता ग्रहण करने के पहले जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर युवा विधायकों के साथ निशांत कुमार ने विचारों का आदान-प्रदान किया। तब एक सवाल भी उठा था कि निशांत कुमार अभी किस हैसियत से दो दर्जन युवा विधायकों की बैठक ली। बहरहाल, उस बैठक से जो बाते छनकर कर आई, वो ये कि बिहार के संदर्भ में बातचीत हुई। ताकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। उधर, आनन-फानन में जेडीयू विधायक रुहेल रंजन के घर पर 14 युवा विधायकों ने एकमत होकर निशांत कुमार को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की। मीटिंग में शामिल विधायकों ने खुद को टीम निशांत बताते हुए कहा कि वे भविष्य में निशांत कुमार की लीडरशिप में काम करना चाहते हैं। ये नीतीश कुमार की राजनीति का ही हिस्सा रहा होगा कि निशांत के नाम से युवा

विधायकों की टीम बने, जो उनके सपोर्ट में रहकर निशांत की राजनीतिक चेतना को जागृत रख सके। इसके साथ ही राजनीति का आगाज कर रहे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सीधे सांगठनिक उच्च पद या फिर मंत्री का पद लेकर अपनी नई पारी की शुरुआत नहीं की। पहले जदयू के सामान्य सदस्य बने और बनते ही बिहार के 38 जिलों की यात्रा की घोषणा कर डाली। इस बात का खुलासा अपनी मां की प्रतिमा पर फूल अर्पण करने के बाद की। उन्होंने कहा कि मां का आशीर्वाद ले लिया और अब राजनीतिक सफर पर निकलूंगा। ये राजनीतिक यात्रा बिहार के 38 जिलों से गुजरेगी।

बहरहाल, इतना तो आप मानते हैं न कि नीतीश कुमार का दिमाग काफी तेज चलता है। आप ये भी जानते हैं कि नीतीश कुमार अपने समकालीन नेता लालू यादव की तरह नहीं हैं। आपको ये भी पता होगा कि नीतीश कुमार बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं करते। नीतीश कुमार इंजीनियर रहे हैं। उनका बेटा भी मेसरा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स कर चुका है। नीतीश कुमार आनन-फानन में लालू यादव की तरह अपने बेटे को लॉन्च करने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने बकायदा राजनीति में लाने के बाद फील्ड में तपने के लिए छोड़ दिया है। ध्यान रहे कि जब से निशांत कुमार ने जेडीयू ज्वाइन किया है। वे लगातार सक्रिय रहे हैं। मीडिया में अपने पिता से ज्यादा बार कुछ न कुछ बोलते हुए देखे जाते हैं। संयमित और विनम्र स्वभाव के साथ बोलते हैं। कोई एक्स्ट्रा और विवादित बात नहीं करते। नपा-तुला बोलते हैं। सियासी पंडितों का भी मानना है कि निशांत कुमार को पूरी तरह राजनीति में पक्का कर यानी तपाकर सामने लाने की प्लानिंग है। नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत किसी अन्य को देने की सोचें, उससे पहले उनके खास सिपहसालार निशांत को राजनीति में बिल्कुल पक्का कर देंगे। ज्ञात हो कि बिहार दिवस के मौके पर गांधी मैदान में आयोजित तीन दिवसीय उत्सव में भ्रमण के लिए पहुंचे निशांत कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग के स्टॉल का दौरा किया था। इस दौरान वे अपने पिता के किए गए विकास कार्यों को देखकर गौरवान्वित लगे। उन्होंने कहा कि पापा ने इस विभाग में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं और उनकी छत्रछाया में आपदा प्रबंधन विभाग काफी फल-फूल रहा है। पिछले 20 वर्षों में इस विभाग ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने निरीक्षण के दौरान ये भी कहा कि मैंने देखा कि कैसे भूकंप के दौरान बिल्डिंग शेक करती है और उसे बचाने के लिए क्या योजनाएं हैं। हालांकि, मुझे लगता है कि आम जनता में अभी भी जागरूकता की कुछ कमी है। मैंने विभाग के अध्यक्ष उदय कांत जी से भी इस बारे में बात की है कि लोगों के बीच जागरूकता बढ़नी चाहिए। निशांत कुमार के बयान के इस आईने में आप उन सियासी चर्चाओं की पड़ताल कर सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि निशांत कुमार बकायदा नीतीश कुमार के कुछ खास करीबी लोगों के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। उसी तरह का बयान दे रहे हैं। नपी तुली बात कह रहे हैं। राज्य सरकार की तारीफ कर रहे हैं। जहां पिता नहीं पहुंचते हैं। वहां निशांत कुमार पहुंच जाते हैं। कुल मिलाकर उन्हें बिहार की राजनीति में इस कदर एक्टिव किया जा रहा है कि वे महज जेडीयू के प्राथमिक सदस्य बनकर नहीं रह जाएं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए जेडीयू को लीड करें। जिस दिन निशांत जेडीयू ज्वाइन कर रहे थे, उस दिन प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा था कि पार्टी के भविष्य अब यही हैं। कुल मिलाकर बिहार में नीतीश कुमार के बदले एक स्ट्रांग नेतृत्व को जेडीयू के अंदर से उभारने की कोशिश का नाम निशांत कुमार है। जानकार मानते हैं, आने वाले दिनों में इसका प्रभाव दिखने

लगेगा।

गौरतलब है कि बिहार की राजनीति में पिछले 35 साल में दो ब्रांड की चर्चा होती है, एक लालू और दूसरा नीतीश। कोर्ट के फैसले के कारण लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जबकि नीतीश कुमार भी अब अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं, लेकिन दोनों के बेटे बिहार की सियासत में दमखम के साथ एक-दूसरे को चुनौती देने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव तो पिछले दो दशक से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं लेकिन निशांत कुमार ने हाल ही में राजनीतिक पारी की शुरुआत की है। ऐसे में इस बात की बहस शुरू हो गई है कि 2029 और 2030 में होने वाले चुनावों में कौन किस पर भारी पड़ेगा? विदित है कि 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव बिहार की सत्ता के केंद्र बिंदु बने रहे। 2005 में लालू-राबड़ी को सत्ता से हटाकर नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली और तब से वही सत्ता के सिरमौर हैं। हालांकि 2029 और 2030 की लड़ाई लालू और नीतीश के बीच नहीं, बल्कि इनके बेटों के बीच होनी है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी 2014 से राजनीति में क्रिकेट का पिच छोड़कर पिता का हाथ मजबूत कर रहे हैं। 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश और लालू जब एक हुए तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी सरकार में तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनाए गए। हालांकि 2017 में नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, जिसके बाद तेजस्वी पहली बार नेता प्रतिपक्ष बन गए। 2022 में जब नीतीश ने पाला बदलकर लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाया था तो तेजस्वी को दूसरी बार डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में बनने का मौका मिला था, लेकिन 2024 में नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने के कारण तेजस्वी सरकार से बाहर हो गए। 2020 और 2025 विधानसभा का चुनाव तेजस्वी के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन तेजस्वी सफल नहीं हुए।

2020 में प्रदर्शन संतोषजनक था लेकिन हालिया 2025 के चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन रहा। तेजस्वी फिलहाल नेता प्रतिपक्ष के साथ-साथ आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव पिछले डेढ़ दशक से राजनीतिक पारी खेल रहे हैं और राजनीति में परिपक्व हो चुके हैं। उनके पास पिता लालू प्रसाद यादव का बनाया हुआ बड़ा वोट बैंक है। 14% यादव और 17% मुस्लिम वोट बैंक का अधिकांश हिस्सा आरजेडी के पास है। तेजस्वी लगातार तीसरी बार राघोपुर से विधायक बने हैं। नीतीश के साथ दो बार डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर चुके हैं, चौथी बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तेजस्वी यादव अच्छे वक्ता बनकर उभरे हैं। 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार रह चुके हैं। किन्तु तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव का 15 साल का कार्यकाल सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। भ्रष्टाचार और जंगल राज के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। लालू चारा घोटाले में सजायफ्ता हैं, जिस वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसी कारण तेजस्वी यादव अपने पिता का पोस्टर लगाने से बचते हैं। उनके परिवार में भी काफी विवाद है। महज 9 कक्षा तक की पढ़ाई करने के कारण विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। खुद भी लैंड फॉर जॉब स्कैम में चार्जशीटेड हो चुके हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने लंबे इंतजार के बाद राजनीतिक पारी की शुरुआत की है और अब मजबूती से अपने इरादे जाहिर कर रहे हैं। निशांत को अभी पार्टी में और सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है लेकिन चर्चा है कि जल्द ही उन्हें बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। जेडीयू नेताओं की डिमांड है कि उन्हें सीएम बनाया जाए। अगर सीएम नहीं बने तो डिप्टी सीएम बनना तय है। इसके साथ ही पार्टी की कमान भी निशांत ही संभालेंगे, ये भी तय है। नीतीश कुमार का 20 साल का सुशासन और उनकी भ्रष्टाचार मुक्त छवि निशांत कुमार का सबसे मजबूत पक्ष है। निशांत की एंट्री राजनीति में नेताओं और कार्यकर्ताओं की डिमांड पर हुई है। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और उन पर न तो किसी तरह का कोई मामला दर्ज है और न ही किसी तरह के विवादों में रहे हैं। किन्तु निशांत कुमार ने राजनीति में आने में काफी समय लगा दिया है। करीब 50 साल की उम्र में उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग हुई है।

बहरहाल, नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और उसका वोट बैंक बहुत ज्यादा

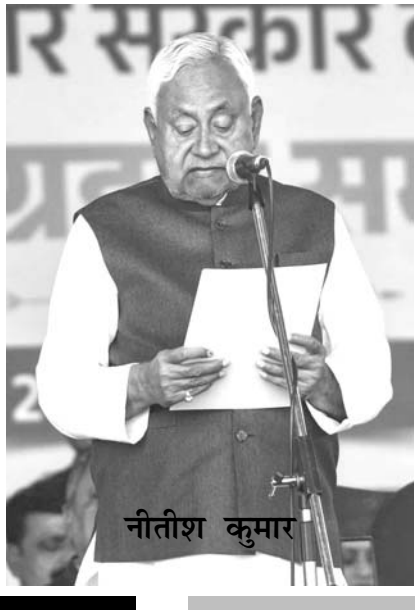
नीतीश कुमार

उदय नारायण चौधरी

तेजस्वी यादव

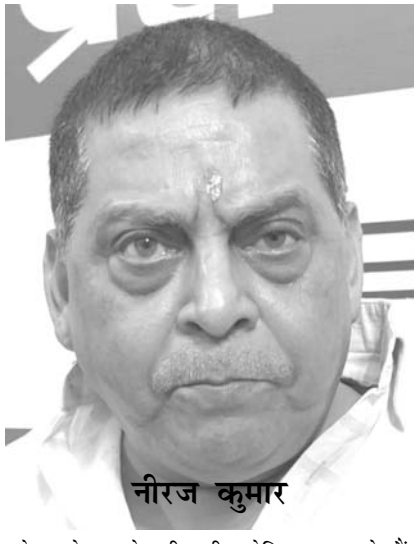
नीरज कुमार

नहीं है। ऐसे में इस वोट बैंक को बचाकर रखने के साथ-साथ नए वोट को जोड़ने की भी चुनौती होगी। तेजस्वी यादव की कमजोरी और मजबूती लोग देख चुके हैं, जबकि निशांत अभी नए-नवेले हैं। नीतीश कुमार की छवि का लाभ जरूर निशांत कुमार को मिल सकता है लेकिन निशांत की जो अपनी छवि है, वह बहुत लो प्रोफाइल वाला है। सुगमता से और सहजता से लोगों से मिलते हैं तो बिहार के लोग ऐसे नेताओं के प्रति आकर्षित होते हैं लेकिन असली ताकत का पता तो आने वाले चुनाव में ही चलेगा। वही आरजेडी नेताओं का मानना है कि तेजस्वी यादव से निशांत की तुलना नहीं हो सकती है। राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा कि हमारे नेता के पास राजनीति का लंबा अनुभव है, जबकि निशांत अभी-अभी राजनीति में आए हैं। विधानसभा चुनाव में हमारे नेता ने जो-जो घोषणा की थी, उसकी एनडीए की सरकार ने नकल की थी। तेजस्वी यादव इस्टैबलिश्ड लीडर हैं। विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो घोषणा की थी, उसकी नकल कर ली गई। निशांत भी आ रहे हैं अच्छी बात है लेकिन असली ताकत तो आने वाले समय में पता चलेगी। वहीं, जेडीयू नेताओं को निशांत कुमार में भविष्य नजर आता है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि कोई कुछ भी दावा कर ले लेकिन बिहार में नीतीश कुमार का ही मॉडल चलेगा। 2029 और 2030 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए हमलोग निशांत कुमार की अगुवाई में ही आगे बढ़ेंगे। निशांत कुमार ने जिस प्रकार से राजनीतिक पारी की शुरुआत की है, उसे देखते हुए तेजस्वी यादव से उनकी कहीं तुलना ही नहीं है। बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा और 2029-2030 के युवराज निशांत ही होंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार निशांत कुमार की गुणगान कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता पंकज कुमार सिंह कहते हैं कि निशांत, तेजस्वी की तरह रणछोड़ नहीं हैं। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बिहार में सुशासन को आगे बढ़ाएंगे।

विदित है कि पिछले डेढ़ दशक की राजनीति में तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर की है लेकिन पिता वाली लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाए। तेजस्वी अब लालू की परंपरा को भी तोड़ने में लगे हैं। लालू अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कनेक्ट करने के लिए मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा-दही भोज का आयोजन करते थे। इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे। छठ जैसे महापर्व में अपनी बड़ी भूमिका निभाते थे, लेकिन इन सब से तेजस्वी ने दूरी बना ली है। वहीं, निशांत कुमार ने अभी हाल ही में राजनीतिक पारी की शुरुआत की है लेकिन पिता की विरासत

निशांत कुमार

को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। छठ-दिवाली और होली से लेकर इफ्तार पार्टी तक में नीतीश कुमार के नक्शेकदम पर चल रहे हैं। इसके साथ ही पिता के सुशासन के काम को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी काफी सहजता से मिलते हैं। वही तेजस्वी यादव जहां अपने माता-पिता के 15 साल के शासन के कामकाज की चर्चा करने से बचते हैं, वहीं, निशांत खुलकर नीतीश कुमार के विकास की चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी और निशांत एक-दूसरे के खिलाफ भले ही ना बोल रहे हों लेकिन एक-दूसरे के पिता के शासनकाल पर हमला जरूर बोल रहे हैं। 2005 से पहले में बिहार की क्या स्थिति थी, निशांत ने उसका भी जिक्र करना शुरू कर दिया है तो तेजस्वी लगातार दावा करते हैं कि नीतीश कुमार के शासन में बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ा है। वह आंकड़ों के माध्यम से सरकार की नाकामी गिनाते रहते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव में पूरी तरह नाकाम साबित हुए। 144 सीटों पर लड़ने के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल को सिर्फ 25 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू को 2025 चुनाव में 85 सीटों पर सफलता मिली। वहीं लोकसभा में जेडीयू के 12 और आरजेडी के महज 4 सांसद ही हैं। हालिया राज्यसभा चुनाव की बात की जाये तो यहां भी तेजस्वी की रणनीति फेल हो गई। न केवल उनके कैंडिडेट हारे, बल्कि एक विधायक वोट देने भी नहीं आए। ऐसे में 2029 और 2030 में जो चुनाव होंगे, वह दिलचस्प होने वाले हैं। आंकड़े भले ही तेजस्वी के पक्ष में ना हो, लेकिन चुनाव में ही पता चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा?●

यूजीसी के नये नियम से खंडित हुई मोदी की लोकप्रियता

● संजय सिन्हा

पिछले साढ़े ग्यारह वर्ष से अनवरत मोदी सरकार की लोकप्रियता देश में ही नहीं दुनिया में डंका बज रहा था तभी एकाएक बरसात की फुहारे की तरह जो किसी को समझ में आई किसी को नहीं जैसे बरसात के फुहारे में कोई अपनी छतरी खोलता है कोई ऐसे ही चल पड़ता है के तरह यूजीसी में नयें नियम जोड़ कर आ गई बाजार में में इसमें कई तर्क वितर्क होतें रहे और होना भी चाहिए,परंतु एक नियम किसी भी अनपढ़ को समझ से परे है कि जब कोई जानबूझकर किसी एक वर्ग पर आरोप लगाये और स्पष्ट हो जाये कि आरोप लगाने वाला गलत आरोप लगाये हैं, उसके उपरांत भी उस व्यक्ति छोड़ दिया जाये और उसे कोई सजा नहीं हो? ये किसी महामुर्ख को भी गले के निचे नहीं उतरती। इस कायराना नियम की भर्तसना समाज के सभी वर्गों कर रहे हैं जिन्हें जनरल वर्ग के विरोध में ये नया हथियार दिया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति या ओबीसी सभी वर्गों इस कायराना नियम को बेकार एवं समाज में नफरत

ए क दूसरे के लिए वैमनस्य जैसा गंदी व्यवस्था की शुरुआत मान रहे हैं। इस कायराना नियम से जनरल वर्गों के बच्चों (विधार्थी) सहित शिक्षक-प्रोफेसर के जीवन सुरक्षित रह पायेगें क्या? यूजीसी नियम में जर्बदस्ती ओबीसी को शामिल करना एक सोचा समझा खतरनाक खेल है, अगर हम आकड़े पर आये तो शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कुल शिकायत की संख्या के 93 प्रतिशत शिकायत संख्या सिर्फ ओबीसी वर्गों पर दर्ज हैं। एक आकड़े जो एससी एसटी ऐक्ट में भी सबसे ज्यादा मुकदमे ओबीसी वर्गों पर लगे हुए हैं जो कि 90 प्रतिशत फर्जी पाई गई है, ऐसे कानून से कुछ राजनीतिक दल एवं कुछ राजनीतिक व्यक्तियों को फायदा होता होगा ऐसा माना जा सकता हैं परंतु वैसी राजनीति स्थाई नहीं होती। एससी/एसटी की देश में सबसे लोकप्रिय नेता सुश्री मायावती ने भी गलत बताया और सुप्रीमकोर्ट के तत्काल प्रभाव से रोक को सर्मथन किया हैद्य सबसे ज्यादा चर्चा रोहित वेमुला के आत्महत्या कि आती है जबकि रोहित वेमुला ने अपने सुसाइड नोट में अपने सुसाइड के दोष किसी पर नहीं लगाई थी, जबकि रोहित वेमुला के जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था। क्या

ऐसे आत्महत्या को आधार बनाना कहाँ तक उचित है? आज समाज में कोई भेदभाव नही बचा सभी मिलजुलकर रह रहे हैं, वो गाँव हो शहर हो या कोई सोसायटी, अब सभी अपने अपने काम में इतने व्यस्त है कि उनको अपने परोसी का नाम तक पता नहीं होता टाईटल तो बहुत दूर की बात रही? अगर इसे सर्वे करा कर देखा जाये तो कहीं न कहीं एससी एसटी वर्गों को इससे नुकसान हो रही है, समाज के एक वर्ग कोई जोखिम नहीं लेना चाहता इस स्थिति में एससी एसटी वर्गों को किराये के मकान, दुकान, पीजी हाँस्टल या कोई भी सौदा करने से परहेज करते हैं, जबकि कोई भी एससी एसटी वर्ग ऐसा कोई गलत काम या आरोप नहीं लगाते जिन्हें अपनी पढ़ाई करनी है या परिवार चलानी हैं, गलत आरोप लगाने वालों की संख्या किसी भी वर्गों में एक प्रतिशत भी नहीं है,शायद एक लाख पर एक व्यक्ति मुस्किल से अब हम कुछ आकड़ों को समझते हैं, वर्ष 2023-24 में कुल उत्पीड़न के मामले आये 378 जबकि इसी वर्ष कुल छात्र-छात्राओं की संख्या थी 4.82 करोड़ लगभग जो एक करोड़ पर 78 की संख्या आतें है, मतलब एक लाख 29 हजार छात्रों पर एक उत्पीड़न के मामले उसमें भी एक मजे की बातें हैं कि जिस यूजीसी नये नियम में भारत के शिक्षा मंत्री ने ओबीसी वर्गों को भी शामिल किया है

यूजीसी प्रदर्शनकारियों के प्रति सरकार की दोहरी नीति

यूजीसी नियम के विरोध में प्रदर्शनकारियों को 6 मार्च को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मिलने के बाबजूद सरकार के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने कानून- व्यवस्था संबंधी चिंताओं के कारण उनकी इस अनुमति को अस्वीकार कर दिया, जबकि फरवरी के महिने में नगीना उत्तर प्रदेश के सांसद चन्दशेखर रावण को जंतर मंतर पर रैली करने एवं समाज के एक वर्ग को भड़काऊ भाषण देने की ईजाजत मिली थी वो भी ऐसे समय में जब सुप्रीमकोर्ट के 29 जनवरी, 2026 के यूजीसी पर यथावत बने रहने का आदेश जारी कर 19 मार्च को अगली सुनवाई के आदेश जारी किया गया थाह्य सांसद रावण आगे आंदोलन करने एवं यूजीसी कानून को लागू करने की कोर्ट और सरकार से अनुरोध एवं धमकी भी दे दिया हैह्य उधर 6 मार्च को रैली नहीं करने के आदेश जारी के बाबजूद जिन लोगों ने जबर्दस्ती शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने हेतु एकत्रित हुए थे उनमें से लगभग 125 लोगों को गिरफ्तार कर उनकी विवरण लेने के बाद उन्हें बाहरी दिल्ली के ईलाको में छोड़ दिया गया, परंतु उनके एवं उनके परिवार के लोगों पर दिल्ली पुलिस ध्यान रख रही है। इसी तरह अखिल भारतीय क्षत्रिय मंच के पदाधिकारी एवं सनातन करनी सेना के प्रवक्ता गंगा सिंह राठौर ने बताया कि 19 मार्च को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के मिली हुई अनुमति को मात्र एक दिन पहले 18 मार्च, 2026 को उस अनुमति को लिखित निरस्त्र कर दिया और कोई भी प्रदर्शन न करने की मौखिक आदेश भी दे डाला पुलिस इस पर कुछ भी बताने से बचना चाहती हैं।

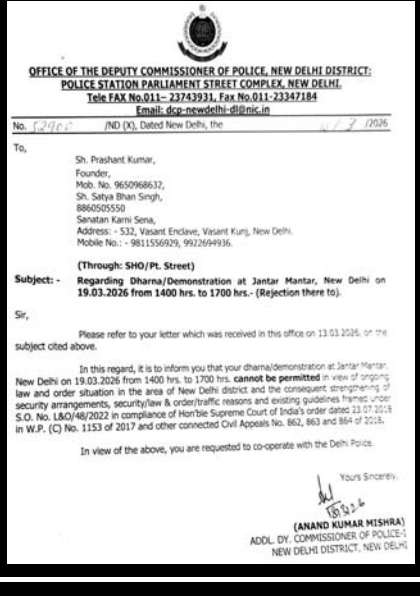

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE, NEW DELHI DISTRICT: POLICE STATION PARLIAMENT STREET COMPLEX, NEW DELHI.
Tele FAX No.011– 23743931, Fax No.011-23347184
Email: dcp-newdelhi-dl@nic.in

No. 5290 /ND (X), Dated New Delhi, the 18/3 /2026

To,

Sh. Prashant Kumar,
Founder,
Mob. No. 9650968632,
Sh. Satya Bhan Singh,
8860505550
Sanatan Karni Sena,
Address: - 532, Vasant Enclave, Vasant Kunj, New Delhi.
Mobile No.: - 9811556929, 9922694936.

(Through: SHO/Pt. Street)

Subject: - Regarding Dharna/Demonstration at Jantar Mantar, New Delhi on 19.03.2026 from 1400 hrs. to 1700 hrs.- (Rejection there to).

Sir,

Please refer to your letter which was received in this office on 13.03.2026, on the subject cited above.

In this regard, it is to inform you that your dharna/demonstration at Jantar Mantar, New Delhi on 19.03.2026 from 1400 hrs. to 1700 hrs. **cannot be permitted** in view of ongoing law and order situation in the area of New Delhi district and the consequent strengthening of security arrangements, security/law & order/traffic reasons and existing guidelines framed under S.O. No. L&O/48/2022 in compliance of Hon'ble Supreme Court of India's order dated 23.07.2018 in W.P. (C) No. 1153 of 2017 and other connected Civil Appeals No. 862, 863 and 864 of 2018.

In view of the above, you are requested to co-operate with the Delhi Police.

Yours Sincerely,

18.3.26

(ANAND KUMAR MISHRA)
ADDL. DY. COMMISSIONER OF POLICE-I
NEW DELHI DISTRICT, NEW DELHI

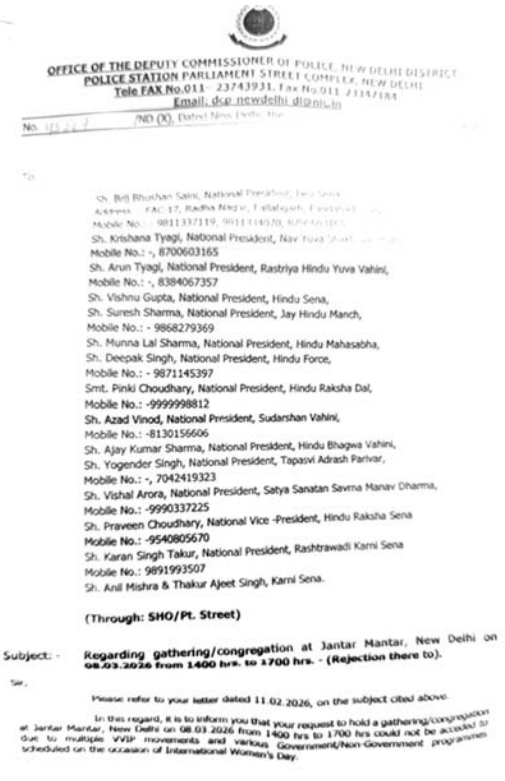

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE, NEW DELHI DISTRICT
POLICE STATION PARLIAMENT STREET COMPLEX, NEW DELHI
Tele FAX No.011- 23743931, Fax No.011 23347184
Email: dcp newdelhi dl@nic.in

No. /ND (X), Dated New Delhi, the

To

Sh. Brij Bhushan Saini, National President, ...
Address - FAC-17, Radha Nagar, Fallabgarh, ...
Mobile No.: - 9811337119, ...
Sh. Krishana Tyagi, National President, Nav Yuva ...
Mobile No.: -, 8700603165
Sh. Arun Tyagi, National President, Rastriya Hindu Yuva Vahini,
Mobile No.: -, 8384067357
Sh. Vishnu Gupta, National President, Hindu Sena,
Sh. Suresh Sharma, National President, Jay Hindu Manch,
Mobile No.: - 9868279369
Sh. Munna Lal Sharma, National President, Hindu Mahasabha,
Sh. Deepak Singh, National President, Hindu Force,
Mobile No.: - 9871145397
Smt. Pinki Choudhary, National President, Hindu Raksha Dal,
Mobile No.: -9999998812
Sh. Azad Vinod, National President, Sudarshan Vahini,
Mobile No.: -8130156606
Sh. Ajay Kumar Sharma, National President, Hindu Bhagwa Vahini,
Sh. Yogender Singh, National President, Tapasvi Adrash Parivar,
Mobile No.: -, 7042419323
Sh. Vishal Arora, National President, Satya Sanatan Savrna Manav Dharma,
Mobile No.: -9990337225
Sh. Praveen Choudhary, National Vice -President, Hindu Raksha Sena
Mobile No.: -9540805670
Sh. Karan Singh Takur, National President, Rashtrawadi Karni Sena
Mobile No.: 9891993507
Sh. Anil Mishra & Thakur Ajeet Singh, Karni Sena.

(Through: SHO/Pt. Street)

Subject: - Regarding gathering/congregation at Jantar Mantar, New Delhi on 08.03.2026 from 1400 hrs. to 1700 hrs. - (Rejection there to).

Sir,

Please refer to your letter dated 11.02.2026, on the subject cited above.

In this regard, it is to inform you that your request to hold a gathering/congregation at Jantar Mantar, New Delhi on 08.03.2026 from 1400 hrs to 1700 hrs could not be acceded to due to multiple VVIP movements and various Government/Non-Government programmes scheduled on the occasion of International Women's Day.

वही ओबीसी वर्गों पर 92 से 93 प्रतिशत उत्पीड़न के मामले दर्ज किये गये हैं, अब इस आकड़े को भी अलग कर सिर्फ जनरल वर्गों पर उत्पीड़न के मामले देखा जाये तो ये 30 लाख छात्रों पर 1 उत्पीड़न का मामले बनते हैं। अभी आगे एक और आकड़े पर ध्यान देना होगा कि कुल उत्पीड़न मामले जो आतें है इनमें 90 प्रतिशत फर्जी और पुर्वाग्रसित उत्पीड़न के मामले लंबीत हुए हैं, इसलिए सरकार ने और खासकर भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने फर्जीवाल शिकायत करने वालों पर केस चलाने के नियम भी हटा दिया है। क्या इस तरह की समाजिक धुव्रीकरण एक न्याय है, क्या? ऐसी समाज की व्यवस्था होने पर नुकसान सभी को है, क्या ऐसी व्यवस्था में एक शिक्षक प्रोफेसर खुलकर अपने छात्रों को पढ़ा पायेगा? वो प्रोफेसर को एक समेस्टर का समय तो सिर्फ छात्र छात्राओं के जाति पता लगाने में लग

जायेगें! जबकि दूसरे तरफ पढ़ने में तेज विधार्थी कभी किसी कम तेज पढ़ने वाले को मदद करने के पहले उसकी जाति का पता लगायेगा उसको डर लगेगा कि ये विधार्थी तो अच्छा है स्वभाव भी अच्छे हैं पर इससे दोसती किया जा सकता हैं क्या? वगैरह वगैरह और कैम्पस का वही हाल होगा जैसे किसी किक्रेट के मैदान में दो अलग अलग टीम खड़े होते हैं! यूजीसी पुरानी या नई नियम हो या फिर एससी एसटी कानून ये हमारे समाज को बाटते हैं, इसके विरोध सभी शिक्षित वर्ग करते हैं। ये सिर्फ किसी भी सरकार के लिए चुनावी फायदा है जबकि नुकसान समुचे समाज का होता रहा है। कमसेकम कोई शिक्षित या सिर्फ हिसाब किताब तक की जानकारी रखने वाले समाज भी नरेंद्र दामोदरदास मोदी सरकार या कहें कि डाक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को परमपूज्य मानने वाले अनुयायी के लोगों की सरकार ऐसी घृणित व कुठित समाज की दिशा तै करेंगे, ये किसी को अभी भी विश्वास नहीं होता है। समाज में सरदार पटेल, संत रविदासजी, कबीरदास जी की कार्यों से एकजुटता के सोच वाले लोगों चाहिए न कि सिर्फ चुनावी लाभ। ●

दिल्ली की खूनी होली

त्यौहार पर साम्प्रदायिक हत्या

● संजय सिन्हा

तरुण खटीक की मौत एक कमजोर कर रहे सनातन संस्कृति व्यवस्था का परिणाम माना जा सकता है, पहले हिन्दुओं को जाति में बाटो, फिर उन्हें वर्ग (कटेगरी) में, फिर उनके भावनाओं को भरकाने वाली सरकारी व्यवस्था, भले वो कमजोर गरीब चमार हो या ब्राह्मण सभी के मन में एक दूसरे के प्रति विकृत सोच और घृणा पनपने लग जाती है। इसका परिणाम समाज के बच्चे गली मुहल्ले से ही एक दूसरे के प्रति नफरत करने लग जाते हैं। आप समरसता की बातें कितने भी क्यों न करें? कहीं न कहीं ये दिखावा हो जाता है। आज वरुण खटीक नहीं बल्कि वरुण हिन्दू की नृशंस हत्या की 10 दिन हो चुके हैं पर न कोई रावण, न कोई चन्द्रशेखर आजाद उसके विलखती व कलपत्ती माँ के आंसू पोछने नहीं आया? हिन्दू या कहें तो राष्ट्र को कमजोर करने वाले कितने भी सरकार यूजीसी एवं एससी एसटी कानून क्यों न बना ले! हिन्दू एक रहेगें, ये स्पष्ट वरुण खटीक के हत्या से साफ हो जाता है। सनातन संस्कृति कभा कमजार नहा हा सकता सनातन सस्कृात सभी धर्म को अपना मानती है एवं समान भी करतीं हैं। वरुण खटीक अनुसूचित जाति बाद में है पहले हिन्दू हैं, आज सभी जाति के लोगों ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय जाट हो या

जाटव सभी वरुण खटीक के मां के साथ है और न्याय की मांग कर रहे हैं। अब इस घटना की विस्तृत चर्चा करते हैंद्य देश की राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में 4 मार्च होली के दिन होली खेल रही 9 साल की बच्ची को नहीं मालूम था कि वह अपने ही परिवार के सदस्य पर जो पानी का गुब्बारा फेंक रही है, उसके छींटे किसी को इतने गंदे इस वैश्विक युग में लगेगें, जब सऊदी अरब यूएइ म ाहन्दू मादर का स्थापना एव ादवाला होली का त्यौहार मनाई जा रहीं हैं। गुब्बारे के छिट्टे ने इलाके में सांप्रदायिक तनाव का कारण बन जाएंगे। उस 9-10 वर्ष की बच्ची को नहीं पता था कि वह गुब्बारा उसके परिवार के लिए काल साबित होगा, जिसकी चपेट में उसका पूरा परिवार आ जाएगा। उसे यह भी नहीं मालूम था कि उस गुब्बारे से निकले पानी की वजह से परिवार ना केवल एक अनचाहे विवाद में पड़ जाएगा, बल्कि उसके परिवार के 25 साल के भाई तरुण की जान भी चली जाएगी। दिल्ली शहर के उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में होली की रात हुए एक ऐसे विवाद की, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।

इस विवाद की शुरुआत एक महिला पर रंग वाले पानी के छींटे लगने से हुई। उस लड़की ने अपने घर के नीचे खड़े अपने रिश्तेदारों पर एक पानी का गुब्बारा फेंका था, जो सड़क पर जा गिरा और फट गया, जिसके बाद रंगीन पानी के कुछ छींटे पड़ोस में रहने वाले दूसरे समुदाय की एक महिला को जा लगे। जिसके बाद हुए विवाद में हिंदू परिवार के युवक की जान चली गई। इस मामले में पुलिस ने अभी तक

एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया। जबकि घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। साथ ही व्याप्त तनाव को देखते हुए पुलिस कोई कोताही नहीं बरत रही है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात करते हुए इलाके में कड़ी सुरक्षा की गई है। रंग के छींटे लगते ही गालियां देने लगी महिला। दरअसल गुब्बारे में भरे पानी के छींटे लगने के बाद पड़ोस में रहने वाली वह महिला ना केवल भड़क गई, बल्कि उसने गंदी-गंदी गालियां देकर विवाद करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने अपने परिजनों व अपने समुदाय के अन्य लोगों को बुला लिया और होली खेल रहे परिवार पर हमला किया। इस दौरान 8 से 10 आरोपियों ने वहां मारपीट करते हुए जमकर तोड़फोड़ भी की। पीड़ित परिवार ने जैसे-तैसे अपने आप को घर के अंदर बंद करते हुए उनसे बचाया, इस झगड़े के दौरान परिवार का सदस्य तरुण अपने दोस्त के घर गया हुआ था और वो इस झगड़े से बेखबर था। जब तरुण रात करीब 10.30 बजे अपने दोस्त के घर से वापस लौट रहा था, इसी दौरान रास्ते में करीब कमसे कम 20 से 40 आरोपियों ने उसे घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान आरोपियों ने लाठी, पत्थर और लोहे की रॉड से तरुण को बेरहमी से पीटा। जब वह बेसुध हो गया तो एक बड़ा सा पथ्थर तरुण के शरीर पर मार डाला उसके उपरांत आरोपी मौके से फरार

ह ा` गए। वरुण के परिजनों को झगड़े का पता चला तो वह मौके पर पहुंचे और वरुण को नजदीकी के अस्पताल में भर्ती किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही उत्तम नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। तरुण की मौत की खबर आते ही इलाके में तनाव फैल गया। मौत की खबर जैसे ही पता चली तो उसके दोस्त, परिचित और इलाके में रहने वाले अन्य लोग बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने आरोपियों के घर के बाहर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी दौरान 6 मार्च शुक्रवार को भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच कुछ लोगों ने एक कार और एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी। जिसके बाद दमकल की गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया, जिन्होंने आग पर तुरंत काबू पा लिया। इसी बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर आरोपी परिवार के घर पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने हस्तक्षेप करते हुए स्थिति और बिगड़ने से पहले भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इस बीच तरुण की माँ न्याय की मांग कर रहीं हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के न्याय तरीके का मांग कर रहीं हैं, परिवार की एक महिला ने न्याय की मांग करते हुए कहा कि घटना के सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं परिवार के कुछ सदस्यों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर सड़कों को जाम करने की चेतावनी भी दे दी। तरुण खटीक के परिवार को तब और न्याय मिलने की आशा बन गई जब मामले में हिंदूवादी संगठन के सदस्यों की सहयोग मिल गया, कुछ और हिंदू संगठन के सदस्य भी थाने पहुंचे और विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए, नारे लगाए और घटना में शामिल सभी लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग किया है। कुछ अपराधियों के घर के कुछ हिस्से तोड़ा भी जा रहा है, मिलाजुला कर वरुण खटीक की मौत की चर्चा बनीं हुई हैं।●

● संजीव कुमार झा

पश्चिम बंगाल में चुनावी डुगडुगी बज चुकी है। इसी साल अप्रैल में सूबे की नई सरकार चुनने के लिए मतदान होना है। हालांकि अभी तक चुनावी तिथियों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस चुनाव को अभी से सूबे की सियासत के लिए निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। सूबे की सत्ता में डेढ़ दशक से जमीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस बार सीधी और संगठित चुनौती पेश करने को तैयार है। ऐसे में आने वाले दो महीने न केवल चुनावी समीकरण तय करेंगे, बल्कि यह भी स्पष्ट करेंगे कि सत्ता, पहचान और महत्वाकांक्षा की इस जटिल लड़ाई को देखते हुए राज्य की राजनीतिक जमीन बदलाव के लिए कितनी तैयार है या फिर वह पुराना इतिहास ही दोहराने वाली है। इसमें दो मत नहीं कि पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में भाजपा खुद को एक निर्णायक मोड़ पर पाती है। पार्टी का एकमात्र लक्ष्य पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की मजबूत पकड़ से छीनना है। या यूं कहिए कि पश्चिम बंगाल की सत्ता से अब तक कोसों दूर रहने वाली भाजपा इस बार चुनाव में 'शेरनी के मुंह से बकरी का बच्चा' छीनने जैसा दुस्साहस दिखाना चाहती है। लेकिन, वहां के तेजी से बदलते राजनीतिक हालात में क्या यह संभव है! इसकी वजह यह है कि वर्ष 2021 के चुनावी नतीजे चीख-चीखकर बताते हैं कि वोट प्रतिशत के मामले में भाजपा अभी भी टीएमसी से करीब 10 फीसद पीछे है। हालांकि, वर्ष 2016 में केवल 3 सीट पाने वाली भाजपा ने 2021 के चुनाव में 294 में से 77 सीटें हासिल की, जो हिंदी पट्टी से बाहर पार्टी की असाधारण बढ़त को दिखाता है। शायद भाजपा की इस सियासी उछलकूद का यह भी एक कारण हो।

ममता बनर्जी

वैसे, भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी राज्य में जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। टीएमसी चौथी बार राज्य की सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव मैदान में है। अभी तक पिछले तीन चुनावों में टीएमसी ने लगातार अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई है। वर्ष 2021 विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर 215 कर ली थी। इससे पहले वर्ष 2016 के चुनावों में टीएमसी ने 211 सीटें जीती थीं। उससे पहले के चुनाव में जब टीएमसी ने वामदलों को सत्ता से हटाया था, तब ममता बनर्जी ने 184 सीटें हासिल की थीं। वर्ष

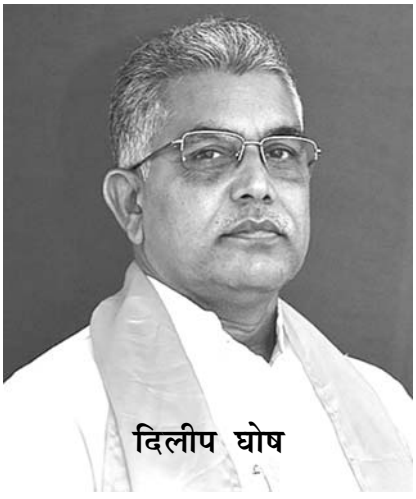
दिलीप घोष

2021 के चुनावों में ममता बनर्जी की टीएमसी का वोट शेयर 48 फीसदी के करीब चल गया था। भाजपा को 38.15 फीसदी वोट मिले थे, जिसके दम पर वह 2021 में 3 सीटों से छलांग लगाते हए सीधे 77 पर पहुंच गई थी। उसी के दम पर वह आज बंगाल में मुख्य विपक्षी दल भी है। उस वक्त राज्य में भाजपा की कमान दिलीप घोष के पास थी। वैसे, 2024 लोकसभा चुनावों में भी टीएमसी का प्रदर्शन अच्छा रहा था। इस बार के चुनाव में भी ममता बनर्जी ने किसी भी दल से गठबंधन की संभावनाओं को नकारते हुए अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं। ममता की इस घोषणा के बाद बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन गई है। संभावना जताई जा रही है कि अब कांग्रेस अपने पुराने गठबंधन वाम दलों के साथ बंगाल में चुनाव लड़ सकती है।

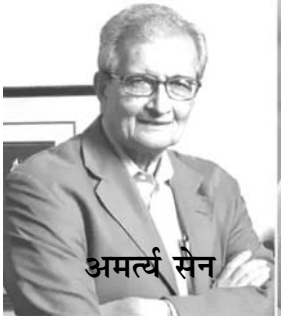
अमर्त्य सेन

मोहम्मद शमी

देव

खास बात यह है कि अभी बंगाल में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर घमासान मचा हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनावों से ऐन पहले चुनाव आयोग द्वारा बंगाल की मतदाता सूचियों का एसआईआर एक बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया है। चुनाव आयोग के चल रहे सत्यापन अभियान में अब तक 11.8 मिलियन से अधिक अनियमितताएं पाई गई हैं और मृत्यु, दोहराव और पते के बेमेल होने का हवाला देते हुए मतदाता सूचियों से लगभग 5.84 मिलियन नाम हटा दिए गए हैं। दिसंबर में प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे में 24 लाख मृत मतदाता, 12 लाख लापता मतदाता और जिलों में 10 लाख बहुप्रविष्टियां पाई गई। बताया जाता है कि यह राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा मतदाता शुद्धिकरण अभियान है। बता दें कि इस मतदाता शुद्धिकरण अभियान के तहत नामचीन अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, क्रिकेटर मोहम्मद शमी और बंगाली अभिनेता देव के परिवार जैसी प्रमुख हस्तियों को भी नोटिस भेजे गए हैं, जिससे प्रशासनिक लेखापरीक्षा एक सार्वजनिक तमाशा बन गई है। टीएमसी ने मनमाने ढंग से नाम हटाने, अपारदर्शी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल और अल्पसंख्यक बहुल सीमावर्ती जिलों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं, टीएमसी ने चुनाव आयोग पर भाजपा से जुड़े विक्रेताओं को तकनीकी काम आउटसोर्स करने का आरोप लगाया है। वहीं, भाजपा का कहना है कि इस संशोधन से खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना में फर्जी मतदाताओं और अवैध प्रविष्टियों का खुलासा हो रहा है। दोनों पार्टियां अब अपनी पूरी ताकत लगा चुकी हैं। इसके तहत भाजपा की बूथ समितियां सूचियों का सत्यापन कर रही हैं, जबकि टीएमसी घर-घर जाकर मतदाता जागरूकता अभियान चला रही है। कुल मिलाकर एसआईआर प्रक्रिया, जिसमें 79 मिलियन से अधिक पंजीकृत मतदाता शामिल हैं, इस प्रकार

2026 का पहला परोक्ष युद्ध बन गई है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पीएसी) के कोलकाता स्थित कार्यालय पर की गई छापेमारी चुनावों से पहले एक राजनीतिक षड्यंत्र का रूप ले चुकी है। ममता बनर्जी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए इस छापेमारी को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की बदले की कार्रवाई करार दिया और खुद को बंगाल की रक्षक के रूप में पेश किया। भाजपा नेताओं का दावा है कि इस तरह की आक्रामकता राजनीतिक हिंसा को जन्म देती है, जो अब बंगाल की राजनीति का पर्याय बन चुकी है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के लिए यह अवज्ञा के माध्यम से अपनी नैतिक साख को पुनः प्राप्त करने का प्रयास है, तो वहीं भाजपा के लिए यह टीएमसी को भ्रष्टाचार और भय से ग्रस्त सरकार के रूप में चित्रित करने का अवसर है।

जहां तक इस चुनाव का सवाल है, तो भाजपा के लिए इस बार की चुनावी कहानी सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी राजनीति से भी तय होगी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मकसद गुटबाजी खत्म करते हुए पार्टी में एकता को मजबूत करना है, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि पश्चिम बंगाल जैसे राजनीतिक रूप से उथल-पुथल वाले राज्य में अंदरूनी कलह किसी भी अभियान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बखूबी पता है कि इस मतभेद के खुले रहने का सीधा फायदा टीएमसी को मिलेगा। वैसे भी ममता बनर्जी का इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा पार्टियों के अंदरूनी मतभेदों का जमकर राजनीतिक लाभ उठाया है। वैसे, भाजपा को अपनी वैचारिक जड़ों और बंगाल से जुड़ाव का भी भरोसा है। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि भारतीय राजनीति के बड़े कैनवस पर भाजपा अपनी मजबूत वैचारिक विरासत और स्थायी ताकत के लिए अलग पहचान रखती है। इसकी जड़ें 1951 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत से जुड़ी हुई है, जिनके अखंड भारत के सपने को आज भाजपा के राजनीतिक नैरेटिव में फिर से जीवन मिला है। इसके साथ ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के 'आनंद मठ' और 'वंदे मातरम्' की भावना-राष्ट्रवाद, एकता और पहचान भी बंगाल जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य में भाजपा की वैचारिक आकांक्षाओं को प्रतिध्वनित करती है। यहां नोट करने वाली एक खास बात यह भी है कि भाजपा ने अपनी हिंदुत्ववादी पहचान को भले ही पूरी तरह नहीं छोड़ा है, लेकिन उसमें नरमी जरूर लाई है। पार्टी रणनीतिकार इसके पीछे का कारण महाराष्ट्र, दिल्ली और हाल ही में हुए बिहार चुनाव बताते हैं, जिनमें कम आक्रामक रुख अपनाने से कुछ मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा या फिर अन्य दूसरे विकल्पों पर विचार किया। भाजपा की बंगाल इकाई को उम्मीद है कि शासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी का भुगतान न होना और कल्याणकारी योजनाओं में होने वाले गबन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से उसे मिश्रित निर्वाचन क्षेत्रों में पैठ बनाने में मदद मिलेगी। भाजपा के अंदरूनी सूत्र तो यह भी यह भी बड़े यकीन के साथ कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टीएमसी पर लगाए गए 'महा जंगल राज' के साथ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से बार-बार बंगाल को 'अराजक', 'हिंसक', 'घुसपैठियों से भरा हुआ' बताने वाले तमाम आरोप भी इस बार यहां के चुनाव में कारगर साबित होंगे। वैसे, भाजपा की ओर से लगाए गए ये तमाम आरोप साधारण नहीं हैं और यह कोई मामूली बहस भी नहीं है, क्योंकि यह बंगाल की आत्मा पर हमला है और जो भी बंगाल की आत्मा को हल्के में लेता है, वह या तो अज्ञानी है या अहंकारी। बंगाल भूलता नहीं। बंगाल झुकता नहीं। और सबसे जरूरी बात, बंगाल नफरत की राजनीति को पहचानता है और उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है। इसी वजह से संघ, भाजपा की राजनीति बंगाल में बार-बार फिसलती है, क्योंकि वह इस धरती की स्मृति से डरती है।

संघ के वैचारिक स्तंभों में गिने जाने वाले नेता बलराज माधोक ने अपनी आत्मकथा में एक ऐसी बात लिख डाली है जिसे आज का संघ-भाजपा तंत्र अंधे कुएं में दफन कर देना चाहता है या यूं कहिए कि दफन कर चुका है। मधोक साफ शब्दों में न केवल स्वीकार करते हैं, बल्कि चेताते भी हैं कि 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ सावधान किया था। नेताजी की चेतावनी साधारण नहीं थी, राजनीतिक भी नहीं थी, बल्कि ऐतिहासिक थी।' नेताजी ने कहा था, 'बंगाल में सांप्रदायिक राजनीति को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।' यह वाक्य कोई भाषण नहीं था। यह बंगाल का घोषणा-पत्र था। और, यह भी संयोग नहीं था कि जिस सभा में सांप्रदायिक राजनीति का प्रतिरोध हुआ, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के माथे पर पत्थर लगा। उस पत्थर को हिंसा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। वह पत्थर बंगाल के विवेक की चेतावनी था। वह बताने आया था कि यह जमीन धार्मिक ध्रुवीकरण की प्रयोगशाला कभी नहीं बन सकती। लेकिन,

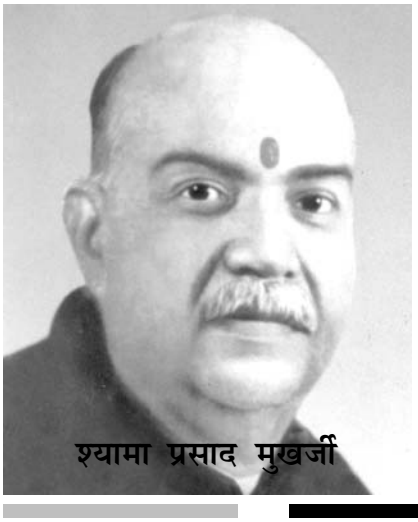
श्यामा प्रसाद मुखर्जी

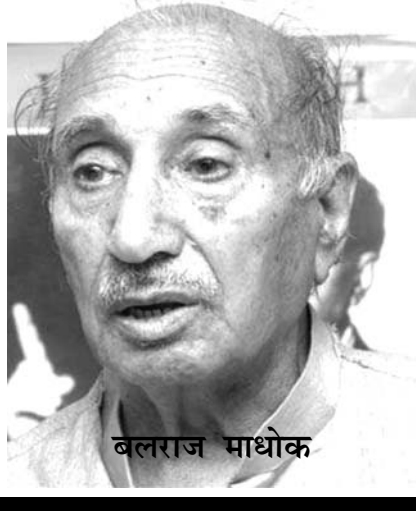
बलराज माधोक

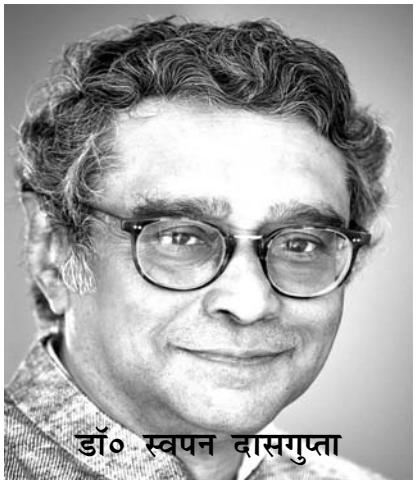
डॉ० स्वपन दासगुप्ता

ज्ञानेश कुमार

दुर्भाग्य देखिए कि आज वही राजनीति, वही जहर, वही सांप्रदायिक एजेंडा नए पैकेज में बंगाल पर थोपा जा रहा है। लेकिन, क्या बंगाल डर गया? नहीं। बंगाल तब भी नहीं डरा था, आज भी नहीं डरा है और शायद भविष्य में भी नहीं डरेगा, क्योंकि डर उसकी फितरत में ही नहीं है। बंगाल को 'अराजक', 'हिंसक', 'घुसपैठियों' से भरा हुआ बताना एक सस्ती रणनीति या फिर साजिश है। इसलिए संघ-भाजपा की बेशर्म राजनीति यहां बार-बार फेल हो जाती है और बंगाल को हराने की उन की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। इसलिए बंगाल के इतिहास को समझना होगा, उसे गंभीरता से अंतर्मन में उतारना होगा। ऐसे में भाजपा की तमाम कवायदों के बावजूद यह कह देना कि इस चुनाव में उसकी राह आसान है, असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं के बीच टीएमसी की मजबूत पकड़ उसके लिए बड़ी बाधाएं पेश करती हैं। दरअसल, पश्चिम बंगाल का सामाजिक ताना-बाना, खासकर इसके जनसांख्यिकीय परतों के कारण बेहद जटिल है। भले ही 2011 की जनगणना में मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत 27 था, लेकिन इस वर्ष यहां करीब 32 फीसद मुस्लिम मतदाता हैं। बड़े पैमाने पर इनका झुकाव टीएमसी की ओर माना जाता है। वहीं, हिंदू आबादी करीब 68 फीसदी है, जिनमें से लगभग 50 फीसद भाजपा समर्थक माने जाते हैं। भाजपा के घोषणापत्र की नई बनाई गई समिति के सदस्य डॉ. स्वपन दासगुप्ता कहते हैं, 'हमारी पार्टी का लक्ष्य हिंदू वोटों का कम से कम 60 से 65 फीसदी हिस्सा हासिल करना है, यानी लगभग 5 फीसदी से ज्यादा का रणनीतिक झुकाव जरूरी है।' डॉ. स्वपन दासगुप्ता का यह कथन स्पष्ट करता है कि राजनीति सिर्फ नैरेटिव नहीं, बल्कि अंकगणित का भी खेल है।

यही वजह है कि अब भाजपा इन सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों से कुशलता से निपटने के मकसद से नाराज समूहों को अपने साथ लाने और साथ ही अपने आधार को मजबूत करने के लिए असंतुष्ट वर्गों को जोड़ने पर जोर दे रही है। इसी के साथ अपने कोर वोट बैंक को भी बेहद संतुलित रणनीति के साथ मजबूत रखने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यह भी कयास लगाया जा रहा है कि विधायक हुमायूं कबीर के टीएमसी से निलंबन और उनके द्वारा अपनी नई पार्टी बनाने से मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर बंगाल के अन्य इलाकों में टीएमसी की मुस्लिम एकाधिकार वाली राजनीति डगमगा सकती है जिसका फायदा भाजपा उठा सकती है। लेकिन, इसे भी अभी दूर की कौड़ी मानना ही उचित होगा। हालांकि, संघ परिवार की वापसी ने इस पुनर्गठन को और गहरा कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद और सेवा भारती, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में दूरी बनाए हुए थे, अब जमीनी प्रचार अभियान का हिस्सा हैं। वे श्रेणी ए और बी के निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की छवि को नरम करने और विश्वास कायम करने के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, संत प्रवास, मंदिर से जुड़े कार्यक्रम और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। लेकिन, इतना सब कुछ करने के बावजूद भाजपा के ही एक वरिष्ठ रणनीतिकार कहते हैं, पश्चिम बंगाल ने हमें विनम्रता सिखाई है, लेकिन इसके बावजूद आप इसे दिल्ली से नहीं जीत सकते। आपको इसे बर्दवान, बांकुरा, कूच बिहार और कोलकाता में मेहनत से हासिल करना होगा।●

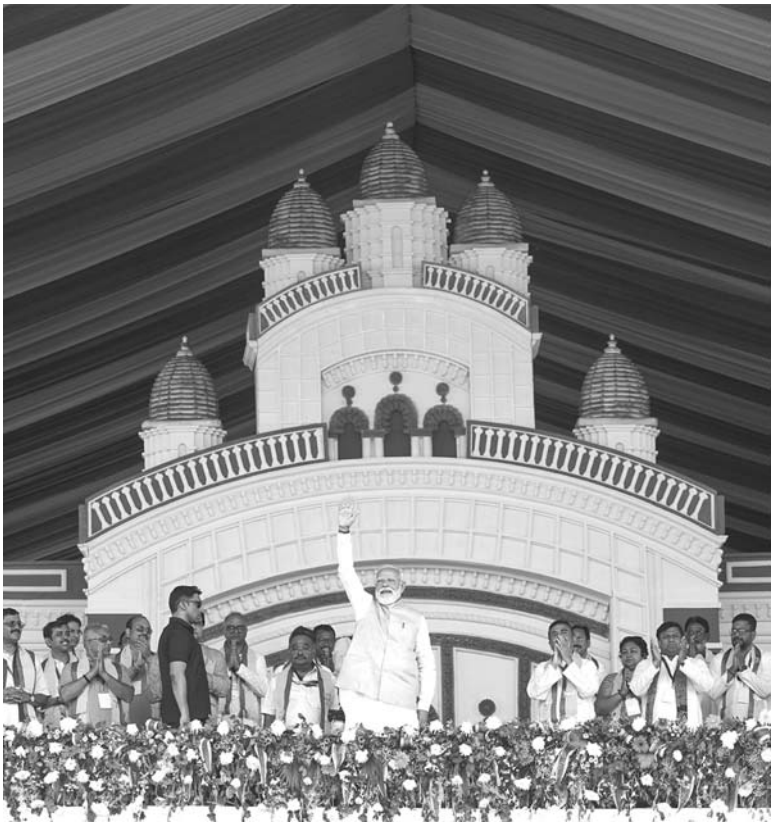

बीजेपी से नाराज ब्राह्मणों पर सभी दलों का दांव

● संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीस साल लंबा वक्त होता है. इतने समय में चेहरे बदलते हैं, नारे बदलते हैं, गठबंधन टूटते-बनते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी सच जस के तस रहते हैं. जाति, सामाजिक संतुलन और सत्ता तक पहुंचने की जद्दोजहद. साल 2007 में जिस सोशल इंजीनियरिंग ने सत्ता का ताला खोला था, करीब दो दशक बाद वही प्रयोग बदले पैकेज में फिर लौटता दिख रहा है. फर्क बस इतना है कि अब हालात ज्यादा जटिल हैं, मतदाता ज्यादा सजग हैं और सियासी खिलाड़ी एक-दूसरे की चाल पहले से बेहतर समझते हैं. 2027 के विधानसभा चुनाव को अभी वक्त है, लेकिन मैदान अभी से सज चुका है. हर दल अपने-अपने स्तर पर उस वोट बैंक की तलाश में है, जो सत्ता की सीढ़ी का आखिरी पायदान बन सकता है. इस पूरी कवायद के केंद्र में एक बार फिर ब्राह्मण वोटर आ खड़ा हुआ है. उत्तर प्रदेश की आबादी में करीब बारह फीसदी हिस्सेदारी रखने वाला यह वर्ग लंबे समय से किसी एक पार्टी का स्थायी वोट बैंक नहीं रहा. कभी सत्ता के साथ, कभी असंतोष में, कभी खामोशी से और कभी मुखर होकर इस वर्ग ने सियासत की दिशा बदली है.

करीब उन्नीस साल पहले बहुजन राजनीति की अगुआ मायावती ने दलित-ब्राह्मण गठजोड़ का जो प्रयोग किया था, उसने यह साबित कर दिया था कि अगर सामाजिक समीकरण सधे हों तो सियासी गणित ध्वस्त भी हो सकता है. 2007 की जीत उसी प्रयोग की देन थी. लेकिन समय के साथ वही फार्मूला कमजोर पड़ता गया. दलित-मुस्लिम समीकरण आजमाया गया, फिर दोबारा ब्राह्मणों की ओर हाथ बढ़ाया गया, लेकिन बीएसपी का जनाधार सिमटता चला गया. 2022 में पार्टी एक सीट पर आ गई. यह गिरावट खुद बताती है कि सिर्फ नारे और प्रतीक काफी नहीं होते, जमीन पर भरोसा भी चाहिए.इसी बदले हुए माहौल में सोशल इंजीनियरिंग 2.0 की चर्चा शुरू हुई है. इस बार प्रयोग सिर्फ एक दल नहीं कर रहा. समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी और उनके

सहयोगी सभी अपने-अपने तरीके से ब्राह्मण वोटर की नब्ज टटोल रहे हैं. फर्क यही है कि अब दलित वोटर को केंद्र में रखने के बजाय कई जगह ओबीसी वोटर को मुख्य धुरी बनाया जा रहा है और ब्राह्मण को उसके साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है. इस पूरी सियासत में सबसे दिलचस्प और आक्रामक एंट्री हुई है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की. पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ से जो संदेश दिया है, वह सिर्फ एक रैली भर नहीं है. आजमगढ़ वही इलाका है, जिसे समाजवादी पार्टी का अभेद किला माना जाता रहा है. यहां से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं. आज भी जिले की सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है. ऐसे इलाके में ब्राह्मणों की बड़ी रैली करना सीधे तौर पर सपा के सामाजिक आधार को चुनौती देना है. राजभर की रैली में ब्राह्मण समाज के सम्मान की बात हुई, परशुराम और सुहेलदेव के नारे लगे, यूजीसी के नए नियमों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के मुद्दे उठे. संदेश साफ था कि यह सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं, बल्कि पढ़े-लिखे, नौकरीपेशा और प्रभावशाली ब्राह्मण वर्ग को भरोसा देने की कोशिश है. मंच से यह भी जताया गया कि न्याय और सम्मान की लड़ाई में

सरकार और अदालत दोनों दरवाजे खुले हैं. यह भाषा सीधे उस वर्ग से संवाद करती है, जो खुद को दिशा देने वाला मानता है. इस रणनीति का एक और पहलू है. राजभर का निशाना बार-बार समाजवादी पार्टी पर रहा. संदेश यह कि आजमगढ़ में जो भीड़ जुटी है, वह सिर्फ समर्थन देने नहीं, बल्कि सपा के दबदबे को तोड़ने आई है. यह दावा जितना राजनीतिक है, उतना ही मनोवैज्ञानिक भी. चुनाव से पहले अगर किसी क्षेत्र में यह धारणा बन जाए कि मुकाबला अब एकतरफा नहीं रहा, तो वोटर का व्यवहार बदलने लगता है. उधर, समाजवादी पार्टी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी. पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव 2024 में असरदार साबित हुआ, उसी को आगे बढ़ाने की तैयारी है. लेकिन साथ ही ब्राह्मणों के बीच संदेश देने की कोशिशें भी दिख रही हैं. विधानसभा में नेता विपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडेय की नियुक्ति, पूर्वांचल के प्रभावशाली ब्राह्मण परिवारों से मुलाकातें और

सोशल मीडिया के जरिए दिए जा रहे संकेत इसी दिशा में पढ़े जा रहे हैं. बीजेपी के लिए स्थिति और भी नाजुक है. सत्ता में होने के फायदे हैं, लेकिन एंटी-इनकंबेंसी का दबाव भी. पार्टी के भीतर ब्राह्मण बनाम ठाकुर की चर्चाएं सामने आ चुकी हैं. कुछ ब्राह्मण विधायकों की बैठक और उस पर नेतृत्व की नाराजगी ने साफ कर दिया कि अंदरखाने खींचतान है. बरेली से लेकर प्रयागराज तक सामने आए विवादों ने इस असंतोष को और हवा दी. यही वजह है कि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जैसे चेहरे प्रतीकात्मक कदमों के जरिए ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश करते नजर आए. कांग्रेस इस पूरी बहस में अपेक्षाकृत खामोश है. एक तरफ राहुल गांधी की ओबीसी राजनीति, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की मजबूरी. कभी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की पहली पसंद रही कांग्रेस अब असमंजस में दिखती है. क्या वह दोबारा उस वर्ग की ओर खुले मन से लौट पाएगी, या मौजूदा लाइन पर ही चलेगी, यह वक्त बताएगा.

असल सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण वोट बैंक आज भी किसी सोशल इंजीनियरिंग का निर्णायक आधार बन सकता है. आंकड़े बताते हैं कि सवर्ण आबादी करीब बीस फीसदी है, जिसमें ब्राह्मण सबसे बड़ा हिस्सा हैं. लेकिन यह वोट हमेशा जाति के आधार पर एकजुट नहीं होता. उम्मीदवार, क्षेत्रीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और सत्ता का माहौल सब मिलकर फैसला तय करते हैं. यही कारण है कि ब्राह्मण राजनीति जोखिम भरी भी है और जरूरी भी.2027 की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश में सियासत अब सिर्फ नारों की नहीं, बल्कि धैर्य, संगठन और भरोसे की परीक्षा बनती जा रही है. सोशल इंजीनियरिंग 2.0 का शोर तेज है, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा दल प्रतीकों से आगे जाकर जमीनी हकीकत को साध पाता है. ब्राह्मण वोटर इस बार भी निर्णायक हो सकता है, लेकिन किसके पक्ष में, यह अभी पूरी तरह खुला सवाल है. ●

योगी से नाराज ब्राह्मण क्या बदल सकते हैं सियासी पाला

● **अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार , लखनऊ)**

उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी रंग लगातार चटक होता जा रहा है। वोटरों को लुभाने के लिए सभी हथकंडे अपनाये और हर छोटी-बड़ी घटना, हर बयान और हर फैसला अब चुनावी नजरिये से देखा जा रहा है कि इससे वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा। फिलहाल यादव बिरादरी और मुसलमान काफी हद तक समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन यूपी में ओवैसी की एंट्री से सपा को नुकसान भी हो सकता है. ठीक इसी तरह ब्राह्मण समुदाय जो हमेशा से भाजपा का मजबूत वोट बैंक रहा है, उसमें योगी सरकार के प्रति आक्रोश उबल रहा

असदुद्दीन ओवैसी

है. जिसमें हाल ही में एसआई की परीक्षा में ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित सवाल ने ब्राह्मणों की नाराजगी को और बढ़ाने में आग में घी डालने का काम किया है. अब यह सवाल सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि इसने योगी सरकार के प्रति ब्राह्मणों के गुस्सा को और भी बढ़ा दिया है। राज्य पुलिस भर्ती की दरोगा परीक्षा में पूछा गया वह सवाल अब पूरे समाज की भावनाओं को चोट पहुंचाने का प्रतीक बन गया है। सवाल था-'अवसर के अनुसार बदल जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है और उसके विकल्पों में पंडित शब्द को शामिल कर दिया गया'। एक सामान्य परीक्षा का सवाल जिसका मकसद सिर्फ ज्ञान जांचना था वह अब जाति विशेष को अवसरवादी बताने

बृजेश पाठक

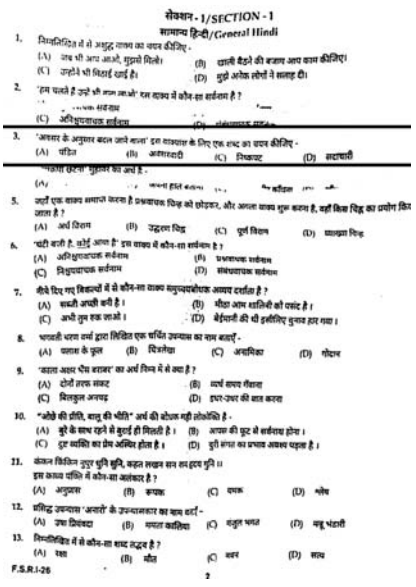

सेक्शन - 1/SECTION - 1
सामान्य हिन्दी/General Hindi

1. निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए -
(A) जब भी आप आओ, मुझसे मिलो। (B) खाली बैठने की बजाय आप काम कीजिए।
(C) उन्होंने भी मिठाई खाई है। (D) मुझे अनेक लोगों ने सलाह दी।

2. 'हम चलते हैं उन्हें भी साथ लाओ' इस वाक्य में कौन-सा सर्वनाम है ?
(C) अनिश्चयवाचक सर्वनाम

3. 'अवसर के अनुसार बदल जाने वाला' इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए -
(A) पंडित (B) अवसरवादी (C) निष्कपट (D) सदाचारी

5. जहाँ एक वाक्य समाप्त करता है प्रश्नवाचक चिह्न को छोड़कर, और अगला वाक्य शुरू करता है, वहाँ किस चिह्न का प्रयोग किया जाता है ?
(A) अर्ध विराम (B) उद्धरण चिह्न (C) पूर्ण विराम (D) व्याख्या चिह्न

6. "घंटी बजी है, कोई आया है" इस वाक्य में कौन-सा सर्वनाम है ?
(A) अनिश्चयवाचक सर्वनाम (B) प्रश्नवाचक सर्वनाम
(C) निश्चयवाचक सर्वनाम (D) संबंधवाचक सर्वनाम

7. नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन-सा वाक्य समुच्चयबोधक अव्यय दर्शाता है ?
(A) सब्जी अच्छी बनी है। (B) मीठा आम शालिनी को पसंद है।
(C) अभी तुम रुक जाओ। (D) बेईमानी की थी इसलिए चुनाव हार गया।

8. भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक चर्चित उपन्यास का नाम बताएँ -
(A) पलाश के फूल (B) चित्रलेखा (C) अनामिका (D) गोदान

9. 'काला अक्षर भैंस बराबर' का अर्थ निम्न में से क्या है ?
(A) दोनों तरफ संकट (B) व्यर्थ समय गँवाना
(C) बिलकुल अनपढ़ (D) इधर-उधर की बात करना

10. "ओछे की प्रीति, बालू की भीति" अर्थ की बोधक सही लोकोक्ति है -
(A) बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। (B) आपस की फूट से सर्वनाश होना।
(C) दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है। (D) बुरी संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है।

11. कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि ॥
इस काव्य पंक्ति में कौन-सा अलंकार है ?
(A) अनुप्रास (B) रूपक (C) यमक (D) श्लेष

12. प्रसिद्ध उपन्यास '[illegible]' के उपन्यासकार का नाम बताएँ -
(A) उषा प्रियंवदा (B) ममता कालिया (C) [illegible] (D) मन्नू भंडारी

13. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द तद्भव है ?
(A) रेखा (B) मौत (C) [illegible] (D) सत्य

F.S.R.I-26
2

योगी आदित्यनाथ

का हथियार बन गया। डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तुरंत इसकी निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी सवाल से किसी समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और कहा भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इसके दोषियों को पकड़ने के लिए जांच कमेटी भी बना दी गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी भर्ती बोर्डो को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी भी जाति पंथ या संप्रदाय की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बार-बार गलती करने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ क्षमा याचना और निर्देशों से काम चल जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण समाज की नाराजगी अब एक-दो घटनाओं तक नहीं रही। यह एक सिलसिला बन चुका है जो पिछले कई महीनों से लगातार जारी है।

दिसंबर 2025 में विधानसभा सत्र के दौरान जब भाजपा के कुछ ब्राह्मण विधायकों ने लखनऊ में बैठक की तो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने तुरंत सख्त चेतावनी दे दी। कहा गया कि जाति आधारित बैठक राजनीति पार्टी को मंजूर नहीं। लेकिन ठीक उसी साल अगस्त में ठाकुर विधायकों की बैठक हुई जिसमें चालीस

से ज्यादा नेता शामिल थे। वह बैठक पांच सितारा होटल में हुई और उसे कुटुंब परिवार का नाम दिया गया। लोध और कुर्मी विधायकों की बैठक भी हुई लेकिन उन पर कोई नोटिस नहीं दिया गया। कोई चेतावनी नहीं मिली। सपा और कांग्रेस ने इस दोहरे मानदंड पर तीखे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाजपा में ब्राह्मण विधायक एक जगह जुट भी नहीं सकते और न ही अपनी बात रख सकते हैं। यह ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर सवाल था जो आज भी गूंज रहा है फिर आया माघ मेला का विवाद। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पालकी पर सवार होकर स्नान के लिए जा रहे थे। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर रोका। धक्का-मुक्की हुई। शंकराचार्य के समर्थक बटुक ब्राह्मणों की चोटियां खींचने के आरोप पुलिस पर लगे। मामला इतना बढ़ा कि शंकराचार्य धरने पर बैठ गए और बिना स्नान किए लौट गए। सपा और कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। बृजेश पाठक ने अपने सरकारी आवास पर सौ बटुकों को सम्मानित किया लेकिन क्या यह कदम पर्याप्त था। समाज अभी भी कह रहा है कि प्रशासन ने शंकराचार्य

पंकज चौधरी

के साथ जो रवैया अपनाया वह अपमानजनक था।

फिर आई फिल्म घूसखोर पंडित। नेटफ्लिक्स पर मनोज बाजपेयी अभिनीत इस फिल्म का टीजर फरवरी 2026 में जारी हुआ। पुलिस अधिकारी को पंडित कहकर संबोधित किया गया। ब्राह्मण संगठनों ने देशभर में विरोध प्रदर्शन किए। यूपी में पोस्टर जलाए गए। सड़कों पर प्रदर्शन हुए। मामले ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने फिल्म रिलीज से पहले नाम बदलने का आदेश दिया और सीबीएफसी को नोटिस जारी किया। निर्माता नीरज पांडे को

शीर्षक बदलना पड़ा। ब्राह्मण समाज ने इसे साजिश बताया कि जानबूझकर एक समुदाय को भ्रष्ट और घूसखोर करार दिया जा रहा है। फिल्म का नया नाम अभी तक तय नहीं हुआ लेकिन समाज के दिल में जो चोट लगी वह अभी भी ताजी है। यूजीसी के नए नियमों ने भी सवर्ण समाज खासकर ब्राह्मणों को नाराज किया। दलित और ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के नाम पर बनाए गए नियमों को ब्राह्मणों ने अपने खिलाफ देखा। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने माघ मेले में शंकराचार्य शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार और यूजीसी नियमों को वजह बताया। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने यूजीसी एक्ट 2026 पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि नियम सामान्य वर्ग को टारगेट कर रहे हैं और सामाजिक बंटवारा बढ़ा सकते हैं। केंद्र को नए नियम बनाने के लिए कहा गया। लेकिन इस दौरान ब्राह्मण सड़कों पर उतरे सोशल मीडिया पर विरोध हुआ।

ये सारी घटनाएं एक के बाद एक आईं और हर बार सरकार को सफाई देनी पड़ी। हर बार डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। लेकिन ब्राह्मण समाज पूछ रहा है कि क्यों बार-बार उसकी भावनाओं की अनदेखी हो रही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों की संख्या दस प्रतिशत से ज्यादा है। 2017 के बाद से भाजपा को इनका 85 से 90 प्रतिशत वोट मिलता रहा है। यह परंपरागत वोट बैंक है जो पार्टी की रीढ़ रहा है। लेकिन 2017 के बाद ब्राह्मणों की शिकायत लगातार बढ़ी है। उन्हें पार्टी और सरकार में उचित सम्मान नहीं मिल रहा। उनकी बात नहीं सुनी जा रही। कुशीनगर के विधायक पी.एन. पाठक ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक में कर्तव्य और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की बात कही थी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की चेतावनी के बाद खामोशी छा गई। अब सपा इस नाराजगी को अपना हथियार बना रही है। उसके ब्राह्मण नेता लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं। ब्राह्मण समाज के संगठन खुलकर कह रहे हैं कि भाजपा ने उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा है लेकिन सम्मान नहीं दिया। ठाकुर कुर्मी लोध जैसे अन्य समुदायों की बैठकें बिना किसी रोक टोक के हो जाती हैं लेकिन ब्राह्मणों की बैठक पर तुरंत नोटिस। परीक्षा का सवाल पंडित को अवसरवादी बताता है। फिल्म का नाम घूसखोर पंडित रखा जाता है। माघ मेले में बटुकों के साथ बदसलूकी। यूजीसी नियम सामान्य वर्ग को निशाना बनाते हैं। ये सारे मुद्दे एक साथ जुड़कर ब्राह्मणों को यह अहसास दिला रहे हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है। 2027 के चुनाव में अगर ब्राह्मण वोट में सिर्फ पांच प्रतिशत भी कमी आई तो भाजपा के कई सीटों पर असर पड़ सकता है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में हैं। पार्टी के अंदर भी ब्राह्मण नेता चुपचाप असंतोष जता रहे

हैं। लेकिन ऊपर से कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा। सरकार को अब सिर्फ निर्देश जारी करने से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाने होंगे। ब्राह्मण संगठनों से संवाद बढ़ाना होगा। परीक्षा बोर्डों में सख्त निगरानी करनी होगी। फिल्म और मीडिया में जाति आधारित अपमान को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान मजबूत करने होंगे। यूजीसी जैसे मुद्दों पर संवेदनशीलता दिखानी होगी। ब्राह्मण समाज सदियों से ज्ञान विज्ञान और संस्कृति का संरक्षक रहा है। अवसरवादी या घूसखोर जैसे शब्दों से उसे जोड़ा जाना न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी। योगी सरकार ने विकास और कानून व्यवस्था पर जोर दिया है लेकिन अगर सामाजिक संतुलन बिगड़ गया तो पूरा प्रयास प्रभावित हो सकता है। ब्राह्मण नाराजगी अब सिर्फ भावनात्मक मुद्दा नहीं रह गया है। यह सियासी गणित का हिस्सा बन चुका है। अगर सरकार ने समय रहते इसे समझा और ठीक किया तो 2027 में यह खतरा टल सकता है। वरना यह बादल और घने होते जाएंगे और चुनावी मैदान में भारी पड़ सकते हैं। ब्राह्मण समाज की आवाज अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि चेतावनी का अलार्म बन चुकी है। सरकार को इसे अनसुना नहीं करना चाहिए।●

कांशीराम की विरासत पर सभी दलों की नजर

● **अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)**

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई प्रतीक ऐसे रहे हैं जिनकी विरासत समय-समय पर नई सियासी व्याख्या के साथ सामने आती है। बहुजन आंदोलन के प्रणेता कांशीराम भी ऐसे ही नेता हैं। 15 मार्च को उनकी जयंती हर साल बसपा मनाती रही है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी तक, लगभग सभी दल कांशीराम की राजनीतिक विरासत को अपने तरीके से याद कर रहे हैं। लखनऊ से दिल्ली तक कार्यक्रमों की श्रृंखला बन रही है, बहुजन संवाद की बातें हो रही हैं और पीडीए दिवस जैसे नए राजनीतिक नारे सामने आ रहे हैं। यह सब महज संयोग नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बदलते सामाजिक समीकरणों का संकेत भी है। दिलचस्प यह है कि कांशीराम की राजनीति का मूल आधार कांग्रेस विरोध से ही बना था। 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने जिस बहुजन राजनीति की नींव रखी, उसने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लगभग हाशिए पर पहुंचा दिया था। लेकिन अब वही कांग्रेस उनकी जयंती को परिवर्तन दिवस के रूप में मना रही है। 13 मार्च को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले कार्यक्रम में राहुल गांधी की मौजूदगी और बहुजन संवाद की योजना इसी कोशिश का हिस्सा है। कांग्रेस का तर्क है कि कांशीराम को किसी एक पार्टी के नेता के रूप में सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें सामाजिक न्याय की लड़ाई के बड़े प्रतीक के रूप में समझना चाहिए। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना और

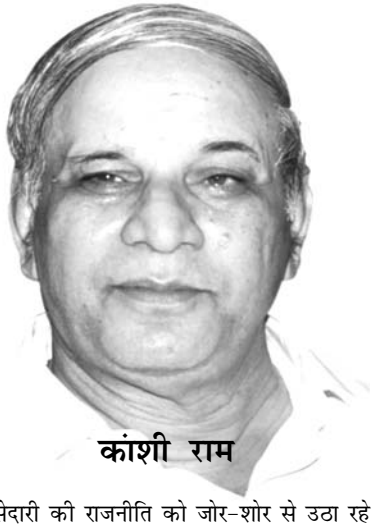

कांशी राम

हिस्सेदारी की राजनीति को जोर-शोर से उठा रहे हैं। कांशीराम के उस पुराने नारे जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी को कांग्रेस आज अपने राजनीतिक तर्क के रूप में सामने रख रही है।

समाजवादी पार्टी की रणनीति भी कम दिलचस्प नहीं है। अखिलेश यादव ने कांशीराम की जयंती को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह सिर्फ प्रतीकात्मक आयोजन नहीं है, बल्कि उस सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में आंशिक रूप से दिखाई दिया था। अखिलेश यादव को यह एहसास है कि सिर्फ यादव-मुस्लिम वोटों के सहारे बीजेपी को चुनौती

देना मुश्किल है। इसलिए पीडीए का फार्मूला दरअसल उस बड़े सामाजिक गठबंधन की तलाश है जिसमें दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक एक साझा राजनीतिक मंच पर आएं। कांशीराम की जयंती को इस रणनीति से जोड़ना इसी सोच का हिस्सा है, क्योंकि बहुजन राजनीति की अवधारणा में यही सामाजिक वर्ग सबसे अहम रहे हैं। बीजेपी भी इस पूरी बहस से अलग नहीं है। पार्टी ने दलित महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाने के लिए एक कैलेंडर तैयार किया है, जिसमें कांशीराम का नाम भी शामिल है। योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण के नेतृत्व में दलित समाज से संवाद बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने दलित समुदाय के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए कई प्रतीकात्मक और सामाजिक कार्यक्रम किए हैं। संत रविदास से लेकर बाबा साहेब आंबेडकर तक, दलित प्रतीकों को पार्टी अपने राजनीतिक विमर्श में शामिल कर चुकी है। ऐसे में कांशीराम का नाम भी इस सूची में जुड़ना स्वाभाविक माना जा रहा है। बीजेपी की रणनीति साफ है दलित समाज को यह संदेश देना कि उसकी राजनीति सिर्फ एक पार्टी की बपौती नहीं है। दरअसल, कांशीराम की विरासत को लेकर अचानक बढ़ी यह दिलचस्पी उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति से जुड़ी है। राज्य में दलित मतदाता लगभग 21 प्रतिशत हैं और अगर

अखिलेश यादव

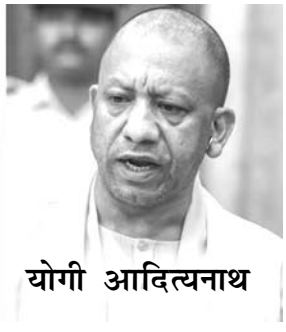

योगी आदित्यनाथ

अतिपिछड़े वर्ग को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 50 प्रतिशत के करीब पहुंच जाती है। कांशीराम ने इन्हीं वर्गों को राजनीतिक ताकत के रूप में संगठित करने का काम किया था। बसपा के उदय के साथ दलित राजनीति को पहली बार ऐसा मंच मिला जिसने सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाया। मायावती चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं और बहुजन राजनीति का एक नया अध्याय लिखा गया, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बसपा का जनाधार लगातार कमजोर होता गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद सीमित रहा। यही वह राजनीतिक खालीपन है जिसे भरने के लिए दूसरी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। सपा को लगता है कि दलित मतदाता अब नए विकल्प की तलाश में हैं और पीडीए फार्मूले के जरिए उन्हें अपने साथ जोड़ा जा सकता है। कांग्रेस भी इसी संभावना को देख रही है और सामाजिक न्याय की नई बहस के जरिए दलित-ओबीसी वर्गों से संवाद बढ़ाना चाहती है। बीजेपी के सामने चुनौती थोड़ी अलग है। पार्टी ने 2014 के बाद से दलित वोटों में उल्लेखनीय बढ़त हासिल की थी, लेकिन 2024 के चुनाव में कई जगहों पर इस समर्थन में हल्की दरार दिखी। इसलिए बीजेपी भी सामाजिक इंजीनियरिंग के जरिए दलित और अतिपिछड़े वर्गों को अपने साथ बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। कांशीराम जैसे प्रतीकों को याद करना उसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। असल सवाल यह है कि क्या कांशीराम की विरासत को सिर्फ राजनीतिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करना ही काफी होगा? कांशीराम ने जिस बहुजन राजनीति की कल्पना की थी, उसका मूल उद्देश्य सत्ता में भागीदारी और सामाजिक सम्मान था। उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों को यह एहसास कराया कि लोकतंत्र में संख्या भी ताकत होती है। उनकी राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति नहीं थी, बल्कि सामाजिक चेतना का आंदोलन भी थी।

आज जब अलग-अलग पार्टियां उनकी जयंती मनाने की होड़ में हैं, तब यह भी देखना होगा कि उनकी मूल सोच को कितनी गंभीरता से अपनाया जाता है। क्या यह सिर्फ वोटों की गणित है या सामाजिक न्याय की वास्तविक चिंता भी है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रतीकों का इस्तेमाल नया नहीं है। अक्सर नेता और दल किसी बड़े सामाजिक नायक की विरासत को अपने पक्ष में पेश करते रहे हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट अभी से सुनाई देने लगी है। सपा सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में है और कांग्रेस खोए हुए जनाधार को फिर से हासिल करना चाहती है। ऐसे में कांशीराम की विरासत एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गई है।लेकिन अंतिम फैसला हमेशा मतदाता ही करता है। यह वही मतदाता है जिसे कांशीराम ने कभी कहा था कि सत्ता की चाबी उसके हाथ में है। अब देखना यह है कि 2027 की लड़ाई में यह चाबी किसके ताले को खोलती है और किसकी राजनीति को नया रास्ता दिखाती है।●

असीम अरूण

आजम का समय खराब तो ...

अखिलेश का नये चेहरे पर दांव

● संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम मतदाता सदैव निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। करीब 125 सीटों पर इनका असर सीधे नतीजों को प्रभावित करता है, खासकर पश्चिमी इलाके में जहां मुस्लिम आबादी चालीस फीसद तक पहुंच जाती है। भाजपा को छोड़ अन्य सभी दल इन मतों को हथियाने के लिए होड़ लगाए रहते हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इस दौड़ में सबसे आगे दिखते हैं। जेल में बंद आजम खान से लेकर बसपा और कांग्रेस छोड़ हाल ही में पार्टी में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी तक पर वे दांव लगा रहे हैं, ताकि यूपी में मुस्लिम वोटों के एक और सौदागर ओवैसी की बढ़ती चुनौती का मुकाबला हो सके। आज हालात यह है कि जेल में बंद आजम खान की कमी सपा के लिए गहरी चोट साबित हो रही है, क्योंकि रामपुर से सहारनपुर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन 60 से अधिक सीटों पर उनका जादू बरकरार है जहां मुस्लिम मतदाता जीत हार तय करते हैं। जेल की चारदीवारी में बंद होते हुए भी उनके समर्थक बाहर चिल्ला रहे हैं, पश्चिमी इलाके के छह जिलों में मुस्लिम आबादी पैंतालीस फीसद से ऊपर होने के कारण वहां सपा का वोट बैंक डगमगाने लगा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस कमी को कितना भर पाएंगे, यह सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि बसपा से होते हुए कांग्रेस तक अपनी यात्रा में उन्होंने बुंदेलखंड के दर्जन भर जिलों में मुस्लिम मतों को संगठित करने का लोहा मनवा लिया है। हाल ही में 15 फरवरी को सपा में शामिल होने के बाद वे बुंदेलखंड की उन पचास सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी तीस फीसद के आसपास है, और पूर्व में बसपा के प्रमुख मुस्लिम नेता के रूप में उन्होंने वहां 17 विधायकों को जुटाया था।

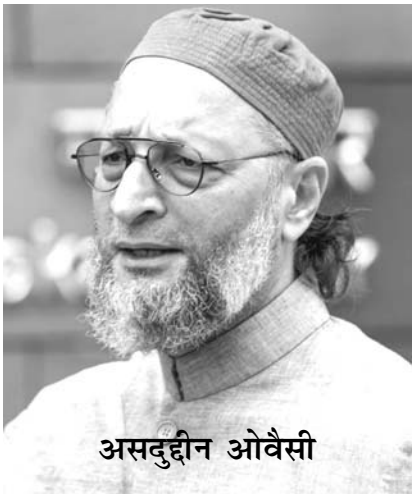

असदुद्दीन ओवैसी

नसीमुद्दीन की ताकत उनकी रणनीतिक चतुराई में है, जो आजम की जमीनी पकड़ से अलग लेकिन पूरक साबित हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम के खालीपन को वे पूरी तरह न भर सकें, क्योंकि वहां सहारनपुर से मुरादाबाद तक की 21 मुस्लिम बहुल सीटों पर आजम का नाम ही वोट जुटाता रहा है। लेकिन बुंदेलखंड में उनकी पैठ गहरी है, जहां झांसी, बांदा, चित्रकूट जैसे जिलों की 18 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं और नसीमुद्दीन ने बसपा काल में इनमें से आधे पर असर डाला था। सपा को कुल मिलाकर 150 सीटों पर फायदा हो सकता है, क्योंकि नसीमुद्दीन पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक 100 से अधिक सीटों पर मुस्लिम युवाओं को लुभाने का दावा कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी हर ग्राम पंचायत में 61 सदस्यीय समितियां गढ़ रही है, जो पश्चिमी इलाके की पचास सीटों पर सेंध लगा सकती है, लेकिन

इमरान मसूद

आशु मलिक

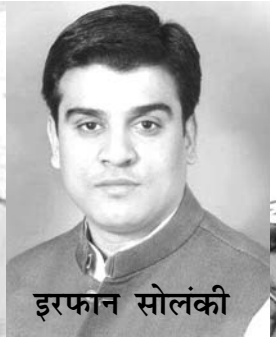
इरफान सोलंकी

नई उल सन

नफीस अहमद

नसीमुद्दीन का अनुभव इस खतरे को कम कर सकता है। सपा के अन्य मुस्लिम नेताओं द्वारा नसीमुद्दीन को स्वीकारना आसान नहीं होगा, क्योंकि पार्टी में पहले से इमरान मसूद जैसे सहारनपुर के दिग्गज हैं जिन्होंने पश्चिमी इलाके में दर्जन भर सीटों पर असर जमाया है। आशु मलिक जैसे नेता भी जिले के निकाय चुनावों में इमरान से टकरा चुके हैं, और सिसामऊ से इरफान सोलंकी तक सपा के 36 मुस्लिम विधायकों में आंतरिक खींचतान पुरानी है। नसीमुद्दीन को बुंदेलखंड संभालने का मौका मिला तो इमरान सहारनपुर की आठ सीटों पर असहज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का वोट बैंक ओवरलैप करता है। लेकिन अखिलेश की चतुराई से यह संतुलन बन सकता है, क्योंकि पिछले चुनावों में सपा ने 51 मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया था और नसीमुद्दीन जैसे चेहरे से वह संख्या सत्तर तक पहुंच सकती है।

आजम की कमी का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन 26 जिलों में सबसे ज्यादा दिखेगा जहां मुस्लिम आबादी 26 फीसद है और सपा को वहां 57 सीटें गंवाने का डर सता रहा है। नसीमुद्दीन इसकी भरपाई बुंदेलखंड से कर सकते हैं, जहां उन्होंने बसपा में 18 नेताओं को संगठित किया था और अब सपा के 17 पूर्व विधायकों के साथ मिलकर 40 सीटों पर दबदबा बना सकते हैं। ओवैसी का भूत सपा के सिर सवार है, क्योंकि उनकी पार्टी पंचायत स्तर पर बूथ मजबूत कर रही है और मुस्लिम युवाओं को छीनने की कोशिश में जुटी है, लेकिन नसीमुद्दीन का आना स प ा को सांस लेने का मौका देगा। शिवपाल सिंह यादव की जेल मुलाकातें आजम का आशीर्वाद दिला सकती हैं और अगर आजम ने हामी भरी तो नसीमुद्दीन को आगे बढ़ाया जाएगा। सपा की भाषा शैली अब बदल रही है, क्योंकि नसीमुद्दीन जैसे नेता मुस्लिम वोटों को जोड़ने के साथ जाट और पिछड़े समीकरण भी साधेंगे। उत्तर प्रदेश की कुल मुस्लिम आबादी पांच करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, जो 125 सीटों पर फैली हुई है। आजम के बिना पश्चिमी इलाके की उन 33 सीटों पर खतरा बढ़ गया जहां मुस्लिम तीस फीसद से ज्यादा हैं, लेकिन नसीमुद्दीन बुंदेलखंड की उन 27 सीटों से भरपाई करेंगे जहां उनका पुराना नेटवर्क काम आएगा। पार्टी के अन्य मुस्लिम चेहरों जैसे नईम उल हसन या नफीस अहमद स्वीकार करेंगे या नहीं, यह आंतरिक कलह पर निर्भर है, लेकिन इमरान मसूद की असहजता पहले ही सतह पर आ चुकी है।

नसीमुद्दीन सिद्दीकी एवं अखिलेश यादव

कुल मिलाकर नसीमुद्दीन, आजम की कमी का आधा भर सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में आजम का जादू अनोखा है जो 21 जिलों की 101 सीटों पर फैला है, जबकि नसीमुद्दीन बुंदेलखंड और पूर्वांचल की 100 सीटों पर मजबूत हैं। सपा के मुस्लिम नेताओं में कलह बरकरार रहेगी, क्योंकि सिकंदरपुर के जियाउर रिजवी से गोपालपुर के नफीस तक कई दावेदार हैं, लेकिन अखिलेश की रणनीति से संतुलन बनेगा। ओवैसी की आक्रामकता पश्चिमी इलाके में सेंध लगाएगी, लेकिन नसीमुद्दीन का सहारा सपा को मजबूत कर सकता है। योगी सरकार तुष्टीकरण पर हमला बोलेगी, पर अगर आजम का समर्थन मिला तो सपा बेदम नहीं पड़ेगी। इस जोड़ी की सफलता से सपा की कमर सीधी हो सकती है, वरना ओवैसी का डर हकीकत बन जाएगा। ●

बिहार के तीन प्रमुख विश्वविद्यालयों में अयोग्य, अनुभवहीन और भ्रष्टाचार के आरोपी कुलपतियों की नियुक्ति ने राज्य की उच्च शिक्षा को संकट के गर्त में धकेल दिया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल. चोंग्थू की संदिग्ध भूमिका इस पूरे तंत्र की धुरी है।

● **शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला**

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य-भारत में कुलपति नियुक्ति की विकृत होती व्यवस्था :- भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली, जो एक समय ज्ञान और शोध का केंद्र हुआ करती थी, आज गहरे संकट में है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक बार यह स्थापित किया है कि कुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विनियमनों के अनुसार ही होनी चाहिए, भले ही राज्यविधान कुछ भी कहे।

सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय (मार्च 2022)
किसी भी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति, चाहे राज्य विधान के अंतर्गत हो, UGC विनियमों के विरुद्ध नहीं हो सकती।
— Live Law

UGC के 2018 विनियमनों के अनुसार कुलपति पद के लिए न्यूनतम 10 वर्षों का प्रोफेसर स्तर पर या किसी मान्यता प्राप्त अनुसंधान/शैक्षणिक नेतृत्व में अनुभव अनिवार्य है। इसके बावजूद पूरे देश में और बिहार में विशेष रूप से कुलपति नियुक्तियाँ राजनीतिक और वित्तीय हितों की भेंट चढ़ रही हैं।

NAAC की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 36 में से केवल 8 विश्वविद्यालयों को ही NAAC मान्यता प्राप्त है और 940 में से केवल 161 महाविद्यालयों को यह आँकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की शिक्षा की दुर्दशा को उजागर करता है। इसी राष्ट्रीय संकट की पृष्ठभूमि में बिहार की कहानी और भी विचलित करने वाली है।

❖ **राजभवन के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल. चोंग्थू - एक विवादित IAS अधिकारी :-** बिहार के राज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में रॉबर्ट एल. चोंग्थू (IAS, बिहार कैडर 1997) एक अत्यंत शक्तिशाली पद पर आसीन हैं। कुलपति नियुक्ति से लेकर विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी करने तक, राज्यपाल सचिवालय के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी केंद्रीय भूमिका होती है।

रॉबर्ट एल. चोंग्थू

❖ **सहरसा शस्त्र लाइसेंस घोटाला, न्यायालय तक पहुँचा मामला :-** सहरसा जिले के जिलाधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल (2004) के दौरान चोंग्थू पर अयोग्य व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेंस देने का गंभीर आरोप लगा। जाँच में पाया गया कि उनके कार्यकाल के दौरान 229 व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेंस दिए गए, जिनमें से 14 के लाइसेंस फर्जी नाम-पते पाए जाने पर निरस्त किए गए।

पटना उच्च न्यायालय की फटकार

वर्ष 2022 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की अनुमति प्रदान की गई। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया था।

— Global Governance News, 26 मई 2022

बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 'Robert Lalchungnunga Chongthu Vs State of Bihar (2025 INSC 1339)' मामले में दो आधारों पर कार्यवाही निरस्त कर दी-पहला अभियोजन स्वीकृति में विवेक के प्रयोग का अभाव और दूसरा 15 वर्षों की असाधारण जाँच देरी से मौलिक अधिकार का उल्लंघन, किंतु यह तकनीकी निरस्तीकरण था, मेरिट पर निर्दोषता का प्रमाण नहीं।

महत्वपूर्ण तथ्य

सर्वोच्च न्यायालय ने अपनेनिर्णय दिनांक 20 नवंबर 2025 में सरकारी अभियोजन प्रक्रिया की खामियों को उजागर किया, न कि यह कहा कि आरोप असत्य थे। एक ऐसे अधिकारी को राजभवन जैसे संवैधानिक पद पर रखना, जिस पर स्वयं न्यायालय तक में अभियोजन की स्वीकृति दी जा चुकी हो, यह 'जीरो टॉलरेंस' नीति का उपहास है।

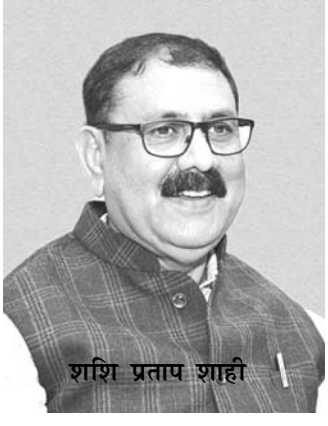

शशि प्रताप शाही

❖ **राजभवन में चोंग्थू की शक्ति और विश्वविद्यालय प्रशासन पर प्रभाव :-** फरवरी 2026 में चोंग्थू द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना के माध्यम से मगध विश्वविद्यालय के कुलपति शशि प्रताप शाही को सेवा विस्तार प्रदान किया गया, यह उसी अधिकारी द्वारा जिसका स्वयं का कार्यकाल विवादों से भरा है। सितंबर 2023 में चोंग्थू ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देशित किया कि वे 'राज्यपाल के निर्देशों के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण के दिशानिर्देशों का पालन न करें।'

❖ **वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के कुलपति डॉ. शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी :-** वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (स्थापना 1992) बिहार के भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास जिलों के लाखों छात्रों की उच्च शिक्षा का केंद्र है। आज यह विश्वविद्यालय अनेक गंभीर विवादों में घिरा हुआ है।

डॉ० शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी

❖ **धारा 420 का मुकदमा और फिर भी सेवा विस्तार :-** अगस्त 2022 में राजभवन ने डॉ. शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी को VKSU का कुलपति नियुक्त किया। यह नियुक्ति उस समय हुई, जब वे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU), मुजफ्फरपुर में प्रभारी कुलपति के रूप में कार्यरत थे।

प्राथमिकी दर्ज : दिनांक 06.10.2023

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के आदेश पर क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, तिरहुत प्रमंडल ने स्थानीय थाने में IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120(इ) (आपराधिक षड्यंत्र) एवं 34 (सामान्य आशय) के तहत प्राथमिकी संख्या-10/23 दर्ज कराई। — Deccan Herald, 6 अक्टूबर 2023 का आरोप :- VC शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और वित्तीय सलाहकार सहित, स्टेशनरी क्रय में लाखों रुपये की वित्तीय अनियमितता।

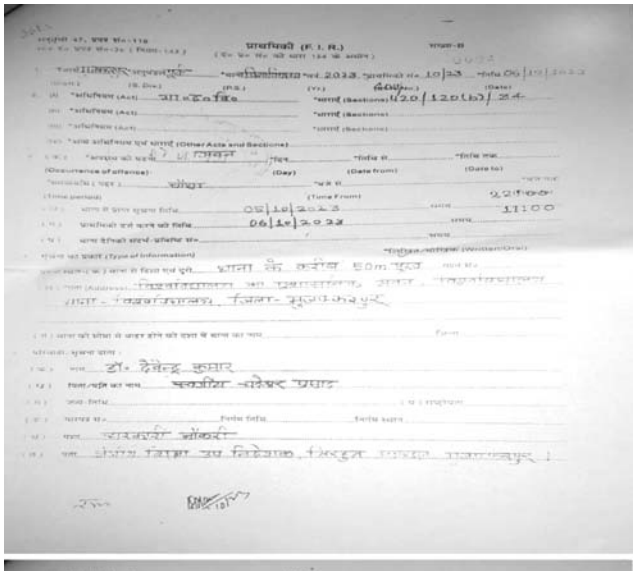

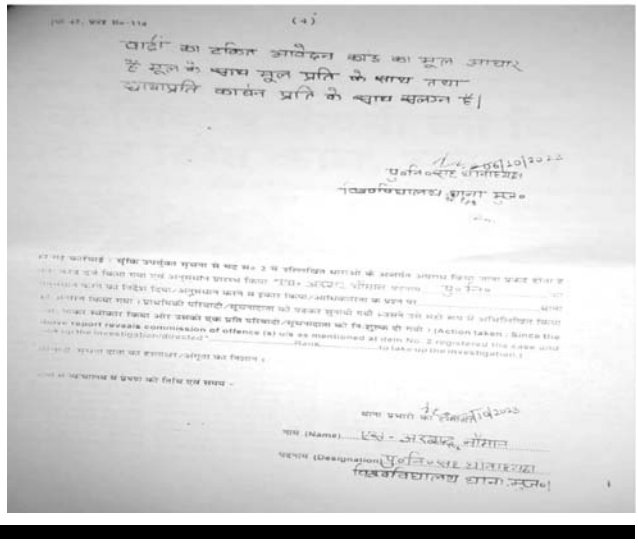

VEER KUNWAR SINGH UNIVERSITY
ARA- 802301 (BIHAR)
Statement of Fact

Regarding CWJC No. 21736 of 2018

Iqbal Ahmad ....Petitioner

Versus.

The State Of Bihar and Ors. ....Respondents.

Instructions are as follows:-

1. That the university took legal opinion from one of its panel lawyers with regard to claim of the petitioner. As per the legal opinion the following points came into light:-
   A. The provision a laid down under statute No. 34(3) (7) inserted by Memo No. 294 dated 29.01.1986 Bihar State Universities Act is as follows:-
   B. ***Sec. 10.0.0 of Statute 48 for career Advancement Scheme 20.07.2001 implemented w.e.f. 27.07.1998 which is regarding counting of past service, reads as follows:-***

      10.1.0. "Previous service without any break as a lecture or equivalent, in a University, College, National Laboratory or other scientific organizations of State / Central Government e.g. SCIR, ICAR, DRADO, UGC, ICSSR, ICHR, a UGC, Research Scientist and Research Associate shall be counted for Placement of lecturer in senior scale / selection Grade Subject to the following terms and conditions.

Statute no. 56 Amendment in the Statute for career Advancement Scheme dated 20.07.2001 implemented w.e.f. 27.07.98 was taken mode by the Hon'ble Chancellor vide letter no. 14/V-3-161/2002 Uche-28 dated 05.01.2006 and was pleased to amend para 10.1.0 of the said statute for incorporating the word "Constituent" before the word "College" in second line. The amended para 10.1.0 reads.

[1]

10.1.0 previous service without any break as a lecturer in a University, constituent college, National Laboratory or other scientific organization of State / Central Govt. e.g. SCIR, ICAR, DRADO, UGC, / ICSSR, ICHR, A UGC Research scientist and Research Associate shall be counted for Placement of lecturer in senior scale selection Grade Subject to the following terms and conditions.

2. That from reading of above noted provisions of the Statue it would be crystal clear that past service in any case cannot be counted in fixation of Inter se seniority. Provisions for counting of past service for the services rendered in other University of the State is only to grant pay protection and for granting retiral benefits etc but in any case not for granting seniority as per Statute Section 34 (3) (7) of the Statute chapter – I

3. That on the basis of the opinion the case of Dr. Iqbal Ahmad covered by the aforesaid provisions of the statute and his past service cannot be counted for granting promotion. **[A copy of Legal Opinion is dated 23.09.2018 is enclosed]**

4. That the writ petition has no merit and the same is fit to be rejected.

Registrar
V.K.S University, Ara

[2]

File No. 15/2023-144/2023 (Computer No. 298365)

(5)

है जबकि 22.03.21 को बिहार दिवस के अवकाश है। सो महाविद्यालय में वर्ग संचालन का आधार गया है जो आपत्ति को दर्शाता है। कुल कार्य दिवस 25 और कुल राशि 25000/भुगतान किया गया इसे स्पष्ट होता है कि महाविद्यालय के सक्षम पदाधिकारी द्वारा उपस्थिति पंजी की जाँच नहीं किया जा रहा है।

13 लेखा वर्ष 21–22 के नमुना जाँच मे पाया गया कि प्रधानाचार्य एस0 बी0 कॉलेज आरा के पत्रांक 171/AC/23 दिनाक 15.02.23 को डा0 श्वेता सिंह (Botony) एस0 बी0 कॉलेज आरा के अगस्त 22 का उपस्थिति पत्र उपलब्ध कराया गया जिसमे 20 दिन दर्शाया गया है जो पेज 05 पर है पेज 60 पर इनके द्वारा मैन्यूलन पजीपर 40 कलाश को दर्शाया गया है जिनका भुगतान 50.000/–रु0 किया गया है। पेज 27,28 पर बयोमेट्रीक अटेन्डेंट (उपस्थिति) अगस्त 22 में पाँच दिन है जबकि पेज 22 पर मैन्यूल उपस्थिति में 20दिन दिखाया गया है। इसे स्पष्ट होता है कि बिना कार्य वर्ग संचालन भूगतान किया गया है जो आपत्ति है।

14 आउट सोर्सिंग द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर कम ऑफिस असीसटेन्ट के एजेन्सी चयन के संबध मे:-

लेखा वर्ष 22–23 के नमुना जाँच में पाया गया की कम्प्यूटर आपरेटर कम ऑफिस असीसटेन्ट का आउट सोर्सिंग एजेन्सी Sixth Sense Seecrty &Mangement Solition Pvt Ltd का चयन किया गया [illegible] गया की निविदा संख्या 3/22 Man Power और House keeping के लिए निविदा निकाली गई जिसका प्रकाशन 11.08.22 को किया गया तकनीकि बीड 5.09.22 को एवं Financial Bid 10.10.22 को खोला गया, कम्प्यूटर आपरेटर कम ऑफिस असीसटेन्ट का Compertive Chart 3 एजेन्सी द्वारा दिखाया गया जिसमें Sixth Sense Seecrty &Mangement Soultion Pvt Ltd का कुल राशि प्रति माह–20962.32 जब Digital wave word (p)Ltd तथा Service Master Clen Ltd का प्रति माह राशि 18167.35 दिखाया गया है जो न्यूनतम है, लेकिन चयन समिति द्वारा Sixth Sense Seecrty &Mangement Solition Pvt Ltd का चयन किया गया निम्नतम निविदा को छोड कर उच्चतर निविदा का चयन किया गया संचिका मे आउट सोर्सिंग माध्यम से आवश्यक कम्प्यूटर आपरेटर की संख्या 40 [illegible] लेकिन चयन एजेन्सी एवं विश्वविद्यालय का Agreement म कुल 60 पद का जिक्र है।

5

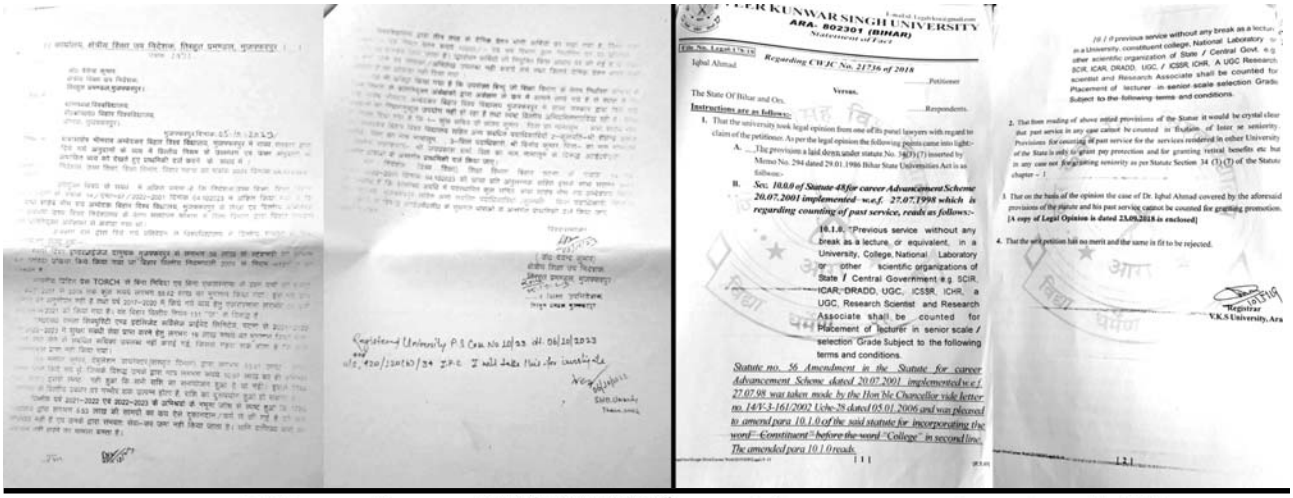

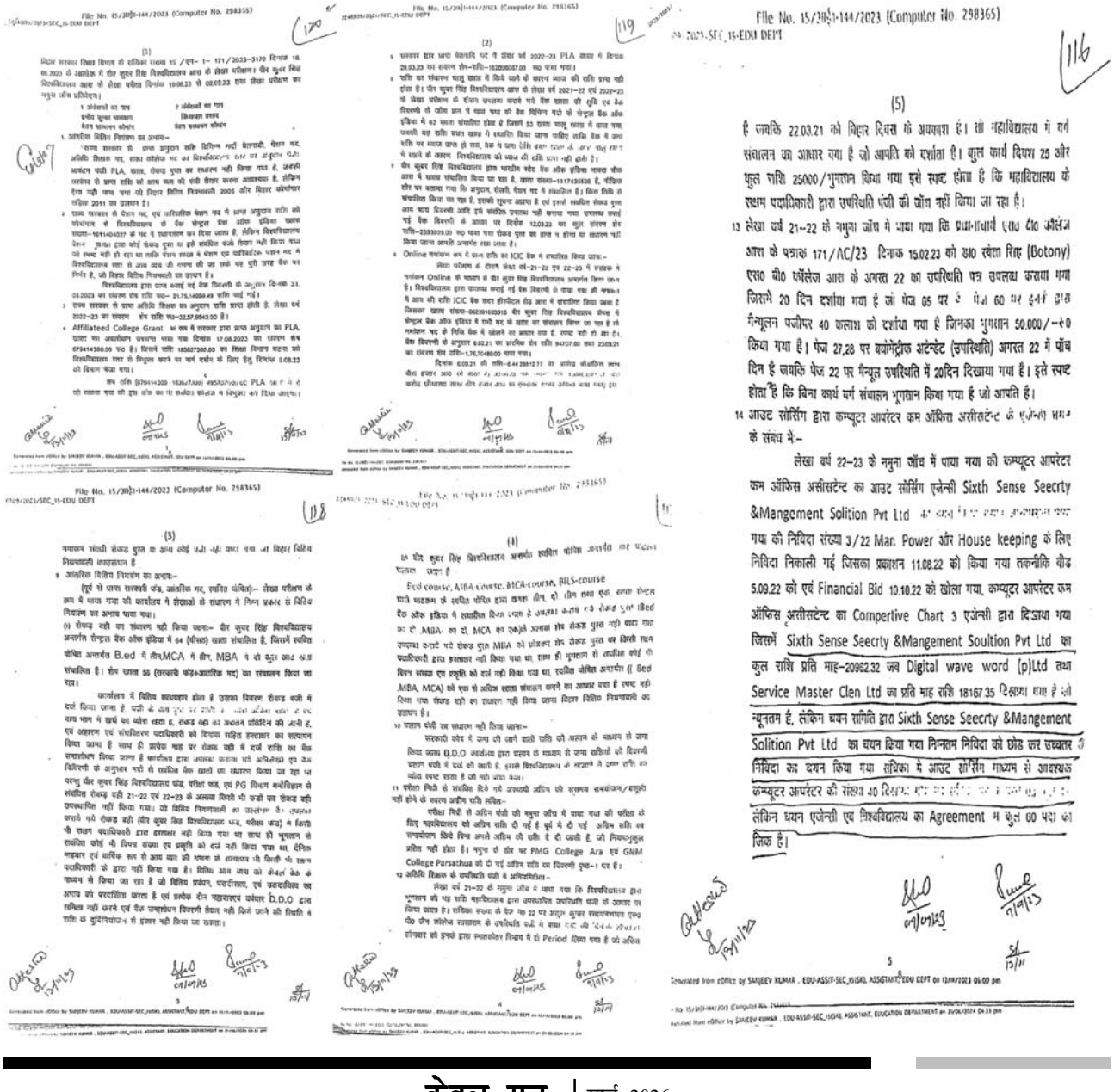

प्रो० डॉ० अनवर इमाम

❖ **चार्जशीटेड अभियुक्त को परीक्षा नियंत्रक, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़** :- VKSU की आधिकारिक वेबसाइट पर 'प्रो० डॉ० अनवर इमाम' का नाम 'Controller of Examinations' के रूप में अंकित है, यह तथ्य सार्वजनिक रूप से सत्यापनीय है। विशेष निगरानी इकाई (SVU), पटना ने केस संख्या-02/2021 में उनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है। राजभवन, पटना ने पत्रांक-2159, दिनांक-28.11.2025 के माध्यम से इस पर संज्ञान लिया और स्पष्टीकरण माँगा, फिर भी डॉ० इमाम आज भी पद पर बने हुए हैं।

चार्जशीटेड भ्रष्टाचारी को परीक्षा नियंत्रक बनाना, यह छात्रों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है।

❖ **ब्लैकलिस्टेड विक्रेताओं को निविदा, नियमों की खुली अवहेलना** :- VKSU ने पुस्तक आपूर्ति हेतु निविदा संख्या-1/2024 में मात्र 6 विक्रेताओं को आमंत्रित किया, जिनमें से 4 एक ही परिवार (जैन बंधु) से संबंधित हैं-इंडिका पब्लिशर्स, मेट्रो बुक्स, ऋषभ बुक्स और आदि बुक्स (सभी नई दिल्ली)। ये सभी संस्थाएँ मगध विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में पहले से ब्लैकलिस्टेड हैं।

❖❖ **16 वर्ष में NAAC मान्यता नहीं और करोड़ों का 'मरम्मत व्यय'** :- VKSU 16 वर्षों से NAAC मान्यता की प्रक्रिया में है, लेकिन अब तक मान्यता नहीं मिली। आरोप है कि जानबूझकर NAAC प्रक्रिया में देरी की जाती है, ताकि 'NAAC तैयारी' के नाम पर मरम्मत, रंग-रोगन और नवीनीकरण में करोड़ों रुपये बिना निविदा के खर्च किए जा सकें। यह वित्तीय विनियमों का सुनियोजित उल्लंघन है।

❖ **मगध विश्वविद्यालय, बोधगया : 4.96 करोड़ का ऑडिट घोटाला** :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या- 47/2024-25 ने मगध विश्वविद्यालय एवं उसके पाँच अंगीभूत महाविद्यालयों में व्यापक वित्तीय भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। फरवरी 2023 से मार्च 2024 तक की लेखा अवधि की जाँच में करोड़ों रुपये की अनियमितता उजागर हुई हैं।

कंडिका	विषय	राशि
कंडिका-1	फर्जी दस्तावेजों से चयनित संस्था को भुगतान	2.07 करोड़
कंडिका-2	बिना कार्य के CBCS पोर्टल एजेंसी को भुगतान	1.27 करोड़
कंडिका-3	GeM पोर्टल की अनदेखी एवं अधिक दर पर खरीद	1.62 करोड़
कुल हानि	सरकारी धन की कुल अनुमानित हानि	4.96 करोड़

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार,पटना

निरिक्षण प्रतिवेदन संख्या :- 47/2024-25

भाग-01

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया एवं पाँच चयनित अंगीभूत महाविद्यालय
2.	कार्यालय प्रधान का नाम	प्रो. शशि प्रताप शाही, कुलपति
3.	लेखा की अवधि	फरवरी 2023 से मार्च 2024 तक
4.	लेखापरीक्षा की तिथि	29 अप्रैल 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक (मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के साथ-साथ चयनित पाँच अंगीभूत महाविद्यालय)
5.	विस्तृत जाँच का माह	कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया: **मई 2023 एवं अगस्त 2023** एवं पाँच चयनित अंगीभूत महाविद्यालय 1. गया महाविद्यालय, गया: अगस्त 2023 एवं सितंबर 2021 2. एस. एस. महाविद्यालय, जहानाबाद: अगस्त 2023 एवं मार्च 2024 3. एस. सिन्हा महाविद्यालय, औरंगाबाद: जुलाई 2021 एवं सितंबर 2023 4. टी. एस. महाविद्यालय, हिसुआ: सितंबर 2023 एवं फरवरी 2023 5. ए. एम. महाविद्यालय, गया: अक्टूबर 2021 एवं अक्टूबर 2022
6.	प्रकाणितीय माह	-Do-
	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया का लेखा अवधि फरवरी 2023 से मार्च 2024 तक के लेखाओं के साथ-साथ चयनित पाँच अंगीभूत महाविद्यालय के लेखाओं का अनुपालन लेखापरीक्षा।
8.	क्या वित विभाग द्वारा कार्यालय का अंकेक्षण किया गया ?	नहीं
9.	महालेखाकार कार्यालय के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं कि समीक्षा कि गयी ?	उपलब्ध नहीं कराई गई।
10.	क्या कार्यालय प्रधान के साथ आपतियों पर विचार-विमर्श किया गया ?	हाँ, दिनांक 19.10.2024 को लेखापरीक्षा की आपतियों पर कुलसचिव से विचार-विमर्श किया गया।
11.	लेखा परीक्षा के दल सदस्य का नाम	श्री जानकी नन्दन, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी श्री गौतम कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री संजीय कुमार सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री विवेकानन्द पाठक, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री अजनवी नाथ गुप्त, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

दावा अस्वीकरण प्रमाण-पत्र

(Disclaimer Certificate)

यह निरिक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया एवं चयनित पाँच अंगीभूत महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार,पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

(The Inspection Report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the O/o Vice Chancellor, Magadh University, Bodhgaya and test checked five constituent colleges. The office of the Principal Accountant General (Audit), Bihar, Patna disclaims any responsibility for any misinformation on the part of the auditee unit.

1

भाग-II

(लेखापरीक्षा निष्कर्ष)

भाग –II (अ)

(महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष)

सन्दर्भ संख्या: OBS-1351506

कंडिका सं. :-1. विश्वविद्यालय द्वारा अनियमित तरीके से चयन कर संस्था को भुगतान रु. 2.07 करोड़।

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131ZI यह उल्लेखित करता हैं कि एक विभाग अर्थव्यवस्था और दक्षता के हित में कुछ सेवाओं को आउटसोर्स कर सकता है और यह निम्नलिखित बुनियादी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए बिना इस उद्देश्य के लिए विस्तृत निर्देश और प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकता है।

नियम 131ZD यह उल्लेखित करता हैं कि आमतौर पर तकनीकी और वित्तीय बोलियों को अलग-अलग सीलबंद करके 'दो-बोली' प्रणाली में सलाहकारों से प्रस्ताव मांगे जाने चाहिए। बोली लगाने वाले को इन दोनों सीलबंद लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखकर विधिवत सीलबंद करके निर्धारित स्थान पर निर्धारित तिथि एवं समय तक विभाग को जमा कराना होगा। तकनीकी प्रस्ताव प्राप्त होने पर सर्वप्रथम विभाग द्वारा निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर खोला जाये।

नियम 131ZJ यह उल्लेखित करता हैं कि विभागों को समान गतिविधियों में शामिल अन्य मंत्रालयों या विभागों और संगठनों से औपचारिक या अनौपचारिक पूछताछ, 'येलो पेज' और व्यापार पत्रिकाओं, यदि उपलब्ध हो, की जांच, वेबसाइट आदि के आधार पर संभावित और संभावित ठेकेदारों की एक सूची तैयार करनी चाहिए।

श्रम ठेकेदारों के माध्यम से काम की आउटसोर्सिंग करते समय प्रधान नियोक्ता द्वारा अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन अधिनियम) 1970 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम1948कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 195 और भारतीय अनुबंध अधिनियम,1872 का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

the Compliance under EPF & MP Act, 1952 के पैरा 5 में कहा गया है कि प्रधान नियोक्ता को निम्नलिखित सुनिश्चित करना है जिससे नियोजित कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की उनकी वैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन हो:

किसी भी अनुबंध को देने से पहले प्रधान नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ठेकेदार ईपीएफओ के साथ पंजीकृत है। ठेका देने के बाद, ईपीएफओ पोर्टल में ठेकेदार का विवरण दर्ज किया जाना चाहिए; ठेकेदार को देय भुगतान यह सत्यापित करने के बाद ही किया जाना चाहिए कि ईपीएफओ को वैधानिक पीएफ भुगतान किया गया है। यह या तो सीधे ईपीएफओ पोर्टल से सत्यापित किया जा सकता है या भुगतान करते समय ईपीएफओ पोर्टल से ठेकेदार को प्राप्त भुगतान रसीद द्वारा।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापन (नवंबर 2017) के संकल्प के अनुसार, आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों/ एजेंसियों आदि द्वारा आरक्षण नीति का पालन किया जाना था। राज्य में प्रचलित आरक्षण के प्रावधानों के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सेवा के उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया जाना था जो संबंधित विभाग और कार्यालय को सेवाएं प्रदान करता था। सेवा प्राप्त करने वाली संस्था/ कार्यालय/ विभाग आदि का यह भी दायित्व था कि सेवा प्रदाता एजेंसी से आरक्षण अनुपालन के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही कर्मचारियों की सेवा ली जानी थी।

कार्यालय मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के साफ-सफाई से संबन्धित बाह्य सेवा के लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि वर्तमान मे विश्वविद्यालय के अंतर्गत तथा इसके अधीनस्थ स्नातकोत्तर विभाग में बटेश्वर सेवा संस्थान, नाहर चौर, गोड्डा झारखंड द्वारा साफ सफाई का कार्य करवाया जा रहा है।

कार्यालय द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा सूचना ज्ञापांक R/66/2020, दिनांक 13.08.2022 के द्वारा निविदा प्रकाशित की गयी थी एवं निविदा की शर्तों के अनुसार प्रत्येक निविदा दाता को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी थी।

ISO 2000 के अंतर्गत निबंधन,
PF/ESI एवं GST में निबंधन,
सरकारी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सफाई कार्य का न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव,
सुरक्षा जमा राशि, राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत, 1 लाख का डिमांड ड्राफ्ट,
बिहार श्रम नियम के तहत निबंधन,
निविदा दाता द्वारा विगत तीन वर्षों का आकार रिटर्न एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन,
एजेंसी का टर्न ओवर विगत तीन वर्षों का औसत एक करोड़ से कम नहीं होना चाहिए एवं
सफाई हेतु सभी सामाग्री चयनित एजेंसी द्वारा प्रदान की जाएगी।

पुनः लेखापरीक्षा क्रम मे पाया गया कि तकनीकी निविदा में कुल पाँच एजेंसी ने भाग लिया एवं सभी को सफल माना गया तथा पुनः वित्तीय निविदा में उक्त पाँचों एजेंसी में से बटेश्वर सेवा संस्थान, नाहर चौर, गोड्डा झारखंड का L1 के रूप मे चयन किया गया एवं दिनांक 22.01.2021 को उक्त संस्थान को कार्य करने हेतु एकरारनामा करने का निर्देश प्रदान किया गया तथा एकरारनामा के पश्चात दिनांक 03.02.2021 को कार्यादेश निर्गत किया गया।

दिनांक 03.02.2021 से M/s बटेश्वर सेवा संस्थान, नाहर चौर, गोड्डा झारखंड प्रोजेक्ट मैनेजर शिवशंकर शर्मा, शिवपुरी, शास्त्रीनगर, पटना के साथ एकरारनामा किया गया एवं इस एकरारनामा मे निदिष्ट नियम एवं शर्तों में शर्त 01 के अनुरूप 18 माह की वैधता अर्थात जुलाई 22 तक वैध थी जिसे कार्य संतोषजनक होने पर बढाया जा सकता था एवं शर्त 10 के अनुसार साफ सफाई हेतु सभी आवश्यक सामाग्री एजेंसी को विश्वविद्यालय की तरफ से उपलब्ध करायी जानी थी। एकरारनामा के शर्त के अनुसार चयनित एजेंसी को एक पर्यवेक्षक एवं 05 सफाई मित्र की व्यवस्था करनी थी। जबकि कुल सफाई कर्मी का उल्लेख न तो निविदा मे एवं न ही एकरारनामा में किया गया था। तथा विश्वविद्यालय द्वारा स्थान का उल्लेख एक चार्ट

3

के माध्यम से चयनित एजेंसी को उपलब्ध कराया जाएगा जहाँ सफाई करनी है किन्तु एकरारनामा के साथ कोई चार्ट संलग्न नहीं था।

लेखापरीक्षा क्रम मे आगे पाया गया कि दिनांक 22.10.2022 को भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 03.08.2022 से 18 माह अर्थात जनवरी 2024 तक कार्य अवधि का विस्तार किया गया एवं वर्तमान अर्थात लेखा परीक्षा अवधि तक कार्य कराया जा रहा था।

लेखापरीक्षा अवलोकन : विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए संचिका (144/DSW/22 एंव part file 144/DSW/22) के लेखापरीक्षा में निम्न लेखा परीक्षा अवलोकन हैं।

तकनीकी एवं वित्तीय बोलियों के लिए अलग-अलग सीलबंद लिफाफों मे न होकर सभी पाँचों फार्म द्वारा एक ही सीलबंद लिफाफा मे समर्पित किया गया था।

तकनीकी निविदा में सभी पांचों फर्म को सफल घोषित किया गया था एवं वित्तीय निविदा में M/s बटेश्वर सेवा संस्थान, नाहर चौर, गोड्डा झारखंड का चयन किया गया किन्तु निविदा की शर्तों के अनुसार फर्म को ISO 2000 के अंतर्गत निबंधन प्राप्त करना अनिवार्य था। लेखापरीक्षा क्रम मे यह पाया गया कि चयनित संस्था के द्वारा ISO9001:2015 Certificate Number 1060828082M समर्पित किया गया था। उक्त certificate की online जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त certificate Number अस्तित्व में ही नहीं था अर्थात फर्जी ISO9001:2015 समर्पित किया गया था एवं समर्पित Certificate पर संस्था द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था।

निविदा शर्तों के अनुसार PF/ESI एवं GST में निबंधन अनिवार्य था। साफ-सफाई कार्य हेतु निविदा का प्रकाशन दिनांक 14.08.2020 को प्रेषित किया गया एवं तकनीकी निविदा में सभी फर्मों का सफल चयन दिनांक 30.08.2020 को ही कर लिया गया था। चयनित एजेंसी द्वारा EPFO कि राशि को कोड BRPAT2297204000 में कटौती कर जमा दिखाया जा रहा है जबकि श्रम विभाग द्वारा यह कोड दिनांक 06.02.2021 अर्थात तकनीकी निविदा के पाँच माह पश्चात् निर्गत किया गया था।

इसी प्रकार 30.08.2020 को ही सभी शर्तों को पूर्ण कर तकनीकी निविदा में सफल घोषित किए जाने वाली चयनित संस्था M/s बटेश्वर सेवा संस्थान विपत्र के द्वारा प्राप्त GST की राशि को GSTIN:10AAATB3844K2Z1 में जमा दिखा रही है जबकि प्रयुक्त GSTIN का रजिस्ट्रेशन दिनांक 30.07.2021 को अर्थात निविदा में चयन के 12 माह पश्चात निर्गत किया गया था।

निविदा की शर्त के अनुसार एजेंसी का टर्न ओवर विगत तीन वर्षों का औसत एक करोड़ से कम नहीं होना चाहिए था, जबकि चयनित फर्म द्वारा समर्पित आयकर रिटर्न में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में पैन संख्या AAATB3844K, जो की बटेश्वर सेवा संस्थान के नाम से निर्गत है का आय एवं टैक्स दोनों शून्य था अर्थात निविदा की मानक शर्तों के विरुद्ध था।

चयनित फर्म द्वारा समर्पित ठेका मजदूर (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम के धारा 12(1) के अधीन समर्पित लाइसेन्स भी वर्ष 2018 तक ही मान्य थी जबकि कार्य का आवंटन वर्ष 2020 में किया गया था। पुनः फर्म द्वारा समर्पित एक और लाइसेन्स PT/CLR/2021/01248 जो कि दिनांक 27.06.2021 अर्थात निविदा से चयन के करीब 10 माह पश्चात निर्गत किया गया था एवं इस निर्गत लाइसेन्स के Annexure

4

मे यह भी उल्लेखित था कि संस्था किसी भी दिन 50 से अधिक मजदूर को कार्य पर नहीं रख सकता एवं यह लाइसेन्स भी कार्यपालक अभियंता, BUIDCO दानापुर पटना हेतु निर्गत था।

वित्तीय निविदा में चयनित संस्था M/s बटेश्वर सेवा संस्थान, द्वारा प्रति सफाई कर्मी प्रतिमाह रु. 8732.10 (सभी सफाई सामाग्री, ईपीएफओ, ईएसआईसी, कंपनी का प्रशासनिक व्यय, प्रोफिट मार्जिन सहित) अंकित था तथा उसी वित्तीय निविदा मे अन्य फर्म शिवा प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड ने सभी उपरोक्त शर्तों के साथ रु. 8,383.38/- दर अंकित किया था। संचिका के लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि सर्वप्रथम विश्वविद्यालय द्वारा चयनित बटेश्वर सेवा संस्थान को वास्तविक उल्लेखित दर रु. 8732.10 ही comparative chart में दर्शाया गया एवं संस्था को सबसे अंत में L(V) घोषित किया गया परंतु पुनः एक और comparative Chart बनाकर M/s बटेश्वर सेवा संस्थान का दर रु. 8732.10 के जगह 8372.00 दिखाया गया एवं इस प्रकार इस फर्म को अन्य संस्था से कम दर्शाते हुए L(1) घोषित किया गया एवं फर्जी तरीके से इसे चयनित कर कार्यादेश प्रदान किया गया।

निविदा की शर्तों के अनुसार साफ-सफाई हेतु सभी आवश्यक सामाग्री यथा झाड़ू, फिनाइल, एसिड, फिनाइल गोली, ओडोनिल, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि की व्यवस्था चयनित एजेंसी द्वारा की जानी थी एवं चयनित एजेंसी बटेश्वर सेवा संस्थान ने भी अपना दर सभी साफ सफाई हेतु सामग्री मिलाकर ही दिया था किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा एकरारनामा में यह वर्णित कर दिया गया कि सभी साफ-सफाई सामग्री विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी।

वित्तीय नियमों एवं compliance Under EPF & MP Act 1952 के अनुसार एजेंसी को भुगतान करने से पूर्व ईपीएफओ भुगतान सत्यापन के पश्चात ही करना था किन्तु लेखापरीक्षा क्रम में पाया गया कि चयनित एजेंसी द्वारा मात्र मई, जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2021 का ही ईपीएफओ का भुगतान किया गया है जबकि शेष महीनों से संबन्धित EPFO भुगतान का चालान संलग्न नहीं है जिससे स्पष्ट होता था कि संस्था के द्वारा शेष महीनों का EPFO जमा किया बिना भुगतान प्राप्त किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा क्रम मे यह भी ज्ञात हुआ कि न तो निविदा मे एवं न ही एकरारनामा में कुल सफाई कर्मियों की संख्या का उल्लेख है एवं न ही साफ-सफाई के स्थलों का चार्ट ही उपलब्ध कराया गया किन्तु प्रत्येक माह 66 सफाई कर्मियों का भुगतान (नवम्बर 2021 में 64) जनवरी 2024 तक किया गया।

चयनित संस्था के साथ एकरारनामा में कार्य की वैधता 18 माह अर्थात जुलाई 22 तक थी जिसे भूतलक्षी प्रभाव में 22.10.2022 अर्थात बिना कार्य अवधि विस्तार के अगस्त 2022 से 21.10.2022 तक किया जा रहा था जबकि कार्य अवधि का विस्तार कार्य समाप्ती के पूर्व ही किया जाना था। इसी प्रकार दिनांक 22.10.2022 को कार्य अवधि विस्तार पत्र में दिनांक 03.08.2022 से 18 माह अर्थात जनवरी 2024 तक किया गया था किन्तु संस्था द्वारा लेखापरीक्षा अवधि तक बिना कार्य विस्तार के कार्य कराया जा रहा था।

चयनित एजेंसी द्वारा सरकारी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सफाई कार्य का 5 वर्षों का अनुभव संलग्न नहीं था।

चयनित एजेंसी द्वारा समर्पित बैंकर्स चेक जो दिनांक 26.08.2020 को निर्गत गया कि वैधता 3 माह ही थी एवं उसके पश्चात इसे revalidate नहीं किया गया था।

5

❖ **पूर्व कुलपति राजेंद्र प्रसाद : जेल और 20 करोड़ का घोटाला :-** वर्तमान कुलपति शशि प्रताप शाही के पूर्ववर्ती VC राजेंद्र प्रसाद, जो पहले VKSU के कुलपति भी थे, बिहार पुलिस की विशेष सतर्कता इकाई (SVU) की छापेमारी के बाद जेल में हैं। उन पर 20 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध खरीद का आरोप है। IPC की धारा 120B, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं शामिल हैं।

Times of India (फरवरी 2023)
मगध विश्वविद्यालय को गलत कारणों से चर्चा में रहने का इतिहास है। पूर्व VC राजेंद्र प्रसाद एक गबन मामले और अनुपातहीन संपत्ति के कारण जेल में हैं।

❖ **शशि प्रताप शाही : निविदा घोटाला और चोंग्थू के हस्ताक्षर से सेवा विस्तार :-** शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा गठित अंकेक्षकों की लेखा परीक्षण रिपोर्ट में निविदा घोटाले काठोस साक्ष्य है। न्यूनतम निविदा को दरकिनार कर उच्च निविदा का चयन, यह वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है। फरवरी 2026 में शशि प्रताप शाही का तीन वर्षीय कार्यकाल समाप्त हुआ, लेकिन राजभवन ने उन्हें सेवा विस्तार दिया और यह अधिसूचना जारी की खुद रॉबर्ट एल.चोंग्थू ने।

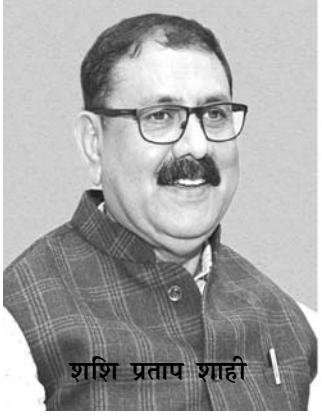

शशि प्रताप शाही

रॉबर्ट एल. चोंग्थू

❖ **ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा : नए कुलपति, पुरानी समस्याएँ :-** ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (LNMU) 1972 में स्थापित और मिथिला क्षेत्र के सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ा एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है। प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी को फरवरी 2024 में LNMU का कुलपति नियुक्त किया गया। उनका पूर्व पद भागलपुर राष्ट्रीय महाविद्यालय में 'Commissioned Principal' के रूप में था, जो विश्वविद्यालय प्रशासन में 10 वर्षीय अनुभव की अनिवार्यता को

प्रो० संजय कुमार चौधरी

प्रश्नांकित करता है।

LNMU में भी शिक्षकों की अनधिकृत नियुक्तियों, वित्तीय अनुशासनहीनता और RTI सूचनाएँ न देने की समस्याएँ सामने आई हैं।

LNMU को NAAC ने 'B Grade' दिया है, किंतु इस मान्यता को बनाए रखना वर्तमान प्रशासन की प्राथमिकता नहीं दिखती।

❖ **तुलनात्मक विश्लेषण : तीन विश्वविद्यालय, एक पैटर्न** :- नीचे दी गई तालिका तीनों विश्वविद्यालयों की स्थिति को एकत्रित रूप में प्रस्तुत करती है, जो एक स्पष्ट और चिंताजनक पैटर्न को उजागर करती है :-

विश्वविद्यालय / कुलपति	आरोप एवं अनियमितताएं	वर्तमान स्थिति
VKSU, आरा – शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी	FIR दर्ज (IPC 420, 120-B) | चार्जशीटेड परीक्षा नियंत्रक नियुक्त | UGC मानक का उल्लंघन	सेवा विस्तार प्रदान
मगध वि.वि., गया – शशि प्रताप शाही	लेखा परीक्षण में निविदा घोटाला | पूर्व VC जेल में | ₹4.96 करोड़की अनियमितताएं	सेवा विस्तार प्रदान
LNMU, दरभंगा – संजय कुमार चौधरी	10 वर्षीय वि.वि. अनुभव संदिग्ध | वित्तीय शिकायतें | RTI उल्लंघन	सेवा विस्तार प्रदान
NAAC मान्यता	VKSU – 16 वर्ष बाद भी नहीं | MU – विलंबित | LNMU – B Grade (जोड़िमर्म)	36 में से केवल 8 वि.वि. मान्यता प्राप्त

❖ **राष्ट्रव्यापी संकट : बिहार एक अपवाद नहीं, एक प्रतीक है** :- बिहार की स्थिति को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता। पूरे देश में राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच कुलपति नियुक्ति को लेकर टकराव जारी है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, सभी जगह यही संघर्ष है।

फरवरी 2025 में NAAC के 900 से अधिक Peer Reviewers को रिश्वतखोरी के आरोप में हटाया गया। A++ ग्रेड के बदले नकद, सोना, लैपटॉप और मोबाइल फोन लेने के आरोप। यह राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा व्यवस्था के सड़ने का प्रमाण है।

Scroll.in (मार्च 2025)

UGC और NAAC दोनों के इर्द-गिर्द के विवाद भारत की उच्च शिक्षा में एक गहरे संकट को प्रतिबिंबित करते हैं, जो नौकरशाही, अकुशलता, अप्रभावी ढाँचों और भ्रष्टाचार के आरोपों से चिह्नित है।

❖ **असली पीड़ित : बिहार का छात्र** :- इस पूरे भ्रष्ट तंत्र का सबसे बड़ा शिकार वे लाखों छात्र हैं जो इन विश्वविद्यालयों में दाखिला लेते हैं। NAAC मान्यता के अभाव में RUSA जैसी केंद्रीय योजनाओं से शोध अनुदान नहीं मिलता। चार्जशीटेड परीक्षा नियंत्रक के कारण परीक्षा फल और प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है।

योग्य शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती, क्योंकि नियुक्ति का आधार मेरिट नहीं, पैसा है। परिणामस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता गिरती है और छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ते हैं। सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे छात्र जो केवल सरकारी विश्वविद्यालयों पर निर्भर हैं, सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।

जब ज्ञान का मंदिर भ्रष्टाचार का केंद्र बन जाए, तो पहला नुकसान उस पहली पीढ़ी के छात्र को होता है जो परिवार में पहली बार कॉलेज में पढ़ने आया है।

❖ **दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार** :-

☞ माँग 5: कुलपति चयन समिति में UGC नॉमिनी की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। पूरी नियुक्ति प्रक्रिया सार्वजनिक डोमेन में हो।

☞ माँग 6: बिहार के विश्वविद्यालयों में NAAC मान्यता प्राप्ति के लिए समयबद्ध रोडमैप बनाया जाए।

☞ माँग 7: विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र विश्वविद्यालयलोकपाल की स्थापना हो।

❖ **उपसंहार : संविधान की परीक्षा** :- बिहार के विश्वविद्यालयों में जो हो रहा है वह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, यह संवैधानिक संकट है। राज्यपाल संवैधानिक दायित्व के वाहक हैं। उनका सचिवालय विश्वविद्यालयों का संरक्षक है, किंतु जब संरक्षक ही शोषक बन जाए तो व्यवस्था की रीढ़ टूट जाती है।

यह विडंबना है कि राज्यपाल सचिवालय एक ओर विश्वविद्यालयों को सुधार के पत्र लिखता है और दूसरी ओर उन्हीं विश्वविद्यालयों में भ्रष्ट और अयोग्य कुलपतियों को सेवा विस्तार देता है। यह 'दोहरा मानदंड' ही बिहार की उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा शत्रु है।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि UGC मानकों से नीचे की कोई नियुक्ति वैध नहीं, लेकिन जब तक व्यवस्था के भीतर से सुधार नहीं होगा, जब तक राजभवन का आचरण संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होगा, तब तक न्यायालय के आदेश भी पर्याप्त नहीं होंगे।

'जहाँ शिक्षक भ्रष्ट हो, प्रशासक अयोग्य हो और संरक्षक मौन हो, वहाँ केवल छात्र ही भुगतता है।'

❖ **परिशिष्ट : प्रमुख संदर्भ एवं दस्तावेज** :-

☞ प्राथमिकी संख्या 10/23, दिनांक 06.10.2023-BRABU मुजफ्फरपुर (IPC 420/120इ/34)।

☞ जनहित याचिका CW.J.C. 12504/2024-पटना उच्च न्यायालय (VKSU VC नियुक्ति)।

☞ CWJC/3647/2025, आदेश दिनांक-05.03.2025-पटना उच्च न्यायालय।

☞ राज्यपाल सचिवालय पत्रांक-बी.के.एस.यू.-20/2025-2159/रा.स.(I), दिनांक-20.11.2025 ।

☞ Robert Lalchungnunga Chongthu Vs State of Bihar, 2025 INSC 1339-सर्वोच्च न्यायालय।

☞ Magadh University VC Extension Notification (11/2022-172/GS-I), फरवरी 2026 ।

☞ Deccan Herald, 6 अक्टूबर 2023-BRABU FIR रिपोर्ट।

☞ CAG Performance Audit Report No. 5 of 2024-Bihar Universities

☞ NAAC Bribery Scandal, February 2025-Scroll.in

☞ UGC Regulations 2018 और 2025 (Draft)-न्यूनतम योग्यता एवं कुलपति नियुक्ति विनियम।●

● **डॉ0 ब्रह्मानंद राजपूत**

हम विश्व में लगातार कई वर्षों से अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते आ रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए घोषित इस दिन का उद्देश्य सिर्फ महिलाओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान बताना है। इसलिए इस दिन को महिलाओं के आध्यात्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नारी मानव जाति के लिए जननी का रूप है। कहा जाए तो जननी ही नारी है और नारी ही जननी है। नारी शक्ति या मातृशक्ति का इस संसार को आगे बढ़ाने में अहम् योगदान है। बिना नारी के इस दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर नारी नहीं होगी तो इस संसार का विकास नहीं हो पायेगा। नारी ही एक पुरुष को जन्म देती है, तभी नारी की सहन करने की शक्ति यानी सहनशक्ति का अहसास होता है कि वह इस संसार में कितनी मजबूत शक्ति है। आज उसी ही मजबूत नारी शक्ति पर कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त पुरुषों (ऐसे पुरुष जो नारी शक्ति को अपने उपभोग कि वस्तु समझते हैं) द्वारा बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं। ऐसे पुरुषों द्वारा नारी को शारीरिक शोषण द्वारा हमेशा लज्जित किया जाता है, यह चीज समस्त मानवजाति को शर्मसार करती है। कुछ पुरुषों के ऐसे कृत्यों द्वारा बाकी के साफ-सुथरी छवि के पुरुषों को भी शर्मसार होना पड़ता है। आज जरूरत है महिलाओं और छोटी छोटी बच्चियों के खिलाफ बलात्कार जैसी होनी वाली घटनाओं पर लगाम लगाई जाए। ये तभी हो सकता है जब बलात्कार जैसे कृत्यों के खिलाफ मानव जाति एकजुट होकर फैंसला ले और जो लोग दोषी पुरुषों का साथ देते हैं ऐसे लोगों का भी समाज पूर्ण रूप से बहिष्कार करे। इसके साथ ही आज जरूरत है कि बलात्कार जैसे कृत्यों के खिलाफ सरकारें एक कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करें और बलात्कार जैसे मामलों की फास्टट्रैक कोर्ट द्वारा त्वरित कार्यवाही हो। जिससे कि दूसरे लोग भी ऐसे कृत्य करने से पहले सौ बार सोचें। तभी मानव जाति और समाज के स्तर को उठाया जा सकता है।

आज अपने समाज में नारी के स्तर को उठाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं की आध्यात्मिक, शैक्षिक, सामजिक, राजनैतिक और आर्थिक शक्ति में वृध्दि करना, बिना इसके महिला सशक्तिकरण असंभव है। आज हर महिला समाज में धार्मिक रूढ़ियों, पुराने नियम कानून में अपने आप को बंधा पाती है। पर अब वक्त है कि हर महिला तमाम रूढ़ियों से खुद को मुक्त करे। प्रकृति ने औरतों को खूबसूरती ही नहीं, दृढ़ता भी दी है। प्रजनन क्षमता भी सिर्फ उसी को हासिल है। भारतीय समाज में आज भी कन्या भ्रूण हत्या जैसे कृत्य दिन-रात किए जा रहे हैं। पर हर कन्या में एक मां दुर्गा छिपी होती है। यह हैरत की बात है कि दुर्गा की पूजा करने वाला इंसान दुर्गा की प्रतिरूप नवजात कन्या का गर्भ में वध कर देता है। इसमें बाप, परिवार के साथ समाज भी सहयोग देता हैं। आज जरूरत है कि देश में बच्चियों को हम वही आत्मविश्वास और हिम्मत दें जो लड़कों को देते हैं। इससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। इसलिए जरूरी है कि इस धरती पर कन्या को भी बराबर का सम्मान मिले। साथ ही उसकी गरिमा भी बनी रहे। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को जागृत करें और हर स्त्री में यह शक्ति जगाएं ताकि वह हर विकृत मानसिकता का सामना पूरे साहस और धीरज के साथ कर सके। एक नारी के बिना किसी भी व्यक्ति जीवन सृजित नहीं हो सकता है। जिस परिवार में महिला नहीं होती, वहां पुरुष न तो अच्छी तरह से

जिम्मेदारी निभा पाते हैं और ना ही लंबे समय तक जीते हैं। वहीं जिन परिवारों में महिलाओं पर परिवार की जिम्मेदारी होती है, वहां महिलाएं हर चुनौती, हर जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाती है ओर परिवार खुशहाल रहता है। अगर मजबूती की बात की जाए तो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा मजबूत होती हैं क्योंकि वो पुरुषों को जन्म देती हैं।

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त भारत के मौलिक के मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत सभी को अनुच्छेद 14-18 के अन्तर्गत समानता का अधिकार दिया गया है। जो कि महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का अधिकार देता है। इसके अन्तर्गत यह भी सुनिश्चित किया गया है कि राज्य के तहत होने वाली नियुक्तियों और रोजगार के संबंध में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत दिये गया समानता का अधिकार भारतीय राज्य को किसी के भी खिलाफ लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। देष में महिलाओं के उत्थान और सशक्तीकरण को देखते हुए हमारे संविधान को 1993 में संशोधित किया गया। 73वें संशोधन के जरिये संविधान में अनुच्छेद 243ए से 243ओ तक जोड़ा गया। इस संशोधन में इस बात की व्यवस्था की गई कि पंचायतों और नगरपालिकाओं में कुल सीटों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी। इस संशोधन में इसकी भी व्यवस्था की गई कि पंचायतों और नगरपालिकाओं में कम से कम एक तिहाई चेयरपर्सन की सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित हों। पंचायती राज संस्थानों द्वारा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने में सकारात्मक कार्यवाही से महिलाओं के प्रतिनिधित्व में तेजी से वृद्धि हुई है। वास्तव में देखा जाए तो देषभर में पंचायतों में चुनी गई महिलाओं का प्रतिनिधित्व 40 प्रतिशत हो गया है। कुछ राज्यों में पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है। बिना प्रतिनिधित्व के महिलाओं का सशक्तीकरण असंभव है। जब तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा तब तक हम महिलाओं के सशक्तिकरण की कल्पना नहीं कर सकते।

नए संसद भवन में 20 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पास हुआ था। लोकसभा में पास होने के बाद 21 सितंबर 2023 को यह नारी शक्ति वंदन विधेयक राज्यसभा से भी पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। आने वाले सालों में कानून के अमल में आने बाद लोकसभा और विधानसभा में बहुत कुछ बदल जाएगा। लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सबसे बडी कमी है कि इसके अन्तर्गत पिछडे और आदिवासी वर्ग की महिलाओं को अलग से कोटा नही दिया गया है। अगर इसके अन्तर्गत पिछडे और आदिवासी वर्ग की महिलाओं को अलग से कोटा दिया जाता तो पिछडे और दबे कुचले वर्ग की महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी आने वाले सालों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में बढ पाता। इसके लिये सरकार को नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके अन्तर्गत पिछडे और आदिवासी वर्ग की महिलाओं के लिये कोटे की व्यवस्था आने वाले समय में करनी चाहिये। कोई भी राष्ट्र महिलाओं के बिना शक्तिहीन है। क्योंकि राष्ट्र को हमेशा से महिलाओं से ही शक्ति मिलती है। किसी भी जीवंत और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी से लोकतंत्र की जडें मजबूत होती है।

आज जरूरत है कि समाज में महिलाओं को अज्ञानता, अशिक्षा, कूपमंण्डुकता, संकुचित विचारों और रूढिवादी भावनाओं के गर्त से निकालकर प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए उसे आधुनिक घटनाओं, ऐतहासिक गरिमामयी जानकारी और जातीय क्रियाकलापों से अवगत कराने के लिए उसमे आर्थिक ,सामजिक, शैक्षिक, राजनैतिक चेतना पैदा करने की। जिससे की नारी पुरुषों के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर समाज को आगे बढाने में सहयोग कर सके। साथ-साथ आज जरूरत है कि समाज कि जितनी भी रूढिवादी समस्याएं हैं हमें उनका समाधान खोजते हुए हटधर्मिता त्यागकर शैक्षिक, सामजिक, सोहाद्पूर्ण, व्यावसायिक और राजनैतिक चेतना का मार्ग प्रशस्त करते हुए महिलाओं के सामजिक उत्थान का संकल्प लेना चाहिये। क्योंकि हजारों मील की यात्रा भी एक पहले कदम से शुरू होती है। सही मायने में महिला दिवस तब सार्थक होगा जब असलियत में महिलाओं को वह सम्मान मिलेगा जिसकी वे हकदार हैं। इसके साथ ही समाज को संकल्प लेना चाहिए कि भारत में समरसता की बयार बहे, भारत के किसी घर में कन्या भ्रूण हत्या न हो और भारत की किसा भी बेटी को दहेज के नाम पर न जलाया जाये। विश्व के मानस पटल पर एक अखंड और प्रखर भारत की तस्वीर तभी प्रकट होगी जब हमारी मातृशक्ति अपने अधिकारों और शक्ति को पहचान कर अपनी गरिमा और गौरव का परिचय देगी और राष्ट्र निर्माण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाएंगी।

● **(स्वतंत्र लेखक का आलेख)**

फर्जी ऐप बनाकर कारोबारी से करोड़ों की ठगी

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

ऑनलाइन शॉपिंग ने लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन साइबर ठग यहाँ भी अपनी सेंध लगा चुके हैं। हाल ही में चंडीगढ़ की एक महिला ने डैमेज प्रोडक्ट के रिफंड के लिए गूगल पर कस्टमर केयर नंबर सर्च किया। इसके बाद वह स्कैमर्स के जाल में फंस गई। ठगों ने रिफंड प्रोसेस का झांसा देकर महिला के खाते से 80 हजार रुपए उड़ा लिए।

शेयर बाजार में कम समय में दोगुना-तिगुना मुनाफा दिलाने का लोभ देकर पटना के एक कारोबारी से 2.25 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपित खुद को पीड़ित बता कर साइबर थाने में फर्जी एफआईआर दर्ज कराने पहुंचा था, लेकिन जांच में सच्चाई सामने आने के बाद उसे थाने से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पीडित कारोबारी राजकिशोर कुमार सिंह ने 5 फरवरी को साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। एफआईआर के अनुसार उन्होंने लगभग डेढ़ महीने के भीतर 30 ट्रांजेक्शन के जरिये आर.टी.जी.एस. से करीब 2.25 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये थे। जब पीड़ित ने मुनाफे की राशि लौटाने का दबाव बनाया और शिकायत की चेतावनी दी तो आरोपित खुद को बचाने के लिए नयी चाल चली। वह साइबर थाने पहुंचा और खुद को ठगी का शिकार बताते हुए फर्जी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करने लगा। गिरफ्तार आरोपित की पहचान दानापुर निवासी 21 वर्षीय विकास कुमार विपुल के रूप में हुई। जांच में खुलासा हुआ है कि उसने 'इंडिया बोल्ट प्लस' समेत कई फर्जी निवेश एप तैयार कर रखे थे, जिनके जरिये वह लोगों को शेयर बाजार में निवेश का झांसा देता था। आरोपित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों से संपर्क करता था और खुद को शेयर बाजार का विशेषज्ञ बताता था। शुरुआत में वह छोटी रकम पर फर्जी मुनाफा दिखाकर विश्वास जीतता, फिर बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रेरित करता था। साइबर सेल को पहले से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस को संदेह हुआ। तकनीकी जांच में मोबाइल नंबर, बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड सामने आ गया। जांच में स्पष्ट हो गया कि वही युवक निवेश के नाम पर ठगी का मास्टरमाइंड हैं। इसके बाद पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले में साइबर थाना के डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि आरोपित संगठित तरीके से ठगी कर रहा था। पुलिस, बैंक

कैंप लगाकर साइबर अपराधियों ने खुलवाये खाते
3.50 करोड़ का किया ट्रांजेक्शन

बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में शौचालय बनाने और मरम्मत योजना के नाम पर एक बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने गाँवों में कैंप लगाकर ग्रामीणों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने का झांसा दिया और तीन बैंको में करीब 360 खाते खुलवा लिये, इसके बाद उनके पासबुक, एटीएम कार्ड व सिम कार्ड अपने कब्जे में रख लिये। अब इन खातों के माध्यम से पिछले छः महीने में लगभग 3.50 करोड रुपये का संदिग्ध लेन-देन होने की बात सामने आयी है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ग्रामीण साइबर थाना पहुँचे और शिकायत दर्ज करायी। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गयी है। ग्रामीणों के अनुसार बदमाशों ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि तीन-चार महीने के अंदर ही सरकार की ओर से शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये और मरम्मत के लिए छः हजार रुपये खाते भेजे जाएंगें। इसी लालच में कई लोगों ने खाते खुलवा लिए। शौचालय योजना की राशि दिलाने के नाम पर झांसे में लोग आ गये। बख्तियारपुर इलाके के ग्रामीण साइबर थाना पहुंच कर मामला दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि ये खाते केनरा बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में खुलवाये गए हैं।

ग्रामीणों के अनुसार सैदपुर गांव के अवध राम एक महिला के साथ आये थे और उन्होंने शौचालय योजना को लेकर स्कीम बताये और खाता खुलवाने को कहा। जगदम्बा मंदिर के के पास कैंप में लोगों से आधार कार्ड की तीन कॉपी और छः पासपोर्ट फोटो लिए गए। इसी आधार पर केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में खाते खोले गये। खातों से जुड़े एटीएम व सिम कार्ड भी शातिरों ने अपने पास रख लिए। अवध राय का कहना है कि नरौली की सीता कुमारी ने खुद को बैंककर्मी बताकर उन्हें भी झांसे में लिया था और अब सीता का मोबाइल बंद आ रहा है। पीड़ितों द्वारा खाता बंद कराने की मांग की जा रही है। उक्त घटना के बारे में साइबर थाना के डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया से बात की गई, जिनके सवाल और जवाब इस प्रकार हैं :-

❖ **साइबर शातिरों ने कई गांवों में कैंप लगाकर खाता खोल करोड़ों के ट्रांजेक्शन करवाया, क्या कार्रवाई हुई इस मामले में?**

मुझे यह सूचना मिली है। यह गंभीर मामला है। बड़े पैमाने पर कैंप लगा कर खाता खोलना गंभीर मामला है। सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जाँच की जा रही है।

❖ **क्या इसमें किसी बैंक कर्मी की मिलीभगत है, क्योंकि धडल्ले से बड़े पैमाने पर खातों का खुलना इस दिशा की ओर संकेत देता है?**

बख्तियारपुर थाने की पुलिस और ग्रामीणों से जानकारी ली जाएगी। जब इतने बड़े पैमाने पर खाता खुलवाये जा रहे थे तब बैंककर्मी ने क्यों जाँच नहीं की। सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक जाँच की जा रही है।

❖ **इस मामले में ग्रामीणों पर भी केस दर्ज होगा और कार्रवाई होगी?**

साइबर थाने के पदाधिकारियों द्वारा इसकी संघनता से जाँच की जा रही है। सभी पदाधिकारी मुस्तैदी से इसकी जाँच में जुट गए है। अगर साइबर अपराधियों के साथ ग्रामीणों की कोई भी संलिप्तता पायी जाती है तब निःसंदेह ग्रामीणों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खातों और डिजिटल डिजिटल ट्रेल के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। गिरफ्तारी के बाद विकास कुमार विपुल को जेल भेज दिया गया है। उसके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक दस्तावेज और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किये गये हैं। साइबर थाने की पुलिस ने कमीशन के बदले बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले तीन शातिरों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने जक्कनपुर के संजय पाठक, बाकरगंज के शब्बीर खान और शुभम कुमार को गिरफ्तार किया है। तीनों साइबर गिरोह को अपने करंट और बिजनेस अकाउंट में 15 प्रतिशत कमीशन पर उपलब्ध कराते थे। पुलिस ने आरोपितों के खाते जब्त कर लिये लिये हैं और कई अन्य सदिग्ध बैंक खातों की भी जानकारी जुटायी है। सभी खातों के ट्रांजेक्शन डिटेल संबंधित बैंकों से मांगें गये हैं।

जांच में सामने आया कि शुभम कुमार के खाते में विभिन्न राज्यों हुई साइबर ठगी के 1.52 करोड़ रुपये ट्रॉसफर किये गये थे। उसके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में 21 मामले दर्ज हैं। वहीं, शब्बीर खान के खाते में करीब 35 लाख रुपये और संजय पाठक के खाते में 25 लाख रुपये ट्रांसफर हुए। शब्बीर के खिलाफ 16 मामले, जबकि संजय के खिलाफ दो मामले दर्ज हैं। साइबर अपराधी ठगी की रकम इन खातों में भेजते थे। इसके बाद आरोपित 15 प्रतिशत कमीशन काट कर शेष राशि गिरोह द्वारा बताये गये अन्य खातों में ट्रांसफर कर देते थे। साइबर थाना के डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि तीनों आरोपित संगठित साइबर गिरोह से जुड़े हैं। गिरोह के सरगना की पहचान कर ली गई हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जांच मे भी सामने आया है कि आरोपितों के खिलाफ गुजरात, महाराष्ट्र तमिलनाडु और दिल्ली सहित कई राज्यों में मामले दर्ज हैं।●

मसौढ़ी एसडीएम की अध्यक्षता में ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती

● **श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव**

मसौढ़ी शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। इस पर रोक लगाने के लिए अनुमंडल प्रशासन सख्त रूप अपनाया है। बीते दिनों अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। बैठक में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सोनाली, अनुमंडल कार्यपालक दंडाधिकारी धर्मवीर कुमार, विधि विशेषज्ञ जय शिव सत्यानंद, मसौढ़ी और पुनपुन के सभी थानाध्यक्ष, कार्यापालक पदाधिकारियों समेत बीडीओ एवं अन्य विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी इस बैठक में रही। एस.डी.एम. ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी निर्देशित किया गया कि स्कूलों की दीवारों पर 'नो हॉर्न' और 'साइलेंस जोन' के पोस्टर व लेखन अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। वहीं अस्पताल प्रबंधन को भी परिसर के बाहर 'नो हॉर्न' बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। मसौढ़ी में संचालित सभी कम्युनिटी हॉल और मैरिज हॉल संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण, विद्युत सुरक्षा, फायर ब्रिगेड और यातायात जोन से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया गया है। नियमों के विपरीत संचालन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पूरी तरह प्रतिबंधित है। एस.डी.एम. ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य, नींद और दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, जिससे वे मानसिक रूप से काफी प्रभावित करता हैं। नियमों के अनुसार अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। दिन में भी ध्वनि का ऐसी उपयोग या संगीत बजाने पर रोक है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो। इस बैठक में यह भी मुद्दा उठा कि टेम्पो और ई-रिक्शा में तेज आवाज में गाने बजाए जाते हैं, जिससे यात्रियों खासकर महिलाएँ बहुत ही असहज हो जाती है और उन्हें काफी असुविधा होती है। प्रशासन के लिए ऐसे मामलों में भी कार्रवाई का निर्देश दिया है। एस.डी.एम. ने स्पष्ट कहा है कहा कि ध्वनि प्रदूषण कोई मामूली विषय नहीं है। इसे नियंत्रित करने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी करेगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।●

मसौढ़ी एसडीएम और सीओ सुस्त

पांच सालों में भी जमीन नापी नहीं करके उलझाया गया जमीनी विवाद

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

नक्सल प्रभावित लंबे अरसों से रहा मसौढ़ी अब जमीनी विवाद में उलझ के रह गया है। यहाँ मसौढ़ी एसडीएम और सी.ओ. इतने सुस्त हैं कि पाँच वर्षों में भी जमीनी विवाद को नहीं सुलझाया जाता है। बिहार में हत्या के ज्यादातर मामलों में जमीनी विवाद ही रहता है लेकिन थाना, प्रखण्ड स्तर और अनुमंडल स्तर के लचर व्यवस्था के कारण जमीनी विवाद को नहीं सुलझाया जाता है। आखिर इनकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा? भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के फटकारों के बाद भी भ्रष्टाचार इस कदर सिस्टम के रग-रग में समा चुका है कि बिना पैसे दिए थाना और प्रखंड में काम तक नहीं होता है। मसौढ़ी थानाध्यक्ष रहे रंजीत कुमार रजक के खिलाफ भी केवल सच पत्रिका में उनके काले करतूत को विस्तार से समाचार छापा गया था।

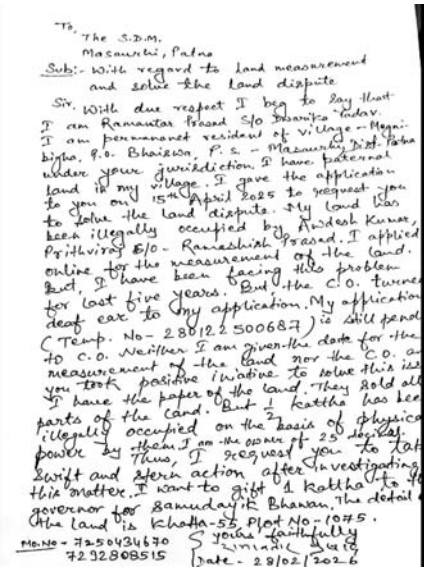

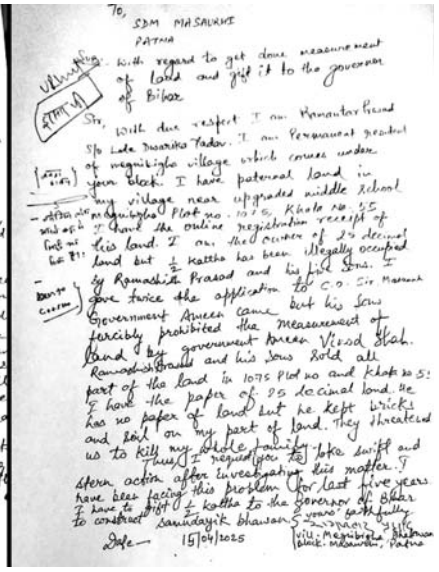

विदित हो कि मेघनीबिगहा ग्राम के रहनेवाले रामावतार प्रसाद के जमीन पर दबंगों का कब्जा पिछले पाँच वर्षों से है। आवेदक ने मसौढ़ी सी.ओ., मसौढ़ी एस.डी.एम. के पास कई बार आवेदन देकर इस मामले को सुलझाने का आग्रह किया। जमीन मापी के लिए आये सरकारी अमीन को भी कई बार गाली गलौज और डरा-धमका कर भगा दिया गया। आखिर कौन निष्पक्ष मापी कराके इस जमीन विवाद को सुलझाएगा? यह एक यक्ष प्रश्न है। जमीन पर मिट्टी भरकर ईंट रखकर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इस अवैध कब्जे को अभी तब मापी कराके नहीं हटाया गया है। पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि अदालतों में बहुत सारे लंबित मामले हैं और केसों को बोझ

To,
The S.D.M.
Masaurhi, Patna
Sub:- With regard to land measurement and solve the land dispute
Sir. With due respect I beg to say that I am Ramautar Prasad S/o Dwarika Yadav. I am permanent resident of village - Megni-bigha, P.O. Bhairwa, P.S. - Masaurhi, Dist. Patna under your jurisdiction. I have paternal land in my village. I gave the application to you on 15th April 2025 to request you to solve the land dispute. My land has been illegally occupied by Awdesh Kumar, Prithviraj S/O - Ramashish Prasad. I applied online for the measurement of the land. But, I have been facing this problem for last five years. But the C.O. turned deaf ear to my application. My application (Temp. No - 280122500687) is still pending to C.O. Neither I am given the date for the measurement of the land nor the C.O. and you took positive iniative to solve this issue. I have the paper of the land. They sold all parts of the land. But ½ kattha has been illegally occupied on the basis of physical power by them. I am the owner of 25 decimal. Thus, I request you to take swift and stern action after investigating this matter. I want to gift 1 kattha to the governor for Samudayik Bhawan. The detail of the land is Khatta-55 Plot No-1075.
Mo. No - 7250434670
7292808515
Yours faithfully
Date - 28/02/2026

To,
SDM MASAURHI
PATNA
Sub:- With regard to get done measurement of land and gift it to the governor of Bihar
Sir,
With due respect I am Ramautar Prasad S/o Late Dwarika Yadav. I am Permanent resident of Megnibigha village which comes under your block. I have paternal land in my village near upgraded middle school Megnibigha Plot no. 1075, Khata No. 55. I have the online registration receipt of his land. I am the owner of 25 decimal land but ½ kattha has been illegally occupied by Ramashish Prasad and his five sons. I gave twice the application to C.O. Sir, Masaurhi. Government Ameen came but his sons forcibly prohibited the measurement of land by government Ameen Vinod Shah. Ramashish Prasad and his sons sold all part of the land in 1075 Plot no and Khata no 55. I have the paper of 25 decimal land. He has no paper of land but he kept bricks and soil on my part of land. They threatened us to kill my whole family. Thus, I request you to take swift and stern action after investigating this matter. I have been facing this problem for last five years. I have to gift ½ kattha to the Governor of Bihar to construct Samudayik bhawan.
Yours faithfully
Date - 15/04/2025
Vill. Megnibigha, Bhairwa
Block. Masaurhi, Patna

दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका मूल कारण थाना, प्रखंड और अनुमंडल स्तर के पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी सही ढ़ंग से नहीं निभाना है। यह जमीन का रसीद रामावतार प्रसाद लगातार कटा रहे हैं। यह रैयती जमीन है। इसका खाता सं-55, प्लॉट सं-1075 है। प्राइवेट अमीन से भी दो बार मापी कराया गया है लेकिन जमीन निकलने के बावजूद दबंगई दिखाकर ना ही जमीन मापी स्वच्छतापूर्वक एवं शांतिपूर्वक कराया जाता है और ना ही इसे सुलझाया जाता है। केवल इसे और उलझा कर मामले को गंभीर बनने का इंतजार किया जाता है। पिछले बार समाचार प्रकाशित होने के बाद विभिन्न समाचार पत्रो एवं केवल सच पत्रिका में दबंगों ने पीड़ित के घर लाठी-डंडा लेकर उग्रवादियों को लेकर घंटी भर रात में गाली-गलौज और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिये थे। आखिर यह कैसा सुशासन है कि जब पीड़ित द्वारा थानाध्यक्ष को फोन किया गया, फिर भी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक के कान में जू तक नहीं रेंगा, क्योंकि थानाध्यक्ष मसौढ़ी कहते थे कि तुम डी. एम. हो क्या, जिसके कहने पर हम तुरंत वहाँ आ जाएंगे। आखिर थानाध्यक्ष सी.एम. और डी.एम. के आदेश का ही केवल पालन करेंगे और पीड़ित के परिवार मौत के साये में गुजर बसर करते रहेंगे। रामावतार प्रसाद के बड़े पुत्र का भी 2007 में दिल्ली में संदेहास्पद स्थिति में हत्या हो चुकी है। अब इनके इकलौते पुत्र को भी जान से मारने और पूरे खानदान को समाप्त करने की बार-बार धमकी दी जा रही है। इनके बड़े पुत्र तापीश कुमार दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन संदेहास्पद स्थिति में इनकी हत्या हो चुकी है। आखिर कौन इस मामले को सुलझाएगा? यह प्रशासन के लिए भी चुनौती है। अगर प्रशासन ईमानदारीपूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाए तो निश्चित ही शांतिपूर्वक यह जमीनी विवाद सुलझाया जा सकता है।

रामाशीष प्रसाद के पुत्रों द्वारा अपने हिस्से का जमीन इस प्लॉट में में बेचा जा चुका है, फिर भी पीड़ित के जमीन पर अवैध कब्जा करके बार-बार गाली गलौज अवधेश कुमार और पृथ्वीराज द्वारा किया जाता है एवं केस वापस लेने की धमकी दिया जाता है, अन्यथा पूरे वंश को चेतावनी दिया जाता है। आखिर कैसे हल होगा यह जमीन मापी का विवाद? यह सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती है।●

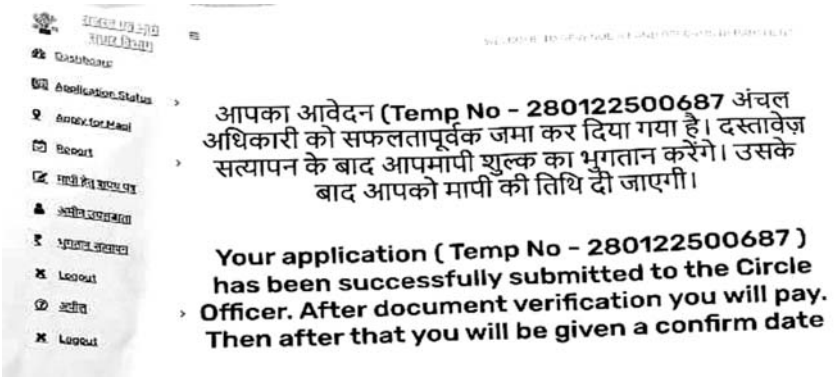

अपराध की योजना बना रहे दो युवक गिरफ्तार

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

मसौढी होली पर्व को लेकर पुलिस अपनी सक्रियता दिखाते हुए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी हुई है। इसी दौरान कादिरगंज पुलिस ने अगरपुर पंचायत सरकार भवन के पास से दो युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिसके पास से एक देसी कट्टा जप्त गई थी। वहीं पूछताछ के दौरान रौनी राज के घर से उसके आंगन से एक देशी राइफल को भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार दो युवकों में रौशन कुमार, उम्र करीब 20 वर्ष पिता स्वव रामबली प्रसाद साव पोखरपर रौनी राज, उम्र करीब 21 वर्ष,पिता अशोक प्रसाद साव अगरपुर दोनों कादिरगंज थाना इस पूरे मामले में सहायक पुलिस अधीक्षक कोमल मीणा ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करते हुए कहा कि यह दोनों युवक को कादिरगंज पुलिस ने पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। दरअसल छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर यह दोनों युवक भाग रहे थे जिसे गिरफ्तार किया गया है और पूरे जांच पड़ताल के दौरान हथियार भी बरामद की गई है। दोनों गिरफ्तार युवक के पास कई आपराधिक इतिहास रहा है। कई मामलों में भी वांछित रहा है। अभी पूरी पूछताछ जाच पड़ताल की जा रही है कि हथियार कहां से लाया है क्या इसकी योजना थी और यह अभी वर्तमान में क्या कर रहा है पूरी बिंदुवार जांच पड़ताल की जा रही है कादिरगंज थानाध्यक्ष रौशन कुमार समेत सभी पुलिसकर्मियों को एएसपी ने पुरस्कृत करने का भी बात कही है।●

जेल, महिला सुरक्षा गृह में पत्रकारों पर प्रतिबंध क्यों?

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने सरकार से तीखा सवाल किया है कि पत्रकारों को जेल और महिला सुरक्षा गृह में प्रवेश पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है? क्या सरकार अब सच्चाई से डरने लगी है? डॉ पटेल ने कहा कि पत्रकार सरकार के मुफ्त सेवक होते हैं। वे जनता और सरकार के बीच सच्चाई का सेतु बनकर काम करते हैं। जब पत्रकारों को ही सच्चाई देखने-समझने से रोका जाएगा तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार ही वह माध्यम हैं जो जेलों के अंदर की खामियां, निर्दोष लोगों के जेल में बंद होने का सच, भ्रष्ट अधिकारियों को मिल रही विशेष सुविधाएं और महिला सुरक्षा गृहों की वास्तविक स्थिति सरकार और जनता के सामने लाते हैं। डॉ पटेल ने जोर देकर कहा कि अगर पत्रकारों को पहले से ही प्रतिबंधित कर दिया जाता, तो शायद देश को मुजफ्फरपुर बालिका सुरक्षा गृह कांड जैसी भयावह सच्चाई कभी पता ही नहीं चलती। उसी मामले ने यह दिखा दिया कि किस प्रकार मासूम बच्चियों का शोषण सत्ता और व्यवस्था के संरक्षण में हो रहा था। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की आंख और कलम ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। यदि उस पर ताला लगा दिया गया तो भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय को छिपाने का रास्ता खुल जाएगा। डॉ पटेल ने जोरदार अंदाज में कहा, "सरकार यह याद रखे, पत्रकार दुश्मन नहीं बल्कि लोकतंत्र के प्रहरी हैं। जेल और महिला सुरक्षा गृह में प्रतिबंध लगाकर सच्चाई को कैद नहीं किया जा सकता। सच्चाई को जितना दबाया जाएगा, उतना ही बड़ा विस्फोट होगा।" उन्होंने सरकार से मांग की कि पत्रकारों को जेल और महिला सुरक्षा गृहों में प्रवेश की स्वतंत्रता दी जाए, ताकि व्यवस्था की खामियां सामने आएं और सुधार हो सके। डॉ पटेल ने अंत में कहा, "जहाँ पत्रकारों की आवाज दबती है, वहाँ लोकतंत्र कमजोर होता है और जहाँ पत्रकार निर्भीक होते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार की जड़ें हिल जाती हैं।" इस मुद्दे पर उन्होंने पूरे बिहार में राजनीतिक और सामाजिक बहस शुरू करने की जरूरत बताई और कहा कि पत्रकारों की स्वतंत्रता पर कोई भी रोक लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है।●

540 खाद जांच में नकली!
किसानों को जहर, मुनाफाखोरों को संरक्षण

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

देश की अन्नदाता किसान आज ऐसी त्रासदी झेल रहा है कि उसकी पीड़ा सुनकर भी व्यवस्था की आत्मा नहीं कांपती। हाल ही में 540 खाद के नमूनों की जांच में नकली खाद का खुलासा होना इस बात का प्रमाण है कि किसानों के साथ कितना बड़ा छल और षड्यंत्र किया जा रहा है। खेतों में उपज बढ़ाने के नाम पर किसानों को नकली खाद परोसी जा रही है, और किसान मजबूरी में उसी जहर को अपनी जमीन में डालने को विवश है। आज किसान की हालत यह हो गई है कि बीज के लिए कर्ज, खाद के लिए कर्ज, पानी के लिए कर्ज, दवा के लिए कर्ज, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज, इलाज के लिए कर्ज और अंत में मृत्यु के बाद कफन के लिए भी कर्ज। यह कैसी व्यवस्था है, जहाँ देश को अन्न देने वाला किसान खुद कर्ज के बोझ से दबा हुआ है? जिन किसानों के पसीने से पूरे देश की थाली भरती है, वही किसान आज अपमान, शोषण और लूट का शिकार है। नकली खाद बेचने वाले मुनाफाखोर खुलेआम बाजार में किसानों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और प्रशासन अक्सर मूकदर्शक बना रहता है। भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ. लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि यदि देश के अन्नदाता को सम्मान नहीं मिला, तो यह केवल किसान का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान होगा। सरकार को केवल योजनाओं की घोषणा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर कठोर कार्रवाई करनी होगी। नकली खाद बनाने और बेचने वालों पर देशद्रोह जैसा कठोर मुकदमा चलाया जाए, ताकि कोई भी किसान के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। डॉ. पटेल ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया कि जिस किसान के श्रम से देश का पेट भरता है, उसे भी सम्मानपूर्वक जीने का अधि कार मिलना चाहिए। सरकार कम से कम किसान परिवार को एक चपरासी के बराबर 30 से 35 हजार रुपये मासिक सम्मान राशि सुनिश्चित करे, ताकि किसान परिवार आधा पेट ही सही, लेकिन सम्मान के साथ जीवित रह सके। ाज देश का किसान भीख नहीं मांग रहा, अपने पसीने का सम्मान मांग रहा है। अगर अन्नदाता ही टूट गया तो देश की समृद्धि का सपना भी टूट जाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि किसान की दुर्दशा पर भाषण नहीं, निर्णायक और कठोर कार्रवाई हो।●

मुद्रा योजना में पारदर्शिता लाओ, नहीं तो जनता जवाब मांगेगी

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ. लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख रुपये तक के ऋण की महत्वपूर्ण योजना लागू की थी। इस योजना का उद्देश्य था कि देश का बेरोजगार युवा स्वयं रोजगार करे और दूसरों को भी रोजगार देने वाला बने। डॉ. पटेल ने कहा कि यह योजना गरीब, बेरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी पहल थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कई जगहों से गंभीर शिकायतें मिल रही हैं कि बैंक अधिकारियों की मनमानी, पक्षपात और सिफारिशी संस्कृति के कारण वास्तविक जरूरतमंद युवाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बैंक शाखाओं में लोन वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और आम जनता को यहाँ तक पता नहीं चल पाता कि इस योजना का लाभ किन लोगों को दिया गया है। इससे युवाओं में निराशा और आक्रोश बढ़ रहा है। डॉ. पटेल ने मांग की कि सभी सरकारी और निजी बैंक अपनी-अपनी शाखाओं में इस योजना के अंतर्गत दिए गए लोन की पूरी सूची सार्वजनिक रूप से नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें, ताकि जनता यह देख सके कि योजना का लाभ वास्तव में किसे मिला है। उन्होंने कहा कि यदि बैंक और संबंधित अधिकारी पारदर्शिता नहीं लाते हैं तो आने वाले समय में जनता अपने जनप्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछेगी कि केंद्र सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजना का लाभ आम गरीब और बेरोजगार युवाओं तक क्यों नहीं पहुंच पाया। डॉ. पटेल ने कहा कि योजनाएं तभी सफल होती हैं जब उनका लाभ ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सही लोगों तक पहुंचे। डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री बिहार सरकार, भाजपा के अपने अपने क्षेत्र के सांसद ,विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रखण्ड अध्यक्ष जनता के सहयोग से सभी बैंक प्रबंधक को लाभार्थियों का सूची बैंक के गेंट पर वोर्ड में टगंवा दें।●